Tuesday, 11 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

Preservation 6-7-92
Promulgated On 9.1.84
Parliament Library

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 34 मंगलवार, 11 जुलाई, 1967/20 आषाढ, 1889 (शक)

No. 34–Tuesday, July 11, 1967/Asadha 20, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1051 बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनाज की जमाखोरी	Hoarding of Foodgrains in Border Areas of Bihar ...	4879-4880
1052 एयर इंडिया, बम्बई	Air India, Bombay	4881–4884
1054 अखिल भारतीय सड़क तथा देहाती परिवहन के विकास कार्यक्रम	All India Roads and Rural Transport Development Programme ..	4884–4889
1055 स्वेज नहर को पुन: खोलना	Re–Opening of Suez Canal	4889–4892
1056 पिता की सम्पत्ति में लड़की का हिस्सा	Daughter's Share in Father's Property ...	4892–4896
1057 पश्चिमी एशियाई संकट के बाद राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन	Allotment of Foodgrains to States following the West Asian Crisis	4896–4899
अल्प-सूचना प्रश्न/ S. N. Q. Nos.		
27 दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant –	4899-4903
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या/S.Q. Nos.		
1053 राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई	Foodgrains Supply to States	4903–4904

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd

1058	आसाम में पटसन का उत्पादन	Production of Jute in Assam ...	4904
1059	नये हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of New Aerodromes	4905
1060	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का वितरण	Distribution of Foodgrains in drought-hit areas	4905–4906
1061	गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौवहन	Traffic in Ganga and Brahmaputra ...	4906
1062	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग	Sugar Industry in U. P.	4906–4907
1063	मद्रास राज्य के लिये उर्वरकों का नियतन	Allocation of Fertilizers to Madras	4907
1064	स्वेज नहर में से होकर जाने वाले जहाजों का मार्ग परिवर्तन	Re-Routing of Suez Bound Ships ...	4907–4908
1065	आस्ट्रेलिया से गेहूँ की खरीद	Purchase of Wheat from Australia ..	4908–4909
1066	महाराष्ट्र में सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agriculture Programme in Maharashtra	4909
1067	ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में भूख से मृत्यु	Starvation Death in Gwalior (M.P.) ..	4909–4910
1068	एयर इंडिया को विमान चालकों की हड़ताल के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange to Air India by Strike of Pilots	4910
1069	खेती का आधुनिकीकरण	Modernisation of Agriculture	4911
1070	अमरीका से गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat from U. S. A. ...	4911
1071	जम्मू और काश्मीर में जोरदार खाद्य कार्यक्रम	Crash food programme in Jammu & Kashmir	4911–4912
1072	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation ..	4912

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1073	सूखाग्रस्त राज्यों में राशन व्यवस्था	Ration System in Drought hit States	4912
1074	किसानों द्वारा देय बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बारे में सूखा-ग्रस्त राज्यों को निर्देश	Directives to Drought affected States to write-off loans outstanding against Farmers.	4913
1075	अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये फालतू गेहूं देने की पंजाब सरकार की पेशकश	Punjab Government,s offer of surplus Wheat's for Scarcity Areas	4913-4914
1076	उत्तर प्रदेश के लिये खाद्यान्नों का मासिक कोटा	Monthly Quota of Foodgrains for U. P. ...	4914
1077	अनाज ले जा रहे जहाजों को मोड़ना	Diversion of Food carrying Ships ..	4915
1078	कृत्रिम वर्षा करना	Artificial Rain Making	4915
1079	शीघ्र उपज देने वाले गेहूं के बीज की बढ़िया किस्म	Improved Variety of quick-yielding Wheat Seeds ..	4916
1080	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष	International Tourist Year	4916-4917
अतारांकित प्रश्न संख्या			
5147	मध्य प्रदेश के लिये खाद्यान्न का नियतन	Allotment of Foodgrains to M. P.	4917-4918
5148	मध्य प्रदेश में बरमें (रिंग) तथा छिद्रण उपकरण	Rigs and Drilling Equipment in M. P. ...	4918-4919
5149	गोआ, दमन और दीव में छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works in Goa Daman and Diu	4919
5150	भारतीय केन्द्रीय रुई समिति	Indian Central Cotton Committee	4919-4920
5151	अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों का गत चुनावों में भाग लेना	Contest in the Last General Elections by Scheduted Caste Candidates	4920

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS -Contd.

5152	गुजरात में कृषि सम्बन्धी नया प्रस्ताव	New Agricultural Proposal in Gujarat	4920
5153	गुजरात में कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in Gujarat ..	4920-4921
5154	गुजरात में कृषि के विकास के लिये सहायता	Assistance for Agricultural Development in Gujarat	4921-4922
5155	गुजरात में चने का अभाव	Scarcity of Gram in Gujarat – ...	4922
5156	सरकार द्वारा दी गई राजसहायता की राशि	Subsidy Amount borne by Government ...	4923
5157	व्योम बालाए (एयर होस्टेस)	Air Hostesses ..	4923-4924
5158	मध्य प्रदेश को अनाज भेजने में कठिनाइयां	Difficulties in Transport of Foodgrains to M. P.	4924
5159	असैनिक उड्डयन का विकास	Promotion of Civil Aviation	4924-4925
5160	खम्भात पत्तन	Cambay Port	4925
5161	खम्भात पत्तन	Cambay Port ...	4926
5162	उत्तरी गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University for North Gujarat ...	4926
5163	गोआ में सहकारी समितिया	Cooperative Societies in Goa	4926-4927
5164	गोआ में 'खार' भूमि में खेती	Cultivation of 'Khar' Lands in Goa	4927
5165	गोआ में 'खजान' भूमि में खेती	Cultivation of 'Khazan' Lands in Goa	4928
5166	मध्य प्रदेश के लिये अल्प-कालीन तथा मध्यकालीन कृषि ऋण	Short and Mid-term Agricultural Loans for M. P. ...	4928
5167	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	4928-4929
5168	भुवनेश्वर हवाई अड्डा	Bhubaneswar Airfield	4929

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5169	कलकत्ता पत्तन के पलटा वाटर वर्क्स में मिट्टी निकालने का कार्य	Desilting Operation of Palta Water Works, Calcutta Port	492)
5170	देश की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता	Food Requirements of the country	4930
5171	दिल्ली में पशुओं के लिये चने की सप्लाई	Supply of Gram for cattle in Delhi	4931
5172	दिल्ली में सूजी और मैदे का वितरण	Distribution of Suji and Maida in Delhi	4931–4932
5173	हरयाना को गेहू की सप्लाई	Supply of Wheat to Haryana ...	4932
5174	गंडक नदी पर पुल	Bridge on Gandak River	4932
5175	अधिनियम तथा विधियां	Acts and Laws	4932–4933
5176	बम्बई के नाविक	Bombay Saillors	4933–4934
5177	द्वि–विवाह निरोध कानून	Anti Bigamy Law	4934
5178	पी. एल. 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains Under PL 480 ...	4934–4935
5179	गोदामों की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण फलों की क्षति	Wastage of Fruits due to Faulty Storage ...	4935–4936
5180	मोटल	Motels ...	4936
5181	चावल की अधिक उपज वाली नई किस्म	New High Yielding Variety of Rice	4936–4937
5182	चीनी का निर्यात	Export of Sugar ...	4937–4938
5183	उत्तर प्रदेश में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Pant Nagar Agricultural University in U. P.	4938
5184	कीटनाशक औषधियां	Insecticides	4938–4939
5185	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की विमान सेवाए	I. A. C. Services	4939

5186	सहकारी चीनी मिल, बटाला	Co-operative Sugar Mills, Batala	4939-4940
5187	खाद्य तथा उर्वरकों के लिये राजसहायता	Food and Fertilizer Subsidies	4940-4941
5188	मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in M. P.	4941
5189	राजस्थान से चने का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Grams from Rajasthan ..	4941
5190	हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of Airports	4941-4942
5191	अधिक अनाज उपजाओ अभियान के लिये मध्य प्रदेश को अनुदान	Grant to M. P. for Grow More Food Campaign ...	4942
5192	त्रिवेन्द्रम और कोलम्बो के बीच विमान सेवाएं	Air Services between Trivandrum and Colombo	4942-4943
5193	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा	Trivandrum Airport	4943
5194	कोचीन हवाई अड्डा	Cochin Airport	4943-4944
5195	पंचायतों द्वारा राजस्व की वसूली	Revenue Collection by Panchayats	4944
5196	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऋण	Loans by R. B. I. to Central Cooperative Banks	4944-4945
5197	विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन	Publications of Law Journals	4945
5198	भारत के लिये खाद्य प्रतिष्ठान, नीदरलैण्ड (फूड फार इंडिया फाउन्डेशन)	Food for India Foundation, Netherlands ...	4945-4946
5199	सांची में हवाई अड्डा	Airport at Sanchi	4946

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5200	ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण	Reserve Bank Survey on Rural Indebtedness	4946–4947
5201	बाडमेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Barmer Region	4947
5202	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Staff in Food and Agriculture Ministry	4947
5203	भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक	Managing Director of Food Corporation of India	4948
5204	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय	Headquarters of Food Corporation of India in Delhi ..	4948–4949
5205	1967–68 में उर्वरक की आवश्यकता	Requirement of Fertilisers during 1967-68 – ..	4949
5206	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थान	Posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in F. &. A. Ministry ..	4949
5207	गुड़गांव के निकट दिल्ली पुलिस द्वारा चावल के ट्रक का पकड़ा जाना	Seizure of a Tmck Leades with rice by Delhi Police near Gurgaon ...	4950
5208	बिहार में पम्पिंग सैटों की आवश्यकता	Requirement of Pumping Sets in Bihar ...	4950–4951
5209	भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिवहन ठेका	Transport contract by F. C. I. ...	4951
5210	देश में मुर्गीपालन केन्द्र	Poultry Farms in the country ..	4951
5211	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी व्यक्तियों के ठेके	F. C. I. contracts to Private Persons ..	4951–4952

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अता. प्र. संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ
5212	मध्य अन्दमान द्वीपसमूह में ग्राम पंचायतों के चुनाव	Gram Panchayat Elections in Middle Andaman Islands ..	4952
5213	सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation ..	4952-4953
5214	भारतीय खाद्य निगम के गोदाम (भोपाल) से चोरी	Theft from F. C. I. Godown, Bhopal	4953
5215	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	4953–4954
5216	दिल्ली दुग्ध योजना में समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance in Delhi Milk Scheme ...	4954
5217	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का स्टाक	Tobacco Stock in Andhra Pradesh ..	4954–4955
5218	मध्य प्रदेश में पंचायतों और जिला परिषदों की स्थापना	Establishment of Panchayats and Zila Parishads in M. P. ...	4955
5219	दिल्ली में अनाज की जमाखोरी तथा तस्कर व्यापार को रोकने के लिये छापे	Raids in Delhi to check hoarding and smuggling of Foodgrains ...	4955–4956
5220	राजस्थान में आयातित ज्वार का प्रयोग	Use of Imported Jowar in Rajasthan	4956
5221	राजस्थान में सरकारी बीज फार्म	State Seed Farms in Rajasthan ...	4956
5222	बहुप्रयोजनीय किसान सहकारी समिति, दिल्ली	Co-operative Peasants Multi-purpose Society, Delhi ..	4956–4957
5223	इटली का उर्वरक देने का प्रस्ताव	Italian Offer of Fertilizers	4957
5224	भारत और काहिरा के बीच विमान सेवा	India-Cairo Air Services	4957–4958
5225	बिना जोती भूमि का सर्वेक्षण	Survey of Uncultivated Land	4958

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5226	केरल में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Kerala ...	4958–4959
5227	कृषि पुनर्वित्त निगम	Agricultural Re-finance Corporation ...	4959
5228	गंगा–ब्रह्मपुत्र जल परि-वहन बोर्ड के कर्मचारी	Employees of Ganga–Brahmaputra Water Transport Board	4959–4960
5229	राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन	Foodgrains Production in States	4960–4961
5231	बम्बई – इंदौर – भोपाल विमान सेवा	Bombay–Indore–Bhopal Air Service ..	4961
5232	आयातित स्प्रे मशीन	Imported Spray Machines	4961
5233	चांदीपुर का विकास	Development of Chandipur	4962
5234	दक्षिण अन्दमान में भूमि-हीन कृषक परिवार	Landless Agricultural Families in South Andaman	4962
5235	अन्दमान द्वीपसमूह में हल चलाने वाले पशुओं से विहीन कृषक	Cultivators without Plough animals in the Andaman Islands	4963
5236	मंगलुतान – मायाशहर सड़क	Manglutan-Mayashahr Road – ...	4963–4964
5237	अन्दमान द्वीप में पुल और पुलिया	Bridges and Culverts in Andamans	4964
5238	अन्दमान द्वीप के वन विभाग में इमारती लकड़ी की कमी	Shortage of Timber in Andaman Forest Department	4964
5239	अन्दमान वन विभाग	Andaman Forest Department	4965
5240	केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश के लिये धन का नियतन	Allotment from Central Road Fund to U. P.	4965–4966
5241	सहकारी चीनी मिलें	Cooperative Sugar Mills	4966
5242	पब्लिकेशन डिवीजन सह-कारी ऋण तथा बचत समिति	Publication Division Co-operative Credit and Thrift Society – ...	4966

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5243	अन्य राज्यों के आवंटन के लिये पंजाब में गेहूं का समाहार	Wheat Procurement in Punjab for Allocation to other States ... —	4967
5244	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आरा मिलें	Saw Mills in Andaman and Nicobar Islands .. —	4967
5245	उदयपुर का हवाई अड्डा	Udaipur Aerodrome	4967
5246	गुड़ के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Gur ... —	4968
5247	राजस्थान में पर्यटन	Tourism in Rajasthan ... —	4968
5248	महाराष्ट्र को अनाज का नियतन तथा उसकी सप्लाई	Allotment and Supply of Foodgrains to Maharashtra	4968–4969
5249	पंजाब तथा हरियाना द्वारा बिहार को अनाज का बेचा जाना	Sale of Foodgrains by Punjab and Haryana to Bihar	4969
5250	अनाज की उपज में वृद्धि	Increase in Food Output	4969-4970
5251	पंजाब में अधिक उपज वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम	High Yielding Crop Programme in Punjab — —	4970–4971
5252	चीनी के विशेष कोटे	Special Sugar Quotas	4971
5253	मध्य प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का विकास	Development of Places of Tourist interest in M. P. — ...	4972
5254	भोपाल का हवाई अड्डा	Bhopal Airport	4972
5255	संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से अकाल पीड़ितों के लिये सहायता	U. N. I. C. E. F. Contribution in Famine Relief	4972–4974
5256	भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा	Indian Mercantile Fleet .. —	4974-4975

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5257 चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की अनुमानित खपत	Estimated Consumption of Fertilizers during Fourth Plan	.. ..	4975–4976
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	... ...	4976
पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों की वापसी	Repatriation of Indian Nationals detained in Pakistan	... ...	4976
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. ...	4976
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	... ...	4976
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	.. ...	4978
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	... ...	4978–4979
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	... ..	
अनुदानों की मांगें–जारी	Demands for Grants, 1967-68–Contd.	..	4979
संचार विभाग–जारी	Department of Communications–Contd.	..	4979
श्री सरजू पाण्डये	Shri Sarjoo Pandey	... ..	4979
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. ...	4980
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	.. ...	4980
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	... ...	4981
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	... ...	4981
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	.. ...	4982
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	.. ...	4983
श्री अब्राहम	Shri Abraham	... ...	4984
श्री वि. ना. शास्त्री	Shri B. N. Shastri	... ...	4985
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	... ..	4986
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	... ...	4987
श्री बे. कृ. दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	... ..	4987
श्री सोनावने	Shri Sonavane	... ...	4988

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	4988
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	4989
श्री अ. सि. सहगल	Shri A. S. Saigal	4990
डा. कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	4990
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	4991
श्री धीरेन्द्र नाथ देव	Shri D. N. Deb	4991
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	4992
खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	4996
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	4996
श्री तु. राम	Shri T. Ram	4998
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Dutt Sharma	4999
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh .. —	5000
श्री रामभद्र नायडू	Shri Ramabadra Naidu	5020

लोक-सभा वाद-विवाद

का अनूदित संस्करण

दिनांक 11 जुलाई, 1967 । 20 आषाढ़ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
4958	प्रश्न संख्या 5225 के उत्तर के अंग्रेजी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी रुपान्तर पढ़िये :

'खाद्य , कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाने तथा खेती के अन्तर्गत लाने के लिये देश में कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि का पहले ही विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है । वास्तव में भारत सरकार ने 1959 में बेकार पड़ी भूमि सर्वेक्षण समिति नियुक्त की थी । समिति ने बेकार पड़ी भूमि के बड़े बड़े खण्डों अर्थात् 250 एकड़ तथा अधिक के खण्डों तक अपना सर्वेक्षण सीमित रखा और 13 राज्यों में 12,23 लाख एकड़ भूमि के सुधार की सिफारिश की । उसके अतिरिक्त छोटे छोटे खण्डों में पर्याप्त भूमि बेकार पड़ी थी अत: सरकार ने बेकार पड़ी भूमि सर्वेक्षण समिति द्वारा किये गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 250 एकड़ से कम भूमि के खण्डों के सर्वेक्षण के लिए दूसरी समिति बनाई है । यह सर्वेक्षण 220 जिलों में पूरा हो गया है और लगभग 105 जिलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत लगभग 40 लाख एकड़ भूमि सुधार के लिए उचित पाई गई । सर्वेक्षण कार्य के चौथी पंचवर्षीय योजना में समाप्त होने की सम्भावना है । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन हेतु 62.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । योजना के लिए प्रति जिला 50,000 रुपये के हिसाब से केन्द्रीय राज सहायता उपलब्ध होगी ।

(ख) 1967-68 में ऐसी भूमि की उपयुक्तता के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 11 जुलाई, 1967/20 आषाढ़, 1889 (शक)
Tuesday, 11 July, 1967/Asadha 20, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hoarding of Foodgrains in Border Areas of Bihar

\+
***1051. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the deal rs living in the border of areas Bihar adjacent to Nepal border have hoarded foodgrains at different places in Nepal after making purchases from here;

(b) if so, whether the Central Intelligence Bureau have submitted any raport in this connection; and

(c) the steps taken by Government in the matter ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Bibhuti Mishra : This Agency of our Government is very inefficient. I know thirty lakh maunds of paddy is purchased on the Border of Bihar or atleast in my district of Champaran of Bihar.....

द्वा० ना० तिवारी : आप जानकारी मांग नहीं रहे हैं, आप तो जानकारी दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य की बात है कि सभा में ऐसा ही हो रहा है ।

Shri Bibhuil Mishra : I may kindly be given patient hearing. The dealers of rice and paddy from whom our Government wants to purchase rice and paddy have godowns in Nepal and if Nepal Government wants to purchase rice and paddy from them they have godowns in India. In this way thirty lakh maunds of paddy are purchased from my district.......

Mr. Speaker : The debate on food is going to take place to-day. You can make a mention of all this during that discussion.

Shri Bhibhuti Mishar : Sir, you give assurances to all but how many get a chance in that debate ? so, I would like to know whether Government are proposing to make an enguiry in this matter ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : हमने इस मामले को बिहार सरकार को सौंपा था । बिहार सरकार ने हमें लिखा है कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । तब हमने उसे गृह-कार्य मन्त्रालय को भेजा । वह भी कहते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Bibhuti Mishra : Under these circumstanees we feel pity on our Government. Have you even enquired this thing from the Central Intelligence Department at Raxaul ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : बिहार से नेपाल को चोरी छिपे अनाज ले जाने को रोकने के लिये गलगलिया, जोगबनी और जयनगर में पड़ताल चौकियां हैं और रक्सौल में एक चलता-फिरता दल काम कर रहा है । जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं हमने इस मामले को बिहार सरकार को भेजा था और उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether Government are aware of the fact that there is one man who has a rice mill in Nepal as well as in the Indian Territory and the same fellow stores paddy both sides and exchanges it according ta requirements. If it is so, whather Government propose to take any action in this regard ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशिष्ट जानकारी दें तो मैं उसे बिहार सरकार एवं गृह-कार्य मन्त्रालय को भेज दूंगा । हम उन दोनों को माननीय सदस्य के इस प्रश्न से भी अवगत करा देंगे ।

Shri Brij Bhushan Lal : Whether Government are aware that lot of foodgrains are being smuggled to Nepal from that part of Uttar pradesh which is adjacent to Nepal, if so, what steps have been taken to check it and whether there had been nagotiations with Nepal Government in this connection and if not the reasons therefor ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न बिहार और नेपाल सीमा के बारे में है । दूसरा प्रश्न पूछने के लिये पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ।

एयर इण्डिया बम्बई

+

*1052. श्री स० मो० बनर्जी : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एयर इंडिया द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा अन्य विधियों के उल्लंघनों के मामलों की जांच सरकार ने पूरी कर ली है;

(ख) विभिन्न सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्या की गई है;

(ग) क्या इस मामले में एयर इंडिया अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग तथा अधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई कानूनी कार्रवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन कानूनी कार्रवाइयों की वर्तमान स्थित क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप:मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) (ग)और(घ) 'पी' फार्म क्लीयरेंसके बगैर ही टिकट जारी करनेकी अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय (प्रवर्तक निदेशालय) द्वारा एयर इंडिया तथा कारपोरेशन के 8 अफसरों के विरुद्ध प्रारम्भ की गई निर्णयार्थ अदालती कार्यवाही (एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स) अभी चल रही हैं ।

(घ) एयर इण्डिया ने वैभाविक कार्यवाही की, जिसके परिणामस्वरूप एक अफसर को सेवा से निकाल दिया गया । तथा जब तक प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा उन्हीं आरोपों को लेकर चलायी गयी निर्णयार्थ अदालती कार्यवाही (एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स) पूरी नहीं हो जाती तब तक तीन अन्य अफसरों के विरुद्ध मामले (केस) अभी अनिर्णित दशा में पड़े हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उप-मन्त्री ने बताया है कि एक अधिकारी को विभाग के द्वारा सेवा से निकाल दिया गया है तथा तीन अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामलों पर अभी निर्णय नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन तीनों अधिकारियों को, जिनके मामले अभी अनिर्णित पड़े हैं, मुअत्तिल कर दिया गया है अथवा अब भी सेवा में हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : इनमें से एक अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है । एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है । तथा अन्य अधिकारी अभी सेवा में ही हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : त्यागपत्र देने से वह अधिकारी दोषयुक्त हो जायेगा अथवा उस पर आरोप लगाये गये हैं और त्यागपत्र के बाद उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी ?

डा० कर्णसिंह : त्यागपत्र देने से वह दोषमुक्त नहीं हो जायेगा । आरोप लगाये गये हैं और उसको दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

Shri George Fernands : May I know whether the officers againsst whom cases are being pursued have also seaid that their bosses also had a hand in that ?

Dr. Karan Singh : I have no such infomation;

श्री हेम बरुग्रा : पी० फार्म के बगैर ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति देने के लिये एयर इंडिया के कुछ अधिकारियों के प्रश्न को लगभग एक वर्ष पहले जब सभा में उठाया गया था तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके आचरण की जांच की जायेगी तथा उस पर कार्यवाही की जायेगी ।.अब भी वही उत्तर दिया जा रहा है कि जांच की जा रही है । क्या मैं जान सकता हूँ कि जांच को पूरा करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सरकार को कितना समय लग जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक कार्यवाही कर रहा है । वह बम्बई के लिये प्रस्थान कर चुका है तथा एक सप्ताह में सुनवाई शुरू होने वाली है । हम भी चिन्तित हैं कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दन्ड दिया जायं ।

श्री हेम बरुग्रा : आप तो एक वर्ष से चिन्तित हैं ।

डा० कर्ण सिंह : हम अब भी चिन्तित हैं कि उन्हें दन्ड दिया जाये ।

Dr. Ram Manober Lohaia : Sir, an oplasne of Air India which had gone to Bironi while it was coming back to India via Moscow did not carry any pessenger as special dignitaries were travelling in that plane and many seats remained vacant. So I would like to know from the hon. Minister as to how many seats remained vacant and how much loss of foreign exchange was sustained as a result thereof ?

Dr. Karan Singh : I subm t that this question does not arise out of it. If it is raised at some other time I shall answer it,

Dr. Manoher Lohia : This question relates to foreign exchange and a loss of foreign exchange has been sustained in an aeroplane. Hence this question arises out of it. At the most the hon. Minister could say that answer to this question wou'd be begiven later on,

Dr. Karan Singh : This question does not relate to foreign exchange. It is a question ragarding 'P' form. If a question is asked in this connection only then I will answer that.

ग्रध्यक्ष महोदय : इसके अलावा प्रति दिन कितने ही विमान जाते हैं और मेरे विचार से मन्त्री महोदय यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक विमान में कितने स्थान खाली होते हैं ।

Dr. Ram Manoher Lohia : He can enquire. After the he can give an answer.

ग्रध्यक्ष महोदय : इसलिये मैंने कहा है कि आप इसके बारे में एक प्रथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

Dr. Ram Manober Lohia : Sir, you know that quertions are askd now with great difficulty you kindly accept this question now and may ask the hon Minister to give its answer even after ten days.

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक प्रश्न पर एक पृथक प्रश्न पूछा जाये और मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहा जाये तो ऐसा करना कठिन हो जायेगा ।

Shri Rabi Ray : This matter of Air India is the root cause of corruption. May I know from the hon. Minister where it is a fact that one officer Mr. Bakshi and his wife both had gone abroad without fulfilling 'P' form conditions. The matter was enquired into and after the enquiry was over the commissioner Shri S K. Kulka had written.

आप नियम के नियमों के अन्तर्गत तथा विदेशी मुद्रा के सरकारी नियमों का गम्भीरता से उल्लंघन करने के कारण दुर्व्यवहार करने के दोषी हैं । दिसम्बर 1961 में हुई बैठक में आपको बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके अपराध पर कड़ा रवैया नहीं अपनाया है और हमने आपको एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

Similar thing has been written by one commercial manager. So I would like to suggest to the hon. Minister that some Parliamentary Committee should go and conduct an enquiry as many corrupt practices are going on in Air India, Since he is a new Minister I would like him to take some action in this connection.

Dr. Karan Singh : I would like to inform the hon. Member that the services of Shri Bakshi, whose name has been mentioned by him, have been dispensed with. He has been relieved from service.

Shri Rabi Ray : Shri S. K. Koka had written a letter about him- that he had taken a lenient view about him In case the hon. Minister desires I could give that letter.

Dr. Karan Singh : When was it written ?

Shri Rabi Ray : On 20th April, 1961.

Dr. Karan Singh : That is a matter of past.

Shri Rabi Ray : Whether such officers are there now and whether Koka Sahib is there or not and whether he had written this letter or not ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Does the past dishonesty becomes honesty ?

Shri Ram Sewak Yadav : Whether it is a fact that the ex-Minister, Shri A. K. Sen has gone abroad without 'P' form, if so, the reasons therefor ?

Dr. Karan Singh : I have no such information with me.

श्री स० कुण्डू : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में जांच की है । परन्तु माननीय उप-मन्त्री ने 'पी०' फार्म ने उल्लंधन का एक उदाहरण दिया है । एक गिरोह यात्रा एजटों, नाविकों तथा कुछ तार पत्र अधिकारियों के सहयोग से काम कर रहा है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है । क्या उप-मन्त्री ने ऐसे सब उल्लंघनों की जांच की है ? यदि नहीं, तो क्या वह अब ऐसा करने का वचन देंगे ?

डा० कर्णसिंह : जांच के दौरान यह बात हमारे ध्यान में लाई गई कि जिस गिरोह का उल्लेख किया गया है, दुर्भाग्यवश वह वहां था तथा अग्रेतर जांच पर 317 संदिग्ध मामलों की जांच की गई थी। अब तक 55 मामलों का पता लगाया गया है... ...

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि एक सूची सभा-पटल पर रखी गई थी।

श्री स० कुण्डू : उत्तर स्पष्ट नहीं है।

डा० कर्णसिंह : उस सम्बन्ध में आठ अधिकारियों को दोसी ठहराया गया है तथा प्रवर्त्तन निदेशालय ने जो वित्त मण्त्रालय का अंग है, उन अधिकारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही आरम्भ कर दी है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के कोई मामले हमारे ध्यान में आयेंगे तो अपराधी पाये गये लोगों के विरुद्ध हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। परन्तु मैं यह नहीं समझता कि यह कहना सही है कि सारा एयर इंडिया भ्रष्टाचार का केन्द्र है। निस्संदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो उसे समाप्त करने के लिये सदा चिन्तित रहता हूं।

अखिल भारतीय सड़क तथा देहाती परिवहन के खिलाफ कार्यक्रम

+

*1054. **श्री स० चं० सामंत** : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री वेणीशंकर शर्मा** :
श्री अ० क० किस्कु : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री श० ना० माइती : **श्री मं० रं० कृष्ण** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और देहाती परिवहन के विकास का अखिल भारतीय कार्यक्रम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) - (क) जी नहीं। ग्रामीण सड़कों के विकास तथा ग्रामीण परिवहन के लिये प्रधानतः सम्बन्धित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि मन्त्रालय द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने सारे भारत की सड़कों के विकास-कार्य पर 740 रुपये खर्च करने की सिफारिश की थी। यदि हां, तो क्या केन्द्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः 370, 370 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास इस ससय ठीक जानकारी नहीं है। परन्तु इस समय स्थिति यह है कि अभी सभी प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये है। जब तक योजना नियतन अन्तिम रूप से तैयार नही किये जाते हैं, सही सही कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या पहले की नागपुर योजना अब भी चल रही है। यदि नहीं, तो किस प्रकार की योजना बनाई गई है तथा कितना धन कितने समय के लिये आवश्यक होगा ?

श्री भक्त दर्शन : नागपुर प्लान के स्थान पर अब विभिन्न राज्यों के मुख्य इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई एक दूसरी 20 वर्षीय योजना बनाई गई है। अब वही चल रही है। योजनावार तथा वर्ष वार नियतन किया जाता है।

श्री स० चं० सामन्त : कितना कितना ?

श्री भक्त दर्शन : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

Shri B. S. Sharma : The hon. Minister had just now said that rural roads and rural transport is a State subject and he very well knows that the financial position of State is not sound. May I therefore know whether Government is preparing a scheme to help those States which start rural roads and rural transport work ?

Shri Bhakt Darshan : Yes, Sir. The Planning Commission has suggested that 20 p, c. amount arranged by State Governments for roads should be earmarked for rural roads and in that 20 percent amount 40 percent aid should be given by the Centre.

श्री मं० र० कृष्ण : ग्रामीण सड़कों को शामिल करने के लिये राज्य सरकारों के योजना सम्बन्धी आय-व्ययकों में से 20 प्रतिशत की व्यवस्था करने के बारे में क्या मन्त्री महोदय और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच पहले कोई बातचीत हो चुकी है और यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने योजना आयोग के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : अभी नहीं।

श्री कंडप्पन : मेरे विचार से ग्रामीण सड़कों के साथ साथ यह प्रश्न भारत की सारी सड़कों से सम्बन्धित हो जाता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश मद्रास तथा कुछ अन्य पूर्वी राज्यों को मिलाने वाली सड़कों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है जिसके लिये सरकार बहुत समय से वचनबद्ध है ?

श्री भक्त दर्शन : पूर्वी तट सड़क का अपना महत्व है परन्तु यह ग्रामीण सड़क नहीं है।

श्री कंडप्पन : परन्तु यह उपेक्षित क्षेत्रों को मिलायेगी।

श्री भक्त दर्शन : यदि माननीय सदस्य इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछ तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री चिन्तमणि पाणिग्रही : माननीय मन्त्री ने अभी चौथी योजना का उल्लेख किया था जिसमें 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा वह किस चौथी योजना का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई योजना सभा में नहीं आई है और हमें उस योजना की रूपरेखा का भी पता नहीं है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे सहयोगी ने यह बताया था कि योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें सड़कों के लिये जितने धन की व्यवस्था करें उसका 20 प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़कों के लिये निश्चित किया जाये । यदि वे ऐसी करती हैं तो उसने यह सुझाव दिया है कि इस 20 प्रतिशत का 40 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether Government have received such complaints that often such a thing happens in States that the district to which the Ministers of P.W.D. belong gets more wells and roads and the rest of the States remains neglected If it is so, whether Government will ensure that the whole State gets equal treatment or their Plans are brought and finalised here ?

Shri Bhakt Darshan : Government cannot interfere in this case. But the hon. Member can exert his influence and achieve success.

Shri Prakash Vir Shastri : We have not been given such an authority. You are the Minister.

Shri Prem Chand Verma : Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh are Union Territories. How much amount is being given by Government to each Union Territory for roads out of the Central Fund.

Shri Bhakt Darshan : I want notice for that.

Shri Shiv Charan Lal : May I know from the hon. Minister how many roads are likely to be constructed during the Fourth Plan and whether the amount realised from rural areas is spent on roads of rural areas or on the development of cities ? I support Shri Prakash Vir Shastri's contention that the Public Works Minister Uttar Pradesh, Shri Rawat, has got roads constructed in his own area and the whole district of Agra has been neglected.

Shri Bhakt Darshan : I respect the feelings of the hon. Member. At present all weather roads exist only in one third villages out of about 5 lakh villages in India. Much work is yet to be done in this field and if all the State Governments undertake this work together we can achieve success in few years.

Shri Sheo Narain : Ram Tila Road between Ayodhya and Bihar via Gorakhpur is a historical road and I would like that Government should help in its construction.

Shri Bhakt Darshan : The hon. Member may give in writting and we will forward it to the State Government.

श्री नायनार : चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार आरम्भ करने से भी पहले से ही मंगलोर और मद्रास के बीच वर्तमान मुख्य सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता है । क्या

इस मुख्य सड़क की तथा कन्नानूर जिले में बेलियापट्टम स्थित एकमात्र रेल-रोड पुल की मरम्मत की अथवा इस कार्य के लिये केरल सरकार को सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नायनार : यह प्रश्न मंगलौर और मद्रास के बीच मुख्य पश्चिमी घाट सड़क की मरम्मत से सम्बन्धित है।

Shri Maharaj Singh Bharti : A scheme in respect of rural roads is already under implementation, of which one third expenditure would be borne by the Central Government one third by the State Government and remaining one third would be borne by the mill owners and agiiculturists on fifty-fifty basis. Neither the Central Government, nor the State Government and nor the mill owners have paid the amount according to the amount paid by the agriculturists. May I know whether this scheme has been included in the plan for road construction and if so how much amount has so far been given by the Centre ?

Shri Bhakt Darshan : Maintenance of rural road is the mainthing. Lakhs miles long roads constructed in the past, with the help of Shramdan have totally become unserviceable. Therefore the Ministry has decided to appoint an expert committee for this purpose. This Committee will submit a report to the Government as to how these roads will be custructed and maintained. States Government will also be consulted in this matter and I hope after receiving the report the work will be executed in a better way.

Shri Bibhuti Mishra : The Central Government wrote to the Bihar Government and the Uttar Pradesh Government that one third of cost of rural road contruction will be given by the Centre, one third by the State Government, and rest one third will be borne by mill owners and agriculturists on fifty-fifty basis. The agriculcurists have collected their share in our state but the Government have not paid their share and roads have not been constructed. I would like a clarification from the hon. Minister in this regard.

अध्यक्ष महोदय : आपने भी यह कला सीख ली है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के गांवों की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है और यदि हां तो अगली पंचवर्षीय योजना में कितनी आवश्यकता पूरी की जा सकेगी ?

श्री भक्त दर्शन : इसी बात को ध्यान में रख कर इस मामले की जांच करने के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की जा रही है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर कर के रूप में परिवहन उद्योग से लगभग 400 करोड़ रुपये लेती है। क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से कर से प्राप्त होने वाली इस राशि का एक निश्चित प्रतिशत गांवों में सड़कों के विकास के लिये निर्धारित करने की संभावना पर विचार करेगी ?

. **श्री भक्त दर्शन** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से हाल में बम्बई में पूछा गया था और व्यवहार्य न होने के कारण उन्होंने इसे बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया था।

Shri Ganga Reddy : How many years have so far elapsed out of 20 years fixed for road construction ?

Shri Bhakat Darshan : The first twenty year programme was for the period between 1941 and 1961. Now the second twenty year programme is under execution.

श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह बात मान ली है कि अन्तर्राज्यीय पुलों के निर्माण का सारा व्यय वह वहन करेगी, और यदि हां, तो मैसूर तथा आंध्र-प्रदेश सरकारों ने माधवरम मंत्रालयम के निकट तुंगभद्रा नदी पर एक पुल बनाने के लिये कहा है ?

श्री भक्त दर्शन : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर के लिये मुझे समय चाहिये। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में एक योजना है किन्तु इस योजना के अन्तर्गत सभी सड़कों अथवा पुलों का निर्माण नहीं हो सकता है, केवल चुनी हुई सड़कों अथवा पुलों का निर्माण हो सकता है।

Shri D. N. Tiwary : Two years of the Fourth Five Year Plan have passed. You have stated that out of the 20 percent grant 40 percent will be given by the Centre. How much amount has been aiven by the Centre to the States during these two years and what are the names of States to which this grant has been given ?

Shri Bhakt Darshan : The hon. Member might be aware that no amount has been given for new works during these two years. Therefore question does not arise.

Shri O. P. Tyagi : Is it not a fact that roads are being contructed by the Government with a view of economic point of view and this policy is also followed by the State Governments. But there places in India where the construction of roads is not useful with economic point of view. May I know whether Government propose to link tribal areas with the rest of the country by constructing road in those areas ?

Shri Bhakt Darshan : Keeping in view this fact the Planning Commission has put forth this scheme. Only after receiving the final shape of the Fourth Five Year Plan, some progress will be made.

Shrimati Jayben Shah : Several States are far behind the Nagpur Plan whereas several others are much advanced. May I know whether Government propose to take some specific steps to bring about retionalisation between them ?

Shri Bhakt Darshan : Government do not want to retard the progress of advanced States. No doubt efforts will be made for the advancement of the States which are behind the said plan.

Shri Lakhan Lal Kapoor : The hon. Minister has stated that the Planning Commission has prepared a scheme to spend 20 percent of the total amount allocated for road construction, in rural areas. Does the hon. Minister feel that this is a small amount to be spent on road construction and has he stated that more amount should be spent ?

Shri Bhakt Darshan : This allocated amount of 20 percent is the minimum. If the State want to spend more, we will appreciate it.

स्वेज नहर को पुनः खोलना

+
1055. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज नहर में सामान्य नौवहन पुनः आरम्भ हो गया है और यदि नहीं तो उसमें क्या रुकावट है;

(ख) यह रुकावट कब तक दूर हो जायेगी,

(ग) क्या भारत को माल लाने वाले जहाज रुके पड़े हैं अथवा वे जहाज आशा अन्तरीप से होकर आ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस लम्बे मार्ग से होकर जहाज आने से भारत को कितना अधिक भाड़ा देना पड़ेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) स्वेज नहर डूबे हुये जहाजों और संघर्ष के बाद की अवस्था के कारण बन्द है। जब तक इजरायली फौजे नहर के पूर्वीतट पर अधिकार रखेंगी तब तक अरब गणतन्त्र सरकार डूबे हुये जहाजों को हटाने के लिए तैयार नहीं है।

(ग) भारत के लिये 27400 टन बाजरा लाने वाला यू०एस० टैंकर आवजरवर स्वेज नहर में रुका हुआ है। अब भारत के लिये माल लाने वाले पोत आशा अन्तरीप होकर आने वाले मार्ग का व्यवहार कर रहे हैं।

(घ) प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार आशा अन्तरीप होकर भेजे जाने के कारण पूर्ण अतिरिक्त भाड़ा 35.05 करोड़ रुपये वार्षिक होने की सम्भावना है, इससे इस बात को मान लिया गया है कि निर्यात और आयात मौजूदा हालत में ही रहेंगे।

Shri Kameshwar Singh : May I know whether the hon. Minister has sent any officer or any other person to suez area who may examine whether the ships which are held up at the Suez Canal can pass through or not ? Have the Government made a request to the Egyptian Government for opening the Suez Canal for ships as the war has now been stopped ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य को पता ही होगा कि मिश्र सरकार हमारे इस दृष्टिकोण से भली प्रकार अवगत है कि स्वेज नहर को यातायात के लिए शीघ्र खोल दिया जाए। लेकिन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वेज नहर को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में मिश्र सरकार की नीति और कई बातों पर निर्भर करती है।

Shri Kameshwar Singh : According to the position of the Suez Canal Map the ships carrying 27 thousand tons of foodgrains to India can easily pass through Suez Canal

but the Egyptian authorities have deliberately detained it. Has the hon. Minister examined this matter ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात का पता नहीं है।

श्री पीलु मोडी : जहां तक मैं समझता हूँ यू० एस० टैंकर "आॅबजरवर" स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर है और डूबे हुए जहाज इसके उत्तर में हैं। क्या मंत्री महोदय को इस विशेष बात की व्यक्तिगत जानकारी है।

दूसरी बात मुझे यह भी ज्ञात हुई है कि डूबे हुए जहाजों के ऊपर से जहाजों का जाना सम्भव है। माननीय रक्षा मन्त्री से यह प्रश्न किया गया था लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

क्या परिवहन मंत्री इन दो आरोपों की विशेष जांच करवा रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे इसके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है क्योंकि मैं वहां नहीं गया हूं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे यह सूचना प्राप्त नहीं है जो कि माननीय सदस्य को है अर्थात् कि डूबे हुए जहाजों के ऊपर से जहाजों का जाना सम्भव है। मैं इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखूंगा और इनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आज के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार स्वेज नहर के बन्द होने के कारण दैनिक 3 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और इस स्थिति के सुधरने में कितना समय लगेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। 3 करोड़ रुपये मासिक क्षति है। जहां तक स्वेज नहर के पुनः खोले जाने का प्रश्न है मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said that the closure of Suez Canal has effected our Cargo Ships and our foodgrain ships are also held up there. Have the Government given consideration to any other sea route through which our goods can be brought to India easily and with less cost ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सारे जहाज अब आशा अन्तरीप से होकर आ रहे हैं।

स्वेज नहर के अतिरिक्त स्थायी रूप से कोई अन्य मार्ग अपनाने के बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : स्वेज नहर के बन्द हो जाने से न केवल हमारे खाद्यान्न लाने वाले जहाजों पर बल्कि रक्षा सम्बन्धी माल वाहक जहाजों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका से

खाद्यान्न लाने वाले एक जहाज के स्वेज नहर पर रुक जाने से और अन्य खाद्यान्न जहाजों के आशा अन्तरीप से होकर आने से भाड़े में वृद्धि हो गई है और इससे राज–कोष पर दबाव पड गया है । इन तथ्यों को ध्यान में रख कर, संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों के ध्यान को हमारी कठिनाइयों और मुशीबतों की ओर आकर्षित करने के अतिरिक्त क्या भारत सरकार ने विशेष रूपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान भी इस ओर दिलाया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इसके लिये समय चाहिए ।

श्री हेम बरुआ : परिवहन मंत्री को इस सम्बन्ध में वैदेशिक कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री से बातचीत करनी चाहिये थी ।

Shri Yashpal Singh : India always helped U. A. R. as the best friend but U. A. R. detained our ship during Indo-Pak conflict and now our food-ships are being detained. May I know whether any efforts were made to inquire from Shri Nasser, why only our ships are detained every time ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : It is wrong to say that Shri Nasser had detained this ship. It is well known fact that the situation developed there is responsible for detaining the ship. U. A. R. Government are making utmost efforts to help us. But as long as Israel troops are there in Suez Canal area, danger is also there. Our ship were not detained during Indo-Pak conflict. We have examined the possibility to release that sh p but for the time being it is not possible. We also tried to shift cargo of the ship to some other ship but so far we are not able to do so.

श्री पीलु मोडी : क्या नासिर साहिब ने माल को खरीदने के लिये भी प्रस्ताव किया है ?

Shri Jagjivan Ram : No, Sir. They do not require milo because they do not eat it. Therefore it is not feasible to sell it there.

Shri Ram Sewak Yadav : Can it not be diverted ?

Shri Jagjivan Ram : We have examined the possibility. The House is aware that we have also tried in U. N. O. to improve and normalise situation developed in that area.

Shri Kanwar Lal Gupta : India exports goods worth crores of rupees through Suez Canal, May I know what steps Government have taken to ensure that our export is not hampered ? To what extent the closure of Suez Canaal has affected our exports ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : अभी तक हमारे पास इस बारे में कोई विशिष्ठ जानकारी नहीं है । यह स्पष्ट है कि इससे माल भाड़े में वृद्धि हुई है । किन्तु अभी यह कहना कठिन है कि क्या इससे कोई करार रद्द हुआ है अथवा निर्यात में कमी हुई है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने कहा है कि मिश्र की सरकार ने हमारे जहाज नहीं रोके हैं । क्या मंत्री महोदय को पता है कि नासर साहब ने कहा है कि जब तक उस क्षेत्र में इसरायली सेनाएं हैं वह इन जहाजों को नहीं निकलने देंगे । उन्होंने इस सम्बन्ध में कठिनाइयों का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री जगजीवन राम : मैंने स्वयं कहा है कि जब तक इसराइली सेनायें उस क्षेत्र में, किसी जहाज का वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं है ।

Daughter's Share in Father's Property

+
***1056. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atma Das :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain State Legislative Assemblies have asked the Central Government not to allow share to the daughter in her father's property ;

(b) whether similar demands have been made in this regard by social, religious and political institutions ;

(c) if so, full details thereof and whether Government propose to make certain amendments in the law in this regard very shortly ; and

(d) if so, when, and if not, the reasons therefor ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) 8-12-1963 को करनाल में हुए 15वें अखिल भारतीय अकाली सम्मेलन के खुले अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया गया था (जिसकी प्रति शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर के सचिव द्वारा सरकार को भेजी गई थी) जिसमें सरकार से आग्रह किया गया गया था कि वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को इस प्रकार संशोधित करे कि निर्वसीयती मृतक के पुत्रों के साथ-साथ उसकी पुत्र-वधुओं को भी उत्तराधिकार के अधिकार का उपबंध हो जाए। उसमें जो कारण दिया गया है वह यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में के वर्तमान उपबंध के परिणामस्वरूप कृषि सम्पत्ति अधिकाधिक खण्डों में बंट जायेगी और भाइयों और बहनों के बीच वैमनस्य और कुल-बैर की भी सृष्टि होगी ।

अखिल भारतीय कृषक फैडरेशन, नई दिल्ली के अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनता सेवक समाज, रोहतक, भारतीय जनसंघ, पंजाब, जलंधर और चचरारी गांव, जिला लुधियाना, के अभिधारियों ने भी यह व्यपदेशन किया है कि पुत्रियों को विरासत में अपने श्वसुरों/पतियों की सम्पत्ति मिलनी चाहिए, न की अपने पिताओं की सम्पत्ति, और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का इस आधार पर सुझाव दिया है कि यह अधिनियम देश की कृषिक और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल नहीं है ।

सरकार की, इस प्रयोजन के लिए इस विधि (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) में कोई संशोधन करने की प्रस्थापना नहीं है, क्योंकि एक तो, दिल्ली और पंजाब से प्राप्त ऊपर निर्दिष्ट व्यपदेशनों के सिवाय, देश के किसी अन्य भाग या क्षेत्र से, किसी संगठन या संगम से कोई व्यपदेशन प्राप्त नहीं हुआ है । दूसरे, इससे यह दर्शित होता है कि देश की जनता ने जिस

पर कि यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के उपलब्धों को प्रतिगृहीत कर लिया है। तीसरे, संसद् ने पुत्री के अधिकार को, इस विषय पर वर्षों तक सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात् ही मान्यता दी थी। सरकार इस विनिश्चय को इतने वर्षों के पश्चात् उलटना उचित नहीं समझती; ऐसा करना, सरकार की राय में, एक प्रतिगामी कदम होगा।

Shri Prakash Vir Shashtri : Daugher should have a share in her fathers' property till her marriage and after marriage she should have a share in her husband's proerty to avoid illwill and family feuds between brothers and sisters. Do Government propose to consult the State Governments on the lines of the representations received from Delhi and Punjab so that an all-India policy in regard to Hindu Succession Law can be framed ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी, नहीं :

Shri Prakash Vir Shastri : Do Govt. propose to apply the Hindu Succession Act to all the communities keeping in view the secular character of our country ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सभी धर्मों के लिये एक समान संहिता बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। इसके रास्ते में कुछ कठिनाइयां हैं इसीलिये ऐसा करना संभव नहीं हो सका है।

इसे अन्य धर्मों पर लागू करने का प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

Shri Shiv Kumar Shastri : How many cases have so far been filed in the provincial and Central Courts after the enforcement of this Act with what results ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह जागकारी एकत्र नहीं की गई है और न ही यह उपलब्ध है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon. Minister has stated that the people seem to have aceepted the provisions of this act but in my opinion the hon. Minister's claim has no relation with facts. Do Government propose to appoint an enquiry commission to find out the number of transactions made under this Act and the extent to which daughers have inherited their patrnal property ? Their may hardly be one such case among one hundred cases. Therefore, I maintain that the people have not accepted it and it is an absolutely useless law.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने केवल वक्तव्य दिया है, प्रश्न नहीं पूछा है।

Shri Balraj Madhok : If the people of other States have not been vocal in voicing their grievances against the provisions of this Act, it does not mean that they have accepted this law. Is it not a reality that family feuds and ill will between brothers and sisters are being created by the provisions of this Act ?

If after marriage, a girl is given right to inherit from her 'ather-in-laws' property, it will meet the real object of this law. If this suggestion is accepted, it would save the society from much unpleasantness arising from the provisions of this Act.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य तर्क पेश कर रहे हैं और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

Shri Bal Raj Madhok : Will the hon. Minister consider and throw some light on it ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी, नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इस तर्क के आधार पर लड़के को अपने श्वसुर की सम्पत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिये ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस कानून अन्तर्गत कोई झगड़े हुए हैं और औरतों के अशिक्षित होने के कारण उनके भाई उनका शोषण करते हैं और अपनी बहनों को सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा नहीं देते और यदि हां, तो औरतों के साथ न्याय हो, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है और क्या इस काम के लिये कोई समिति स्थापित की जा रही है ?

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the steps that have been taken by the Govt. to implement the constitutional provision of having a common civil law for all the communities with the results thereof ? If no steps have been taken, what are the difficulties that are coming in our way ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक सभी सम्प्रदायों के लिये एक समान संहिता बनाने का प्रश्न है, बहुत से कदम उठाए गये हैं। परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं जैसा कि मैंने अभी कहा ......

श्री बलराज मधोक : क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य इसके लिये एक पृथक प्रश्न की सूचना दें क्योंकि यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बलराज मधोक : जब माननीय मंत्री यह उल्लेख कर रहे हैं कि कुछ कठिनाइयां हैं तो वह उन्हें कठिनाइयां बतानी चाहिये ।

श्री दा० रा० चव्हाण : काफी बाधायें पेश आ रही हैं......

श्री जी० भा० कृपालानी : वे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि कुछ सम्प्रदाय इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री दा० रा० चव्हाण : जिन समाजों पर सामान्य संहिता लागू होती है उनमें से कुछ समाज......

श्री बलराज मधोक : क्योंकि वे मुसलमानों के वोट (मत) चाहते हैं.......

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या यही उनका धर्मनिरपेक्षवाद है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिये । समान संहिता के लिए सम्बन्धित सम्प्रदाय द्वारा शुरूआत की जानी चाहिये । यहां पर लोकतंत्र है और हम किसी पर कोई चीज जबरदस्ती नही थोंप सकते हैं ।

Shri Ram Sewak Yadav : What steps have been taken during the last twenty years to frame a common code for all oommunities ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री जी० भा० कृपालानी : जब बहु-पत्नी विवाह की प्रथा हिन्दुओं के लिये खराब है तो क्या मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें नहीं हैं ? क्या वे एक-पत्नी विवाह का समर्थन नहीं करेंगी ? इसलिये मुस्लिम पुरुषों की बजाय मुस्लिम महिलाओं की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र है।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह एक अच्छा सुझाव है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपालानी : सरकार मुस्लिम महिलाओं का मत क्यों नहीं पूछती।

श्री गोविन्द मेनन : यह अच्छा सुझाव है।

Shri Prem Chand Verma. This Act has resulted in further fragmentation of land holdings by giving a share to a daughter in her fathers' property. Has any assessment been made of the repercussions of this law on small land holdings ?

Shrimati Jayaben Shah : What steps the Govt. propose to take to provide as much rights to Indian muslim women as provided to muslim ladies in Egypt, Pakistan and middle East ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क पेश कर रहे हैं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है।

Shrimati Jayaben Shah : What steps does the hon. Minister propose to take to secure the same rights for the Muslim women in India which have been secured for their counterparts in Egypt, Pakistan and Middle East countries ?

श्री गोविन्द मेनन : जैसी कि संविधान में व्यवस्था है, सभी सम्प्रदायों के लिए उत्तराधिकार, विवाह, आदि के मामले में एक समान संहिता लागू करने के बारे में एक-दो वर्ष पहले कुछ कदम उठाए गये थे और पूछ ताछ की गई थी, और यह मामला अभी छोड़ नहीं दिया गया है। सम्बन्धित सम्प्रदायों और उन सम्प्रदायों से सम्बन्धित संसद सदस्यों से राय मांगी गई थी। ज्यादातर लोगों की राय एक समान संहिता लागू करने के विरुद्ध थी।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या मुस्लिम महिलाएं एक सम्प्रदाय है या नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : आचार्य कृपालानी ने सुझाव दिया है कि बहु-पत्नी विवाह के बारे में मुस्लिम महिलाओं की राय ली जानी चाहिये। केवल महिलाओं की राय जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या ऐसा प्रयास किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विषय में आगे प्रयास किया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order. You should direct the Ministers to reply to the questions in the same languago in which they are put. The hon. Minister has not answered a simple qustion from Shrimati Jayaben Shah, instead he has taken up another point. I want your ruling as to when Ministers are going to be administered this direction.

अध्यक्ष महोदय : यह एक बढ़िया विचार है। पाकिस्तान और मिश्र ने जो कुछ किया है, हम उसे करने के लिये तैयार हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : इस पर विचार किया जायेगा ।

पश्चिमी एशियाई संकट के बाद राज्यों के खाद्यान्नों का आवंटन

+

*1057. **श्री अदिचन :** **श्री रामचरण :**
श्री वासुदेव नायर : **श्री भ० मांझी :**
श्री जनार्दनन् : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री म० ला० सौंधी :**
श्री रा० बरूआ : **श्री रति राम :**
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री स० कुन्डू : **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री ज० अहमद : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी : **श्री निहाल सिंह :**
श्री बेधर बेहेरा : **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री समर गुह : **श्री शिव पूजन शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट के पश्चात् राज्यों को खाद्यान्न आवंटन के मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और (ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये किये गये आवंटनों का व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) मुख्य मन्त्रियों को इस बात से अवगत किया गया कि स्वेज़ नहर के बन्द हो जाने से खाद्यान्नों की आमद में पर्याप्त विलम्ब होगा और इसीलिये सप्लाई अपेक्षाकृत कम रहेगी। राज्य सरकारों से इस बात पर औपचारिक रूप से विचार-विमर्श कर यह निश्चय करने का समय नहीं था कि इस महीने विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सप्लाई की जा सकेगी ।

(ख) जून के महीने में राज्यों को किये गये मूल आवंटन और स्वेज नहर बन्द हो जाने के बाद उनमें जो संशोधन करने आवश्यक हो गये थे, वे सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

जून 1967 के लिये राज्यों को गेहूँ और माइलों का आवंटित प्रभ्येश

राज्य का नाम		मूल			(हजार मीट्रिक टनों में पुनरीक्षित)		
		गेहूँ	माइलो	कुल	गेहूँ	माइलो	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	15.0	5.0	20.0	15.0	—	15.0
2.	आसाम	10.0	–	10.0	10.0	–	10.0
3.	बिहार	130.0	95.0	225.0	145.0 +9.8	50.0	195.0* +9.8 (जी)
4.	गुजरात	42.5	25.0	67.5	42.5	15.0	57.5,
5.	केरल	40.0	–	40.0	40.0	–	40.0
6.	मध्य प्रदेश	16.0	15.0	31.0	16.0	15.0	31.0%
7.	मद्रास	26.8	–	26.8	26.8	–	26 8%
8.	महाराष्ट्र	65.0	15.0	80.0	65.0	5.0	70.0
9.	मैसूर	9.0	2.0	11.0	9.0	–	9.0
10.	उड़ीसा	10.9	–	10.8	10.0	–	10.8
11.	पंजाब	5.0	–	5.0	5.0	–	5.0
12.	हरयाना	5.0	–	5.0	5.0	–	5.0
13.	चण्डीगढ़	1.4	–	1.4	1.4	–	1.4
14.	राजस्थान	25.0	15.0	40.0	25.0	10.0	35.0
15.	उत्तर प्रदेश	65.0	45.0	110.0	65 0	25.0	90.0
16.	पश्चिम बंगाल	75.0	5.0	80.0	75 0	5.0	80.0
17.	दिल्ली	32.5	–	32.5	32.5	–	32 5
18.	जम्मू तथा काश्मीर	10.0	–	10.0	10.0	–	10.0
19.	त्रिपुरा	2.0	–	2.0	2.0	–	2.0
20.	हिमाचल प्रदेश	6.0	–	6.0	6.0	–	60
21.	गोआ/दमन/दीव	3.1	0.3	3.4	3.1	0.3	3.4
22.	प्रतिरक्षा	13.0	–	13.0	13.0	–	13.0
22.	अन्य	14.8	0.3	15.1	14.8	0.3	15.1
	कुल	622.9	222.6	845.5	637.9 +9.8	125.6	763.5 +9.8

* पंजाब से 10,000 मीट्रिक टन जौ भी

" इसमें मुफ्त वितरण के लिये 2.5 भी शामिल है।

% इसमें मुफ्त वितरण के लिये 1.0 भी शामिल है।

केरल को चावल के लिये इसमें 2,500 मीट्रिक टन तथा 14,300 मीट्रिक टन का अतिरिक्त कोटा भी शामिल है।

(जी) कोटे से अतिरिक्त सप्लाई के लिये इस अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति दी गई है, परन्तु वह जुलाई, 1967 में ही भेजी जा सकेगी।

Shri Adichan : Will the hon. Minister kindly state the quantity of rice despatched to Kerala and other States during the months of June and July ?

Shri Annasahib Shinde : 62,000 tons of rice was sent to Kerala.

श्री रा० बरुआ : आसाम का गेहूं का कोटा 20,000 मीट्रिक टन प्रति मास से घटाकर 5,000 मीट्रिक टन प्रति मास कर दिया गया था। इसमें से भी मई और जून में पूरा कोटा नहीं दिया गया था। इस समय क्या स्थिति है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब हमने आसाम के लिये 15,000 मीट्रिक टनका नियतन किया है। ठीक है कि वहां पर बाढ़ तथा अन्य कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारी मंशा यह देखने की है कि नियत की गई मात्रा राज्य को मिले।

श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : मंत्री महोदय ने जून के आंकड़े बताये हैं। जुलाई में कुल कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है और उस महीने में कितनी मात्रा उपलब्ध होने की आशा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार हमें आशा है कि विभिन्न राज्य सरकारों को लगभग 7,92,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेंगे।

श्री रंगा : कुल आवश्यकता कितनी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि कमी वाले अधिकांश राज्य अधिक से अधिक मात्रा चाहते हैं।

श्री रंगा : प्रश्न यह नहीं है, आपने यहां एक बजट बनाया होगा कि इतनी मात्रा सप्लाई करनी है। वे तो केवल यह बता रहे हैं कि कितनी मात्रा नियत की गई है। उनके द्वारा तैयार किये गये बजट से वे यह बताने की स्थिति में होने चाहियें कि कुल आवश्यकता कितनी है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सभापटल पर रखे गये विवरण में वास्तव में दी गई मात्रा के आंकड़े दिये गये हैं।

श्री स० कुण्डू : जबकि खाद्य समस्या इतनी गंभीर है और हमें अनाज मिलने के लिये जहाजों के आने की बाट जोहनी पड़ती है और जबकि उड़ीसा सरकार गेहूं के बदले में अधिक

धान देने के लिये तैयार है, तो राज्य को गेहूं का मूल्य नियतन 10,800 मीट्रिक टन से घटाकर 10,800 मीट्रिक टन क्यों कर दिया गया ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पिछले महीने राज्य सरकारों को नियत मात्रा देने में हमें वास्तव में बहुत कठिनाई हुई। लेकिन हमारा प्रयास रहा है कि जब तक कोई ऐसी बात नहीं होती, जो हमारे वश में नहीं है, राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच जो भी समझौता है, उसका पालन किया जाये।

श्री स० कुण्डू : उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं समझा है। जब उड़ीसा गेहूं के बदले धान देने के लिये तैयार है, तो राज्य का गेहूं का कोटा बढ़ाने की अपेक्षा कम क्यों करते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : माननीय सदस्य की बात से मैं समझता हूं कि उड़ीसा सरकार गेहूं के बदले में असीमित मात्रा में धान देने को तैयार है। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन, जैसाकि सभा को मालूम है, जून में विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हमें कोटा कम करना पड़ा था।

श्री ज० अहमद : आसाम को अधिक चावल नहीं चाहिये, वे अधिक गेहूं चाहते हैं। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आसाम को कितने गेहूं का नियतन किया गया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं उत्तर दे चुका हूं। हम 15,000 मीट्रिक टन गेहूं आसाम को देने का प्रयास कर रहे हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

अ० स० प्रश्न 27. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री शम्भू नाथ :
श्री न० कु० सांघी : श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के तीसरे प्राक्रम के विस्तार के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : यह फैसला किया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 1.6 से 3.4 मिलियन टन तक विस्तार कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया जाय। यह निर्णय इस्पात की मांग, विशेषकर चपटे पदार्थों की मांग के पूर्व प्रत्याशित गति से धीमी गति से बढ़ने, प्रायोजना की अनुमानित लागत तथा विदेशी मुद्रा की लागत के उपलब्ध साधनों से अधिक होने तथा कारखाने के 1.00 मिलियन टन का सामान्य

उत्पादन और 1.6 मिलियन टन तक विस्तार करने की प्राथमिक आवश्यकता को देखते हुए किया गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या ब्रिटेन के सार्थ-संघ ने, जिसने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के तीसरे चरण के समय बढ़ाया था, अपना टेंडर वापस ले लिया है, अथवा क्या सरकार ने पुनः उनसे 160 लाख पौण्ड के ब्रिटिश ऋण को इस विस्तार कार्यक्रम के साथ नहीं जोड़ने के लिये कहा है ?

डा० चन्ना रेड्डी : ब्रिटिश सार्थ-संघ संगठन द्वारा टेंडर का प्रस्ताव इस वर्ष 30 जून, तक बंध था । उनके द्वारा टेंडर वापस लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । ब्रिटिश सरकार की ओर से सर हैनरी हार्टमैन के नेतृत्व में एक दल यहां आया था और उसने विचार-विमर्श किया था, तथा जो स्थिति पहले बताई गई है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विस्तार कार्य को स्थगित करने का निर्णय किया ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस्पात कारखानों के अन्य विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रांची स्थित हैवी इंजीनियरी कारखाने में प्रतिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त रहेगी क्योंकि सभी विस्तार कार्यक्रम रोक दिये जाने वाले हैं, और वह क्षमता कितनी है ?

डा० चन्ना रेड्डी : हैवी इंजीनियरी निगम की क्षमता पर विचार किया जा रहा है ताकि हमारे द्वारा आरम्भ किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उसका प्रयोग किया जा सके । जहां तक दुर्गापुर कारखाने के विस्तार का सम्बन्ध है, इससे हैवी इंजीनियरी निगम की क्षमता पर तुरन्त तथा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है ।

श्री न० कु० सांघी : दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार त्याग देने से क्या देश को आगामी वर्षों में अधिक आयात पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा ? इसको त्याग देने से क्या इस्पात कारखानों की क्षमता अब की अपेक्षा अधिक अप्रयुक्त नहीं रहेगी, और इस प्रकार देश में इस्पात की उत्पादन लागत बढ़ेगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : क्षमता के बेकार रहने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि पहले ही 160 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार हो चुका है, और इस प्रकार हम सारी उत्पादन क्षमता को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं । इस्पात की आवश्यकता के बारे में, प्राक्कलन हाल में राष्ट्रीय व्यावहारिक, आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सौंपे गये हैं, और उनका निष्कर्ष है कि 100 लाख मीट्रिक के हमारे मूल प्राक्कलन के स्थान पर यह 84 लाख मीट्रिक टन होगी । इसलिए पूरी स्थिति पर विचार किया गया है और अधिक अव्यवस्था नहीं होगी ।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले ब्रिटेन के विशेषज्ञों के एक दल ने इस कारखाने का दौरा किया गया था और उन्होंने मत व्यक्त किया था (क) कि कर्मचारी श्रमिकों की वर्तमान संख्या 14,000 से 8,000 की जानी चाहिए, (ख) कि परामर्शदाता अथवा ब्रिटिश प्रतिनिधियों को, जो भी है, प्रबन्ध में कुछ प्रतिनिधित्व देना चाहिए और (ग) कि उन्हें

विस्तार कार्यक्रम की व्यवहार्यता में सन्देह है ? मैं जानना चाहता हूँ कि इस विस्तार को स्थगित करने के लिये ब्रिटेन के इस विशेषज्ञ दल का बाधा डालने वाला यह रवैया और दबाव उत्तरदायी है ।

डा० चन्ना रेड्डी : ब्रिटिश सरकार द्वारा बाधा डालने के तरीके अपनाने अथवा दबाव डालने की बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की । बात केवल इतनी है कि हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति और विभिन्न कारखानों, विशेष रूप से बोकारो, को दिये गये वचनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि इस वर्ष वह आवश्यक धन प्रदान नहीं कर सकेगी ।

श्री उमानाथ : मेरा अभिप्राय ब्रिटिश सरकार से नहीं था, मेरा अभिप्राय यह था कि क्या ब्रिटिश विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की थी ?

डा० चन्ना रेड्डी : उन्होंने विशेष रूप से ऐसी कोई राय नहीं दी थी । उन्होंने कारखाने का दौरा किया था और हमारे साथ विचार-विमर्श के दौरान आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने आदि की बातें अवश्य कही गई थी और हम भी इस बात को महसूस करते हैं तथा हम इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं । विस्तार स्थगित करने के कारण केवल वही है, जिनका मैने उल्लेख किया ।

श्री कार्तिक ओरांव : क्या निर्माण के दूसरे चरण की निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन हुआ है; यदि हां, तो लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितनी क्षमता के अनुसार उत्पादन हुआ ?

डा० चन्ना रेड्डी : दूसरे चरण के लिये निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हुआ है, जो 16 लाख मीट्रिक टन थी । मुझे खेद है कि वास्तविक उत्पादन के आंकड़े इस समय मेरे पास नही हैं ।

श्री कृष्ण मूर्ति : इन क्षेत्रों से दक्षिण को इस्पात भेजने की लागत लगभग 50 से 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । क्या सरकार इन सभी इस्पात कारखानों का विस्तार करने से पहले दक्षिण भारत के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सेलम, विशाखापट्टनम और हास्पेट में तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने पर विचार करेगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न विचाराधीन प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Kameshwar Singh : May I know whether this expansion programme of Durgapur Steel Plant will be based on the latest technology of continuous steel production or on the old one ? Under the continuous steel production technology the manufacture of finished goods proceed simultaneously with the manufacture of iron and it is cheaper as well than the old method.

Dr. Chenna Reddy : I cannot offer any specific comments now on the technology referred to by the hon. Minister but generally speaking. I can say that it will be the first duty of the Planning Commission to make use of the new technology wherever available.

Shri Achal Singh : There is already so much production in the existing plants that the market has gone down. May I know the desirability of setting up Bokaro Plant in the context of such a situation ?

Dr. Chenna Reddy : Bokaro Plant is needed and we are considering it so that it may help us in meeting our ultimate demand by 1970-71

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : मंत्री महोदय ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार जिन बातों को ध्यान में रखकर स्थगित किया था, वे अधिक अथवा कम सामान्य रूप से सभी इस्पात कारखानों पर लागू होती है ।

क्या सरकार भारत में सभी इस्पात कारखानों का और विस्तार उस समय तक स्थगित करने पर विचार करेगी जब तक कि अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं जाती और खपत बढ़ नहीं जाती ?

डा० चन्ना रडडी : कुछ सीमा तक आवश्यक धन प्रदान करना संभव है । बोकारो को आरम्भ किया गया है और उसके निर्माण का कार्य आगे चल रहा है । इसके आगे सरकार समझती है कि हम आवश्यक धन नहीं दे सकते और इसलिये अन्य विस्तार स्थगित कर दिया गया है ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुर्गापुर की पूरी निर्धारित क्षमता प्रयोग नहीं की जा रही है और वहां पर फोर्ज फाउंड्री प्लांट में, जिसकी क्षमता 2,000 मीट्रिक टन प्रति मास है, केवल 200 मीट्रिक टन मासिक उत्पादन होता है, क्या सरकार कोई अन्य कारखाना स्थापित करने अथवा किसी इस्पात कारखाने का विस्तार करने से पहले प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी ?

Dr. Chenna Reddy : In fact we are trying our best to utilise the installed capacity. This fact has been mentioned in the answer also.

श्री रंगा : श्री राममूर्ति ने एक बहुत उपयोगी सुझाव दिया है । मंत्री महोदय ने कहा कि यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, अध्यक्ष महोदय, आपको यह कहना चाहिए कि यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है, यह सरकार के विचारार्थ है । मैं चाहता हूँ कि सरकार इस सुझाव पर तथा अन्य सुझाव पर भी विचार करे न कि केवल इसलिए कि सरकार ने एक निर्णय कर लिया है, बोकारो कारखाने पर ही रुक जाये ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : पांडे समिति ने कमियों और अप्रयुक्त क्षमता के बारे में एक सुझाव दिया था, इस बीच सरकार ने पांडे समिति द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : पांडे समिति ने मुख्य रूप से दुर्गापुर कारखाने के संधारण में उपेक्षा पर जोर दिया है, और वे इसके लिये विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने का प्रयास

करते रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के परामर्श से मंत्रालय ने विवरण पर विचार किया है और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास कर रहा है।

Shri D. N. Tiwary : Is it not a fact that any extension now under taken with the present shortfalls and discrepancies persisting in Durgapur Plant, it will be useless and therefore it will be better first to improve the position there and then only to expand Bokaro so that production of iron is not affected ?

Dr. Chenna Reddy : It is correct and we are working on these very lines.

श्री कंडप्पन : समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत में निर्मित इस्पात के बारे में कुछ देशों ने पूछ-ताछ की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेशों को भारतीय इस्पात के निर्यात की संभावना का पता लगाया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : जैसा कि इस माननीय सभा को मालूम है, हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं; और यह इस्पात उद्योग में हमारी मुख्य प्राथमिकता वाली मद रही है। गत वर्ष 28 करोड़ रुपये के माल का निर्यात हुआ और इस वर्ष हमने लगभग 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इस्पात की कितनी प्रतिशत आवश्यकता देश में से ही पूरी होती है और इस्पात में हमारे कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है तथा क्या सरकार ने इस विषय के इस पहलु पर भी विचार किया है, अर्थात् पहले लोगों की इच्छाओं को बहुत बढ़ाना और बाद में उन्हें कम करना, और आंध्र प्रदेश में ऐसा करने के बाद क्या सरकार बोकारो कारखाने के साथ-साथ अब विशाखापट्टनम में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले ही उठाई जा चुकी है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : श्रीमान् मैं उत्तर चाहती हूं।

डा० चन्ना रेड्डी : इस्पात में आत्म-निर्भरता का प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है क्योंकि आज भी हम विभिन्न प्रकार के इस्पात में आत्म-निर्भर हैं। कुछ अन्य प्रकार के इस्पात के बारे में, जैसे विशेष इस्पात तथा मिश्रित इस्पात आदि के बारे में वास्तव में आत्म:निर्भर होने में समय लगता है और शायद इस्पात की मुख्य मदें हमें हमेशा आयात ही करनी पड़ें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

1053. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति मात्रा समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों की केन्द्रीय सप्लाई प्रत्येक राज्य में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति की जाने वाली सप्लाई की मात्रा के समान मानक पर आधारित नहीं की जा सकती है। किसी वर्ष विशेष में कुछ राज्य अपने राज्य में खपत के लिये अपेक्षित मात्रा से अधिक पैदा करते हैं और अन्य राज्य अपनी आवश्यकताओं का कुछ अंश ही पैदा कर पाते हैं। यह अंश भी प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का केन्द्रीय आवंटन खाद्य सामग्री सम्बन्धी बातों को ध्यान में रख कर केन्द्र के पास कुल उपलब्धि और प्रत्येक राज्य की सापेक्ष आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

आसाम में पटसन का उत्पादन

1058. **श्री रा० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पटसन का उत्पादन लगातार गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जहां तक अच्छी किस्म की पटसन मिलने का सम्बन्ध है इसका पटसन उद्योग पर क्या प्रभाव हुआ है;

(ग) क्या आसाम में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो क्या; और

(घ) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है कि पटसन के मूल्य कलकत्ता में आसाम की पटसन के न्यूनतम मूल्यों से नीचे न गिरें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। पिछले वर्ष की अपेक्षा 1966–67 में उत्पादन बेहतर था। अब तक फसल अच्छी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 977/67] इससे उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी प्रयत्नों का पता लगेगा।

(घ) कलकत्ता में आसाम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम साहाय्य मूल्य से चालू मूल्य अधिक हैं।

नये हवाई अड्डों का निर्माण

*1059. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक नये हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो कहां-कहां, और कितनी लागत पर तथा कितनी अवधि में;

(ख) निर्माण सम्बन्धी फिटिंग तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(ग) क्या इतनी भारी रकम व्यय करना आवश्यक है जबकि वर्तमान हवाई अड्डे सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो नये हवाई अड्डों का निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) यह प्रश्न अनुमानत: विद्यमान हवाई अड्डों के सुधार और नये हवाई अड्डों के निर्माण आरम्भ करने की योजनाओं के बारे में है । जहां तक पहले का सम्बन्ध है, 1970 से आरंभ होने वाले दशाब्द में बहुत बड़े 'सबसानिक और सुपरसानिक' विमानों के आरंभ किये जाने की दृष्टि में रखते हुए चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की जा रही है । यह कहना सही नहीं है कि विद्यमान हवाई अड्डे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध टर्मीनल सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं । इसलिए अगले दशाब्द में विमान यातायात की अत्यधिक बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन हवाई अड्डों के सुधार के एक सुनियोजित एवं वृहद् कार्यक्रम का अनुष्ठान आवश्यक है । इसमें आवश्यक रूप से कुछ विदेशी मुद्रा खर्च होगी लेकिन समिति की रिपोर्ट मिलने से पहले अभी इस अवस्था में कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

जहां तक अन्य विद्यमान हवाई अड्डों तथा नये हवाई अड्डों के निर्माण का भी सम्बन्ध है, ये कार्य इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथावश्यक रूप से निरन्तर होते रहते हैं ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का वितरण

1060. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज के वितरण में पक्षपात किये जाने की शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने वितरण के ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिये, पर्यवेक्षण का कोई तरीका निकाला है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई विशेष निदेश दिये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में कमी से प्रभावित बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया गया था । बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों के भेद-भावपूर्ण वितरण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं । मध्य प्रदेश सरकार से अभी उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के वितरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केन्द्रीय सरकार उसकी देख-रेख नहीं करती है । तथापि, सरकारी वितरण प्रणाली में आई किन्हीं त्रुटियों की जानकारी होने पर केन्द्रीय सरकार उन पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करती है ।

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौवहन

1061. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **परिवहन और नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन अनुसंधान निदेशालय ने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की नौवहन क्षमता का कोइ अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या अन्तर्देशीय नौवहन निदेशालय ने परियोजित अन्तर्देशीय नौवहन की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(घ) क्या इस योजना में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की कर्षनावों (पुश टंग) और बजरों का पूर्ण उपयोग भी सम्मिलित है ?

परिवहन और नौवहन मंत्री (डा० वी. के. आर. वी. राव) : (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 978/67**]

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग

1062. श्री मरन्डी :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल से गन्ने के खेतों में खाद्यान्न उगाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा कुल कितनी भूमि पर खाद्यान्नों की खेती की जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों ने यह संकेत दिया है कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) किसी भी विशेषज्ञ से ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास राज्य के लिये उर्वरकों का नियतन

1063. श्री कंडप्पन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967–68 के लिए मद्रास राज्य सरकार के जितने उर्वरकों के नियतन की मांग की थी उसके लिए उससे आधी मात्रा में उर्वरकों का नियतन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को उन महान प्रयत्नों की जानकारी है जो एक वर्ष की अल्पावधि के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाने के लिए मद्रास राज्य में किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों का जितना कोटा देने का वचन दिया गया था क्या ठीक समय पर वह कोटा राज्य सरकार को दे दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । जुलाई से सितम्बर 1967 की अवधि के लिए मद्रास राज्य को 10,000 मीटरी टन अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया गया है ताकि उस राज्य में अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत लाये गये अतिरिक्त क्षेत्रों की मांग को पूरा किया जा सके ।

(ग) जी हां ।

स्वेज नहर में से होकर जाने वाले जहाजों का मार्ग-परिवर्तन

1064. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री सिक्वेरा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि स्वेज नहर में से होकर आने वाले जहाजों के मार्ग परिवर्तन से, हमारे पत्तनों में भीड़ होने के कारण माल उतारने में, विशेषकर अनाज उतारने में बाधा उत्पन्न न होने पाये, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी आठ सप्ताहों में प्रत्येक बड़े पत्तन पर प्रति सप्ताह कितना कितना अनाज आने की आशा है और शीघ्र तथा निरन्तर माल उतरवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) स्वेज नहर के बन्द हो जाने और जो जहाज समुद्र में थे उन्हें आशा अन्तरीप के रास्ते मोड़ने से उनके पहुंचने में विलम्ब होने के कारण विशेषकर जुलाई, 1967 के दूसरे सप्ताह में विभिन्न बन्दरगाहों पर जहाजों के भारी जमाव हो जाने की आशा है। यह अवश्यम्भावी था। मानसून के महीनों में हमारी विभिन्न बन्दरगाहों पर खाद्यान्न संभालने की कुल क्षमता 8 और 9 लाख मीटरी टन के बीच है, इसीलिये कुछ जहाजों के घाट पर लगने में देरी हो सकती है। तथापि, इन आने वाले खाद्यान्नों के किसी बड़े भाग को संभालने में किसी ऐसी कठिनाई की सम्भावना नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। बड़ी बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों के जहाजों के लिये अधिक घाट सुलभ करने के पग उठाये जाएंगे और बन्दरगाहों पर सम्भालने की क्षमता बढ़ाने के लिये कुछ खाद्यान्न जहाजों से धारा और मझधार में भी माल उतारने का काम किया जाना है। देश की लगभग सभी बन्दरगाहों का जहां मानसून में भी जहाजों से खाद्यान्न उतारा जा सकता है, पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा। जुलाई, 1967 में प्रत्येक बन्दरगाह पर सप्ताहवार जिन खाद्यान्न जहाजों की पहुँचने की आशा है, का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 979/67**] अगस्त, 1967 के महीने में पहुँचने वाले जहाजों के बारे में पूरी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद

1065. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री य० श्र० प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री रामजी राम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इस खरीददारी की शर्तें क्या होंगी; और

(ग) यह गेहूं कब तक भारत आ जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने आस्ट्रेलिया से एक वर्ष के अल्पकालीन उधार पर इस वर्ष अब तक 183 हजार मीटरी टन गेहूँ वाणिज्यिक आधार पर खरीदा है। आशा है कि यह गेहूं अगस्त, 1967 तक भारत पहुंच जाएगा।

Intensive Agriculture Programme in Maharashtra

***1066. Shri D. S. Patil :**
Shri R. D. Bhandare :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Maharashtra Government prepared a 'Crash Programme' for intensive agriculture some time ago;

(b) whether the said programme was sent to the Central Government for approval and financial assistance;

(c) whether this programme has been implemented in any manner; and

(d) if so, whether suitable results have been achieved after its implementation and the amount of expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No proposal involving intensive agriculture and of the nature of a 'Crash Programme' has been received so far from the Government of Maharashtra, apart from the normal plan schemes like the High-Yielding Varieties Programme. Minor Irrigation, etc., which are received and considered from time to time.

(b) to (d) Do not arise.

ग्वालियर (मध्य प्रदेश में) भूख से मृत्यु

1067. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 16 जून, 1967 को 2 बजे दोपहर को ग्वालियर में गोमती बाई नाम की एक बूढ़ी स्त्री भूख के कारण मर गई थी;

(ख) क्या उसकी लाश को शव परीक्षा के लिये भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में सही तथा विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो, इसके लिये सरकार क्या स्थायी व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) यह सच है कि गोमती बाई नाम की एक महिला, जिसकी आयु 70 वर्ष की थी, की 16 जून, 1967 के दोपहर के बाद ग्वालियर के बड़ा बाजार के पास मृत्यु हो गयी थी। चूंकि यह मौत कथित भुखमरी से हुई थी, इसीलिये उसका शरीर "पोस्ट मार्टम" के लिये भेजा गया था जिससे ज्ञात हुआ कि यह मृत्यु टी० बी० के कारण हुई थी।

(घ) जी हां। उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में दी गयी सूचना जैसी ही है।

(ङ) सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने और लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास सम्बन्धी कार्यक्रम चला रही है। सरकार को यह आशा है कि इससे देश व्यापी कुपोषण दूर हो जाएगा, जो कि निस्संदेह भारतीय जनता के बहुत से वर्गों में व्याप्त है।

एयर इंडिया को विमान-चालाकों की हड़ताल के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

***1068. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमान-चालकों की हड़ताल के कारण एयर इंडिया को दिन-प्रतिदिन विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक हानि हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारण अब तक विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) एयर इंडिया की कितनी विमान सेवायें रद्द करनी पड़ी तथा उनमें देरी हुई तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) एयर इंडिया के विमान-चालकों के वेतन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णी सिंह) : (क) एयर इंडिया को अपने विमान-चालकों की हड़ताल के कारण प्रति दिन विदेशी मुद्रा की लगभग 5.00 लाख रुपये की विशुद्ध हानि हुई।

(ख) हड़ताल के 4 दिनों के दौरान विदेशी मुद्रा की अनुमानित हानि 20.00 लाख रुपये की हुई।

(ग) मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 980/67**]

(घ) अन्य एयरलाइनों के विमान-चालकों के वेतन के बारे में सूचना अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

4910

खेती का आधुनिकीकरण

1069. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर देश में खेती के आधुनिकीकरण के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी आवश्यकता का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये, संख्या एल० टी० 981/67**]

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमरीका से गेहूं की खरीद

1070. श्री म० ला० सोंधी :
श्री मरण्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप माल भाड़े में वृद्धि हो जाने के कारण सरकार ने अमरीका से गेहूँ की अधिकांश खरीद स्थगित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खरीद स्थगित की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली अनाज की आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर में जोरदार खाद्य कार्यक्रम

1071. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर सरकार ने अपने "जोरदार खाद्य उत्पादन कार्यक्रम" के लिये आठ करोड़ रुपये की वार्षिक राजसहायता मांगी है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रार्थना को उत्तर प्रदेश और बिहार के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों की प्रार्थनाओं की अपेक्षा वरीयता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

***1072. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टी. डब्ल्यू. ए., अलिटालिया, बी. ओ. ए. सी., लुफ्थान्सा, एयर इंडिया तथा एयरलाइन्स विमान सेवाओं को प्रति वर्ष काफी मुनाफा हो रहा है यद्यपि उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और वे वाणिज्यिक आधार पर चलाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है यद्यपि उसकी प्रत्येक उड़ान में विमान पूर्णतया भरा होता है और इस सम्बन्ध में उसका बिना प्रतिस्पर्धा के एकाधिकार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णी सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को 1959–60 से 1965–66 तक के वर्षों में मुनाफा हुआ। लेकिन उन्हें मुख्यतः अवमूल्यन तथा बढ़े हुए वेतनों के कारण वर्ष 1966–67 में घाटा हुआ।

सूखा-ग्रस्त राज्यों में राशन व्यवस्था

1073. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री मरण्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अपेक्षित मात्रा में अनाज न मिलने के कारण उन क्षेत्रों में अनाज की राशन व्यवस्था प्रायः समाप्त होने वाली है; और

(ख) उन क्षेत्रों में राशन-व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार ने उन राज्यों को न्यूनतम अपेक्षित में अनाज की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां; सरकार ने बिहार के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों को देखा है ।

(ख) केन्द्र सरकार और राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूखा पीड़ित राज्यों की सीमित उपलब्धि की सीमा के अन्दर अधिकतम अनाज सप्लाई करने का प्रबन्ध कर रही है ।

किसानों द्वारा देय बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बारे में सूखा-ग्रस्त राज्यों को निर्देश

1074. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि भयंकर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों ने बीज तथा उर्वरक आदि खरीदने के लिए जो ऋण लिये थे, उनकी देय बकाया राशियों को बट्टे खाते डाल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सूखे से प्रभावित राज्यों की सरकारों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है । कृषकों को दिये गये ऋण को बट्टे खाते में डालने का प्रश्न मुख्यतः राज्य सरकारों के विचार का विषय है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये फालतू गेहूँ देने की पंजाब सरकार की पेशकश

1075. श्री मरंडी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामजी राम :
श्री झा० सुन्दरलाल :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पंजाब सरकार ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अभावग्रस्त क्षेत्रों को अनाज के फालतू स्टाक सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितना और क्या केन्द्र ने इसे स्वीकार कर लिया है और पंजाब सरकार ने ऐसा करने के लिये कहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) चालू वर्ष में पंजाब सरकार ने कमी वाले राज्यों के लिये 6 लाख मीटरी टन खाद्यान्न देने का वायदा किया है। जब कभी विभिन्न खाद्यान्नों की मात्राएं वास्तव में उपलब्ध होती हैं और तुरन्त निर्यात के लिये दी जाती है तब आवंटन किये जाते हैं। अब तक बिहार, हिलाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को किये गये आवंटन इस प्रकार हैं :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

	बिहार	**हिमाचल प्रदेश**	**पश्चिमी बंगाल**
चावल (साबत)	—	3,000	9,200
टूटा चावल	1,100	—	10,000
गेहूं	—	10,000	20,000
जौ	10,000	—	2,500
चना तथा चने की दाल	100	25	1,050

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के लिये खाद्यान्नों का मासिक कोटा

1076. श्री यशपाल सिंह :
श्री मरंडी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने उनके साथ अपनी भेंट में आयातित अनाज के वर्तमान मासिक कोटे को 1,20,000 मीट्रिक टन से बढ़ा कर 2,00,000 मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से मिले थे और उनसे आयातित खाद्यान्नों के मासिक कोटे में वृद्धि करने को कहा था।

(ख) जुलाई के लिए पहले ही आवंटित कोटे में कुछ वृद्धि की जा रही है।

अनाज ले जा रहे जहाजों को मोड़ना

1077. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री सिक्वेरा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज सप्लाई करने वाले देशों से पश्चिम एशिया के संकट के कारण अनाज की सप्लाई में हुए अन्तर को पूरा करने के लिये अन्य खरीददारों के लिए अनाज ले जा रहे जहाजों को समुद्र से ही भारत की ओर मोड़ने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) किन-किन देशों से ऐसा अनुरोध किया गया है, वह किस-किस तारीख को किया गया और उस सम्बन्ध में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 9 जून, 1967 को आस्ट्रेलिया से समुद्र में दो गेहूँ के जहाजों और दो जहाज जिन पर अन्य देशों के लिये गेहूँ लादा जा रहा था, को भारत की ओर मोड़ने का अनुरोध किया गया था। बाद में सरकार को यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित जहाजों को मोड़ना सम्भव नहीं था।

कृषि वर्षा करना

***1078. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा कृत्रिम वर्षा करने के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों के उत्साहवर्द्धक परिणाम' रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रयोगों में क्या सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि आस्ट्रेलिया ने बादल बनाने में सफलतापूर्वक प्रयोग किये हैं, जिनसे विक्टोरिया के क्षेत्रों में, साथ के गेहूँ पैदा करने वाले ऐसे क्षेत्रों की तुलना में जहां ऐसे बादल नहीं बनाये गये, 24 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में आस्ट्रेलिया से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये उस देश के साथ एक करार करने का विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रयोगों से पता लगा है कि बादल बनाने के दिनों में वर्षा में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) आस्ट्रेलिया के प्रयोगों के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न परिणाम निकले हैं।

(घ) जी, नहीं। बादल 'बनाने' की आस्ट्रेलिया की तकनीक भारतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नही समझी गयी है।

शीघ्र उपज देने वाले गेहूं के बीज की बढ़िया किस्म

*1079. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने गेहूं के शीघ्र उपज देने वाले बढ़िया किस्म के बीज पैदा किये हैं;

(ख) क्या आगामी रबी की फसल की काश्त के लिये ये नये बीज कृषकों को दिये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो नये बीज कुल कितने क्षेत्र में बोने का लक्ष्य है; और

(घ) नये बीज कृषकों को किस मूल्य पर बेचे जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली ने मैक्सिको से प्राप्त डर्वाफ सामग्री में से सोनोरा 64 नामक शीघ्र उपज देने वाले गेहूं के बीज की बढ़िया किस्म को चुना है। परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए यह किस्म 90- 120 दिनों में पक जाती है। सौनोरा 64 का लाल रंग अब तकनीकी पद्धति से बदल दिया गया है। इस नई किस्म का नाम शरबती सौनोरा रखा गया है। इसमें पहली किस्म की अपेक्षा 25 प्रतिशत प्रोटीन अधिक है।

(ख) इस वर्ष रबी के दौरान किसानों में वितरित करने के लिए शरबती सौनोरा के कुछ बीज उपलब्ध किये जाएंगे। सौनोरा 64 के बीज काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) 200,000 एकड़ भूमि में सौनोरा 64 बोने के लिए और लगभग 1000 एकड़ भूमि में शरबती सौनोरा बोने के लिए बीज उपलब्ध होंगे।

(घ) बीजों का मूल्य विभिन्न राज्यों में कृषि विभागों द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष

*1080. श्री मरन्डी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष के लिये बनाई गई सुनियोजित योजनायें आधा वर्ष गुजरने से पहले ही समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों ने भारत द्वारा की गई व्यवस्था के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस प्रकार की एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आयी है लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को सही नहीं मानती;

(ग) जी, नहीं। सामान्य तौर पर विदेशी पर्यटकों ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के प्रबन्धों के प्रति किसी प्रकार का असन्तोष व्यक्त नहीं किया है;

(घ) पर्यटन विभाग पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं के पुनरालोकन तथा उनका विकास करने की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहता है ?

मध्य देश के लिये खाद्यान्न का नियतन

***5147. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष केन्द्र से प्रत्येक महीने में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, माइलो और चीनी की कितनी मात्रा मांगी थी;

(ख) मध्य प्रदेश के लिये प्रत्येक महीने में उक्त खाद्यान्नों की कितनी कितनी मात्रा नियत की गई और कितनी मात्रा में ये अनाज वास्तव में राज्य द्वारा लिये गये तथा कितनी मात्रा में ये अनाज प्रत्येक मास में नहीं लिये गये;

(ग) क्या चीनी का कोटा देर से नियत किये जाने के कारण ट्रकों से ले जाना पड़ा;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ङ) में उल्लिखित प्रबन्ध करने पर भी चीनी के कोटे का कुछ अंश नहीं ले जाया जा सका;

(ङ) क्या ट्रकों द्वारा चीनी ले जाने से दर में वृद्धि होती है; और

(च) यदि हां, तो कोटे के छूट जाने, ट्रकों द्वारा माल ले जाने तथा उसके परिणामः स्वरूप मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने ज्वार और बाजरे की कोई मांग नहीं की है। उन्होंने प्रत्येक मास के लिये आवश्यक अपनी चीनी की मांग की रिपोर्ट भी नहीं दी है। विभिन्न समय पर प्राप्त हुई सूचना के अनुसार प्रत्येक महीने की गेहूं और माइलो की मांग इस प्रकार है :—

मास महीना	(1·000 टनों में आंकड़े) आयातित गेहूं और माइलो
जनवरी, 67	75.0
फरवरी, 67	75.0

मार्च, 67	75,0
अप्रैल, 67	81.0
मई, 67	53.0
जून, 67	53.0

(ख) मध्य प्रदेश की प्रत्येक महीने, गेहूं, माइलो और चीनी की नियत की गई मात्रा तथा वास्तविक मात्रा में इन अनाजों को भेजे जाने सौंपे जाने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:--

महीना	गेहूँ और माइलो की नियत की गई मात्रा	चीनी	गेहूँ और माइलो भेजे जाने/सौंपे जाने की मात्रा	चीनी	गेहूं और माइलो की मात्रा में ह्रास होना	चीनी
जनवरी, 67	40.0	14.6	41.8	13.2	(*)	414 टन
फरवरी, 67	40.0	14,6	29.7	14.5	(*)	23 ,,
मार्च, 67	35.0	11.0	24.3	13.1	(*)	111 ,,
अप्रैल 67	31.5	11.2	27.2	8.9	(*)	57 ,,
मई, 67	30.5	9.2	30.1	उपलब्ध नहीं	(*)	
जून, 67	31.2	9.2	28.4	,,	(*)	

(*) न भेजे गये/न सौंपे गये गेहूं और माइलो जिसकी मात्रा में ह्रास नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ट्रकों द्वारा भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मात्रा में ह्रास होने का कारण मात्रा का देरी से नियत किया जाना नहीं है। आवंटन आदेश में यह शर्त थी कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि निर्धारित चीनी को कारखाने के द्वार से उठा सकते हैं या कारखाने से निर्धारित चीनी रेल द्वारा भेजने के लिये कह सकते हैं। मात्रा निर्धारित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

आवंटन आदेश में उल्लेखित सौंप देने की तारीख से बहुत पहले ही मात्रा निर्धारित कर दी गई थी और इस तारीख से 45 दिन पूर्व ही सौंपने का कार्य आरम्भ हो सकता है।

(ङ) रेल से भेजे जाने की तुलना में चीनी को ट्रकों से भेजने में अधिक खर्च होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) कोटे को ह्रास जाने से बचाने या इस बात का निर्णय लेने के लिये कि कोटे को रेल या ट्रकों द्वारा भेजा जाये, राज्य सरकार का दायित्व है।

मध्य प्रदेश में बरमे (रिग) तथा छिद्रण उपकरण

5148 श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने बरमें (रिग) तथा छिद्रण उपकरण इस समय काम कर रहे हैं अथवा प्रयोगार्थ उपलब्ध हैं तथा उनका उपयोग करने के लिए कितना शुल्क लिया जाता है;

(ख) क्या ये उपकरण मांग की कमी के कारण बेकार पड़े रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में पानी की अत्यधिक कमी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर बरमे तथा छिद्रण उपकरण राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रयोग के लिए देने की व्यावहारिकता का सरकार विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जारही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ, दमण और दीव में छोटे सिंचाई कार्य

***5149. श्री शिकरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने छोटे सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार की है और केन्द्रीय सरकार ने उसको मन्जूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) 1966-67 के दौरान 3.39 लाख रुपयों की 12 लघु सिंचाई योजनायें अनुमोदित की गईं । इन योजनाओं का व्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 982/67**] 1967-68 के लिए प्लान आऊटले 12 लाख रुपये का है ।

भारतीय केन्द्रीय रुई समिति

***5150. श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो अमरीकी विशेषज्ञों की सलाह पर भारतीय केन्द्रीय रुई समिति भंग कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या सलाह दी थी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो, तो उस समिति को भंग कर देने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 983/67**]

अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों का गत चुनावों में भाग लेना

5151. श्री इ० रा० परमार
श्री रा० की० अमीन :

क्या **विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आम चुनावों में सामान्य स्थानों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा तथा राज्यवार उनका व्यौरा क्या है और वे किन किन राजनैतिक दलों के थे; और

(ख) उनमें से कितने प्रत्याशी चुनावों में जीते तथा उनका राज्यवार व्यौरा क्या है और वे किन किन राजनैतिक दलों के हैं ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जानकारी संगृहीत की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में कृषि सम्बन्धी नया प्रस्ताव

5152. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कृषि सम्बन्धी नई नीति के अन्तर्गत गुजरात में कौन कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी;

(ख) 1967–68 में इस प्रयोजन के लिए गुजरात के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) प्रत्येक योजना के लिये कितनी कितनी राशि नियत की गई है; और

(घ) इस नई कृषि सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत गुजरात के लिये कृषि उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 984/67**]

गुजरात में कृषि योग्य भूमि

5153. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की जाती है;

(ख) गुजरात में कुल कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि ऐसी है, जिसमें गत कई वर्षों से खेती नहीं की गई है; और

(ग) देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए क्या इस कृषि योग्य भूमि में खेती कराने के प्रश्न के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य में 250 लाख एकड़ भूमि में खेती की जा रही है।

(ख) लगभग 25 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) कृषि योग्य भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने की ओर सरकार लगातार प्रयत्नशील है और राज्य की योजना में उपयुक्त स्कीमों को शामिल किया गया है। परन्तु सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण तथा भूमि के क्षारीय होने व समुद्र के जल-प्लावन (जैसाकि कच्छ के रण के काफी भाग में है) आदि के कारण समस्त भूमि को कृषिगत लाना कठिन है।

गुजरात में कृषि के विकास के लिये सहायता

5154. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को 1967–68 में (एक) बागबानी : (दो) पशु-पालन : (तीन) दुग्ध शालाओं : (चार) अधिक अनाज उपजाओं अभियान : और (पांच) मत्स्यपालन के विकास के लिये कोई सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग के काम के लिये पृथक पृथक कितनी कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 1967–68 के लिए गुजरात में कृषि कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित प्लान आउटले योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है :

मुख्य विकास	स्वीकृत आउटले (रुपये लाखों में)
1. कृषि उत्पादन	247
2. लघु सिंचाई	480
3. भूमि संरक्षण	156
4. आयाकट विकास कार्यक्रम	11
5. पशु-पालन	73

6.	डेरी तथा दुग्ध सप्लाई	110
7.	वन	56
8.	मत्स्यपालन	70
9.	मालगोदाम तथा विपणन	20
		1223

बागवानी सम्बन्धी योजनायें विकास शीर्षक कृषि उत्पादन के अन्तर्गत आती है और अधिक अन्न उगाओ अभियान के लिए योजनाएं कृषि उत्पादन तथा लघु सिंचाई शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं।

उपरोक्त प्लान आऊटले के मुकाबले राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं।

गुजरात में चने का अभाव

5155. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में चने का बहुत अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गुजरात की चने की आवश्यकता कितनी है;

(घ) राज्य सरकार को किस किस किस्म के चने की आवश्यकता है; और

(ङ) वर्ष 1967–68 में अब तक उस राज्य को प्रत्येक किस्म का कितना कितना चना भेजा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक राज्य से दूसरे राज्य को चना ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। गुजरात जो अन्य राज्यों से चने का आयात करता था, अब चने की कमी महसूस कर रहा है। भारत सरकार ने अधिक चना उत्पादित राज्यों से कहा है कि वह आवश्यकता से अधिक चने की घोषणा केन्द्र सरकार के पूल को कर दें। इस प्रकार अतिरिक्त घोषित की गई मात्रा को कमी वाले राज्यों में यथा सम्भव समान आधार पर वितरित कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने चालू वर्ष के लिये 1,50,000 टन चना और चने की दाल आलाट करने की मांग की है। उन्होंने किस्म अनुसार विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है।

(ङ) अभी तक गुजरात को 5,000 टन चना अलाट किया जा चुका है।

सरकार द्वारा दी गई राजसहायता की राशि

5156. **श्री सेझियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले दस वर्षों में, वर्षवार, (एक) गेहूं तथा गेहूं से बने पदार्थों और (दो) चावल के आयात अथवा खरीद तथा बिक्री के लिये सरकार ने राजसहायता के रूप में कितनी राशि दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पिछले दस वर्षों में भारत सरकार द्वारा गेहूं और चावल के क्रय और विक्रय के सम्बन्ध में राजसहायता के रूप में दी गई राशि का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 985/67**] गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों के आयात अथवा खरीद तथा बिक्री के लिये सरकार ने इस अवधि में कोई राजसहायता नहीं दी।

व्योम बालाएं (एयर होस्टेस)

5157. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को एयर इण्डिया ने कितनी एयर होस्टेस नियुक्त कर रखी थीं।

(ख) उनके वेतन तथा वेतन-क्रम क्या हैं;

(ग) उन पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है;

(घ) इस पद के लिये एयर होस्टेसों का किस आधार पर चयन किया जाता है;

(ङ) क्या एयरहोस्टसों को नौकरी में रहते हुए विवाह करने की अनुमति है;

(च) क्या सरकार को पता है कि अनेक विदेशी विमान कम्पनियों एयर होस्टेसों को विवाह करने की अब अनुमति देती है; और

(छ) यदि हां, तो इन विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) 159.

(ख) 485-25-560-40-720-50-770/- रुपये और भत्ते।

(ग) 20,40,924/- रुपये।

(घ) इन पदों का विज्ञापन दिया जाता है जिनमें निर्धारित आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख रहता है। इन योग्यताओं में अन्य बातों के साथ साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात् मैट्रीक्यूलेशन या इसके समकक्ष उपाधि, उम्र 19 से 25 वर्ष से बीच, आकर्षक व्यक्तित्व तथा अविवाहित स्थिति इत्यादि बातें सम्मिलित होती हैं। चुनाव एक समिति द्वारा किया जाता है।

(ङ) विमान परिचारिकाओं को इस सेवा में रहते हुए विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(च) और (छ) कुछ विदेशी विमान कम्पनियां विमान परिचारिकाओं को विवाह करने की अनुमति देती हैं । ये अलीटालिया, सावेना, मलयेशियन और सिंगापुर एयरवेज, ब्रिटिश योरोपियन एयरवेज, लुफ्थान्सा, पैन अमेरिकन और ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स हैं । बी० ओ० ए० सी० ग्रीष्म ऋतु में उड़ान ड्यूटी के लिए कभी कभी उन विवाहित विमान परिचारिकाओं को ले लेती हैं जो कि पहले उनकी सेवा में रह चुकी हैं ।

Difficulties in Transport of Foodgrains to M. P.

5158. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to inadequate transport facilities, the monthly ood quota allotted by the Centre to Madhya Pradesh is not reaching that State in time thus causing considerable difficulties to the Government of Madhya Pradesh in distributing food in the various areas; and

(b) if so, the steps being taken to remove these transport difficulties ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development of and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

असैनिक उड्डयन का विकास

5159. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में असैनिक उड्डयन के विकास के उद्देश्य से शौकिया उड़ान करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के हेतु तथा वाणिज्यिक विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) भारत में फ्लाइंग क्लबों को प्रति उड़ान घंटा किस दर से राजसहायता दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों में प्रति उड़ान घंटे की राजसहायता दर में कोई वृद्धि की है क्योंकि तेल, ईंधन और पुर्जों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1963 तक, इलाहाबाद में एक नागर विमान प्रशिक्षण स्कूल काम करता था । आपात स्थिति के कारण इस स्कूल के बन्द किये जाने पर विमान-चालकों को वाणिज्यिक विमान-चालक लाइसेंस के स्तर तक प्रशिक्षण देने के लिए दो तदर्थ योजनाएं गठित की गयीं । वाणिज्यिक विमान चालकों को प्रशिक्षण के लिए नियमित प्रशिक्षण स्कूल के बारे में प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

शौकिया उड़ान करने वाले लोग फ्लाइंग क्लबों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं जो कि इस समय समस्त देश में 21 हैं। इन फ्लाइंग क्लबों को भारत सरकार द्वारा उपदान दिया जाता है।

(ख) भारत में फ्लाइंग क्लबों को दिये जाने वाले नियत उपदान और उड़ान के लिए आर्थिक सहायता की विद्यमान दरें परिशिष्ट 'क' में दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 986/67]** ये दरें 1.3.1963 से आरंभ की गयीं।

(ग) नियत उपदान और उड़ान के लिए आर्थिक सहायता की दरें जो 1 मार्च, 1963 से पहले लागू थीं, परिशिष्ट 'ख' में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 986/67]** जिनसे यह मालूम हो जाता है कि सरकार ने 1 मार्च, 1963 से उपदान और आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। आगे पेट्रोल, तेल इत्यादि की बढ़ी हुई लागत की क्षति पूर्ति के लिए 4.25 रुपये प्रति घन्टे की एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उसी तारीख को मंजूर की गयी है।

खम्भात पत्तन

5160. श्री रा० की० अमीन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात (गुजरात राज्य) पत्तन के विकास के काम पर गुजरात राज्य की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है; और

(ख) क्या किसी गैर सरकारी उपक्रम को इस पत्तन का विकास करने की अनुमति देने का राज्य सरकार का अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तन विधान की संवर्ती सूची के आते हैं। उनके विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि तीसरी योजना काल में खंभात पत्तन के विकास पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया। दूसरी योजना काल में राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्माण कार्य किये :—

(1)	जेट्टी की विशेष मरम्मत	80988 रुपये
(2)	अवतरण सुविधाओं का सुधार	503530 रुपये

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव निलंबित नहीं है। राज्य सरकार से मालूम हुआ है कि एक गैर सरकारी फर्म इस पत्तन का विकास करने की अनुमति लेने उसके पास आई। खंभात की खाड़ी में बहुत कीचड़ जम गया था और 1966-67 में पत्तन पर यातायात घटकर शून्य तक आ गया था। अतः राज्य सरकार ने फर्म को सूचित किया कि पत्तन को विकसित करने की अनुमति देने के प्रश्न पर नवीनतम जलीय सर्वेक्षण के परिणामों आधार पर पत्तन के विकास की संभावना के स्थापित होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। अभी तक इस सर्वेक्षण का करना संभव नहीं हुआ है।

खम्भात पत्तन

5161. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ोदा और खम्भात के बीच के क्षेत्र में पैट्रो–रसायन उद्योगों के बड़े पैमाने पर विकास योजना को ध्यान में रखते हुये खम्भात पत्तन का शीघ्र ही एक मध्य–वर्ती पत्तन के रूप में विकास करने की आवश्यकता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन के विकास के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) कैंबे पत्तन जो बड़ा पत्तन नहीं है, के विकास करने का क्रियान्वयन दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है कि कैंबे को अन्तर पत्तन के रूप में विकसित करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कैंबे में पत्तन सुविधाओं के विकास से बड़ौदा रिफाइनरी के सन्निकट पैट्रो केमिकल संयंत्रों को सुविधा होगी। किन्तु पत्तन के विकास की सीमा और संभावना कैंबे की खाड़ी की मौजूदा नौदशाओं को नया जलीय सर्वेक्षण करने के बाद ही निश्चित की जा सकती है। खाड़ी में अत्यधिक बालू जमा होने के कारण यह जरूरी है। अभी तक कैंबे की खाड़ी में भावनगर और दहेज पत्तनों के पहुंच मार्गों के पुर्नसर्वेक्षण किये गये हैं। कैंबे पत्तन के पहुँच मार्गों का पुर्नसर्वेक्षण करना है।

उत्तरी गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय

5162. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहब शिन्दे) : (क) उत्तर गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित जांच हेतु उत्तर गुजरात शिक्षा समिति से हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार गुजरात राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पक्ष में है और गुजरात सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय होने पर आवश्यक कदम उठायेगी।

गोवा में सहकारी समितियां

5163. **श्री शिकरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में सहकारी समितयों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, उनकी पूंजी कितनी हैं तथा उनके कुल सदस्य कितने हैं;

(ख) कितनी समितियों ने मुनाफा कमाया है तथा कितना कितना;

(ग) समिति के सदस्यों को उनके अंशों पर लाभांश के रूप में कुल कितना धन दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ समितियों को बहुत घाटा हुआ है तथा उनमें से कुछ समितियों में गबन, धोखादेही तथा अन्य कदाचारों के अनेक मामले पकड़े गये हैं;

(ङ) क्या सरकार गोआ की समितियों के कार्य संचालन से समूचे तोर पर संतुष्ट हैं; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या सरकार स्थानीय सरकार को सहायता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि वह सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में प्रगति कर सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ में 'खार' भूमि में खेती

5164. श्री शिंकरे : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में बहुत बड़ी 'खार' भूमि है जिसमें धान की खेती की जा सकती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि स्थानीय सरकार के पास सीमित संसाधन होने के कारण वह इस 'खार' भूमि में खेती करने की आवश्यक योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय सरकार को पर्याप्त धन तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने का है ताकि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अन्नासाहब शिन्दे**) : (क) जी हां। खार भूमि में बड़े क्षेत्रों में पहले ही धान की खेती की जा रही है। इस भूमि को खेती योग्य बनाया जा रहा है।

(ख) प्रशासन से ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तीसरी योजना में धान की खेती के लिए लगभग 16,500 एकड़ खार तथा खजन भूमि की सुरक्षा हेतु 32 लाख रुपयों का उपयोग किया गया था। चौथी योजना के लिए कार्यक्रम तीसरी योजना के कार्यक्रम की अपेक्षा काफी बड़ा होगा।

गोआ में 'खजान' भूमि में खेती

5165. **श्री शिंकरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में 'खजान' भूमि उसकी मिट्टी कछारी होने के कारण बहुत उपजाऊ है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि स्थानीय सरकार ने उसके पास सीमित राशि होने के कारण दो फसलें उगवाने के लिए योजनायें तैयार की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय सरकार के लिए धनराशि नियत करने का है ताकि वह 'खजान' भूमि में खेती करा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशासन से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) तीसरी योजना की अवधि में धान की खेती के लिए लगभग 16500 एकड़ खजान व खेर भूमि की रक्षा के लिए 32 लाख से अधिक रुपया व्यय किया गया । चतुर्थ योजना का कार्यक्रम तीसरी योजना से काफी अधिक होने की सम्भावना है ।

Short and Mid-Term Agricultural Loans for M P.

5166. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of short-term and mid-term agriculture loan allocated to Madhya Pradesh for 1967-68 ?

The Ministbr of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : So far as cooperative credit is concerned, there is no question of 'allocation' to any State. Targets are prescribed and necessary resources are mobilised from the 'own' funds of Cooperatives, reinforced by assistance from the Reserve Bank subject to the prescribed standards of eligibility for credit limits. According to these targets, the cooperative credit institutations in Madhya Pradesh are likely to have the following loaning programme for agriculture production during 1967-68.

Short term	Rs. 32 crores.
Medium Term	Rs. 8 crores.
Total	Rs. 40 crores.

Further, to provide short-term accommodation for the parchase and distrbution of fertilisers, seed and pesticides, the Central Governmont have in the current year sanctioned Rs. 208 lakhs to Madhya Pradesh.

विदेशी पर्यटक

5167. **श्री यशपाल सिंह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'वैल हील्ड' पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अमरीका के राजदूत द्वारा सुझाये गये 'तीन उपायों' जो कि अप्रैल, 1967 में किसी समय 'अमरीकन रिपोर्टर' में छपे थे, की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तुत दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता के विषय में सरकार सदा सचेत रही है तथा वास्तव में जहां तक संभव हो सका है इस प्रकार के उपाय करती ही रही है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा विदेशों में पर्यटन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने एवं इस देश में भी पर्यटन के विकास एवं प्रोत्साहन के जोरदार प्रयत्न किये जाते रहे हैं। ये प्रयत्न पर्यटन संबंधी चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिफलित हुए हैं जो कि पर्यटन के जरिये हमारी विदेशी मुद्रा की आय में तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण में बड़ी सहायक सिद्ध होगी।

भुवनेश्वर हवाई अड्डा

5168. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विस्तार या उसमें कोई सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस विस्तार/सुधार-कार्य पर 1966-67 में कितनी राशि व्यय हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भुवनेश्वर हवाई अड्डे के ऐप्रन और टैक्सी ट्रैक को 13.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चौड़ा करने तथा मजबूत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन के पटला वाटर वर्क्स में मिट्टी निकालने का कार्य

5169. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दत्तात्रेय कुंटे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने पलटा वाटर वर्क्स में मिट्टी निकालने के कार्य के लिये कलकत्ता निगम की योजना पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है मिट्टी निकालने के कार्य के लिये हालैण्ड की कोई फर्म निशुल्क ड्रेजर देने की इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये इस फर्म से बातचीत की गई थी और यदि नहीं तो इस फर्म को इसमें क्या रुचि है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) पलटा में कलकत्ता निगम का वाटरवर्क्स जो कलकत्ते में उपरिधारा में लगभग 20 मील पर स्थित है, कलकत्ता को छने हुये पानी की सप्लाई के लिये हुगली नदी से जल लेता है। यह पानी नदी से पूर्व नियत टंकियों में ले जाया जाता है जहां बालू इत्यादि बैठ जाती है। पूर्व-नियत टंकियों में लगभग 30 मिलियन घन फीट बालू जमा हो गई है। निगम का प्रस्ताव था कि एक वर्ष में 15 मिलियन घन फीट बालू हटाने के लिये एक ठेकेदार लगा लिया जाये जो एक द्रविक निष्कर्ष से नदी के अन्दर से 15 से 20 प्र० श० बालू का घोल निकाल सके। कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स ने इस पर आपत्ति की क्योंकि इससे नदी में भारी बालू जमा हो जायेगी जबकि नदी को नौचालन योग्य रखने के लिये विस्तृत निकर्षण की आवश्यकता है। इस आपत्ति को एक तकनीकी सलाहकार समिति ने भी मान लिया जिसमें कलकत्ता मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई अथारिटी के निदेशक, मुख्य इंजीनियर कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर, मुख्य इंजीनियर कलकत्ता निगम, और पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई तथा जलमार्ग निदेशालय के मुख्य इंजीनियर थे।

(ग) और (घ) मार्च, 1967 में निगम को एक डच कम्पनी ने इस प्रयोजन के लिये नि:शुल्क सहायक उपस्कर सहित एक निकर्षक सप्लाई करने का आफर किया था। इसमें शर्त यह थी कि निगम को बगैर प्रभार के बिजली सप्लाई करनी होगी। किन्तु मई, 1967 में यह आफर वापस ले लिया गया। इस आफर को करने में फर्म का हित क्या था यह नहीं मालूम है।

देश की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता

5170. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को दिन में केवल एक बार भोजन मिलता है, अन्य 12 करोड़ 50 लाख लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन एक समय का भोजन नहीं मिलता है तथा जन संख्या के लगभग 35 प्रतिशत लोगों को आवश्यकता से कम पोषक तत्वों वाला भोजन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक नागरिक के लिये पेट भर भोजन की व्यवस्था करने के हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण केवल विभिन्न आय के वर्गों के लोगों द्वारा गेहूँ से बने और अन्य खाद्य और अखाद्य वस्तुओं पर व्यय किये गये खर्चों के आंकड़े देता है। इन आंकड़ों में कटौती का सुझाव अवश्य ही किसी धारणा पर आधारित हो सकता है जिसकी सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और विदेशों से यथा सम्भव अनाज का आयात कर आन्तरिक उत्पादन में सहायता के सब उपाय कर रही है।

Supply of Gram for Cattle in Delhi

5171. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the arrangements made by Government to provide grams at a cheap rate to the dairy-owners for their cattle and horses in Delhi.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : No arrangement has been made to provide gram at a cheap rate to the dairy owners and tonga drivers. Instructions are there to the wholesale foodgrains licensed dealers in Delhi to issue up to 50 bags of gram in a day to the 'Dana' (feed for cattle and horses) manufacturers. The dana manufacturers have also instructions to sell dana after adding to their purchase price a margin fixed by the Delhi Administration on account of conversion charges and profit. Some difficulty has arisen of late regarding movement of gram from Haryana to Delhi and the matter is being looked into.

दिल्ली में सूजी और मैदे का वितरण

5172. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सूजी और मैदे का वितरण भारत का खाद्य निगम करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों को विवाह आदि के लिये मैदे और सूजी का परमिट लेने के लिये नई दिल्ली में हार्डिंग ब्रिज पर स्थित इस निगम के कार्यालय में जाना पड़ता है;

(ग) इन वस्तुओं के वितरण का काम दिल्ली प्रशासन से ले लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इसके बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां; लेकिन 12 जुलाई, 1967 से दिल्ली में मैदे और सूजी पर राशन कर दिया जायेगा और उसी दिन से ही राशनिंग प्राधिकारियों को मैदे और सूजी के परमिट दिये जायेंगे।

(ग) चूंकि दिल्ली में 27 जुलाई, 1966 से सूजी और मैदे पर से राशन हटा लिया गया था, दिल्ली प्रशासन के राशन विभाग द्वारा इनके वितरण पर नियंत्रण करने का दायित्व समाप्त हो गया। खाद्य निगम ने दिल्ली में 1 जुलाई, 66 से आटा मिलों को आटे से बने उत्पाद बनाने के लिये मिल की पीसने की दरों पर, आयातित गेहूँ को सप्लाई करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

(घ) जी, नहीं।

हरयाना को गेहूँ की सप्लाई

5173. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में हरियाना सरकार को कितना आयातित गेहूँ दिया गया; और

(ख) वर्ष 1967-68 में कितनी मात्रा में गेहू दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) लगभग 30,000 हजार टन।

(ख) इस समय यह बतलाना कठिन है कि 1967-68 के दौरान हरियाना को कितनी मात्रा में आयातित गेहूँ सप्लाई किया जायेगा।

Bridge on Gandak River

5174. Shri Bibhuti Misra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work on the construction of the bridge on the Gandak river at Dumariaghat (Bihar) on the National Highway is behind the Schedule; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Minister of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) ; (a) and (b) The construaction of the guide bunds and other protective works to the bridge is practically complete and the progress on the same its satisfactory.

In the case of the bridge proper, the progress is not satisfactory. The reasons for the slow progress are the difficulties encountered during the sinking of wells due to hard strata and to lack of adequate sinking equipment with the firm at site.

Acts and Laws

5175. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N Tiwary :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact a number of Acts have been made by the Central Government since the Independence :

(b) if so, whetl er it is also a fact that pleaders are finding it difficult to make use of such a large number of Acts and Laws in Law Courts; and

(c) if so, whether Government are considering to bring forward a consolidated legislation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) It is not a fact that any Acts have been made by the **Central Government** since Independence; but it is a fact that a number of Acts have been passed by **Parliament** since than.

(b) Even on the assumption that the number of Acts passed by Parliament since Independence is large, the Central Government is not aware that pleaders are finding it difficult to make use of the large number of Acts and Laws in Law courts.

(c) Does not arise.

बम्बई के नाविक

5176. श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाहों के नाविकों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए 5 अप्रैल, 1967 को नौवहन महानिदेशक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था :

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) कुछ नाविकों ने 4 अप्रैल 1967 को नौवहन महानिदेशालय बम्बई के सम्मुख प्रदर्शन किया था। भारत की नेशनल यूनिअन आफ सीफेयरर द्वारा निम्न मांगे पेश की गई है–

(1) मौजूदा सरकारी डाक्टरी परीक्षा बन्द की जानी चाहिये।

(2) विदेश जाने वाले क्षेत्र के केवल नये भरती किये जाने वालों को डाक्टरी परीक्षा के लिए मेडीकल आफिसर, सीमैन मेडिकल इक्सामिनेशन आरगेनाइजेशन, के पास भेजा जाना चाहिये। नये भरती किये जाने वालों की एक बार परीक्षा के बाद यदि वे फिट घोषित कर दिये जायें तो उन्हे मेडिकल आफिसर, एम० ई० ओ के पास नियतकालिक परीक्षा के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये।

(3) डाक्टरी परीक्षा केवल कम्पनी में मेडिकल आफिसर द्वारा की जानी चाहिये। यदि कम्पनी के मेडिकल अफसर की राय के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो यूनीअन तुरन्त समझौते के लिये कम्पनी से बातचीत करेगी और यदि यूनीयन की इच्छा होगी तो नाविक की डाक्टरी परीक्षा कम्पनी तथा यूनियन द्वारा स्वीकृत डाक्टर द्वारा की जायेगी और उसका निर्णय दोनों दलों को मान्य होगा।

(4) डाक्टरी परीक्षा और चेकअप की पद्धति को केन्द्रीकृत करना और इस तरह चलाना चाहिये कि यदि जांच में स्वयं अधिक समय लगे तब तो और बात है अन्यथा जांच दो दिनों में समाप्त हो जानी चाहिये ।

(5) इम्पलायीजस्टेटे इंश्योरेंस स्कीम की लाइन पर एक हेल्थ इंश्योरेन्स स्कीम होनी चाहिये इसके अन्तर्गत नाविक की बेरोजगारी की हालत में उसे और उसके परिवार को मुफ्त डाक्टरी इलाज उपलब्ध होना चाहिये ।

(6) अस्थायी अयोग्यता तथा जांच और चेक अप के समय में नाविकों को मुफ्त डाक्टरी इलाज और आधी मजदूरी मिलनी चाहिये ।

(7) यदि कोई नाविक समुद्र में कार्य करने के लिये स्थायी तौर से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तब उपरोक्त उल्लिखित हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत सेवा पर निर्भर रहते हुये उसे पर्याप्त एक मुश्तराशि की अदायगी की जानी चाहिये ।

(8) उन नाविकों के पुर्नवास के लिए जो स्थाई तौर से समुद्र यात्रा के कार्य के लिये स्थायी तौर से बेकार घोषित कर दिये गये हैं सरकार को तटीय संस्थानों में नौकरी की व्यवस्था, व्यवसायक प्रशिक्षण इत्यादि के लिये सुविधायें, इत्यादि, देने के उपाय करने चाहिये ।

भारत की नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर, नौवहन महानिदेशालय के अधिकारियों, और सीमैन मेडिकल इक्सामिनेशन आरगोनाइजेशन प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप कुछ प्रस्ताव बनाये गये हैं । ये प्रस्ताव पोत मालिकों और नाविकों के विभिन्न संगठनों को विचारार्थ भेजे गये हैं । उनकी राय जान लेने के बाद उसके सब पहलुओं में मामले पर निर्णय करना संभव हो सकेगा ।

द्वि विवाह निरोध कानून

5177. बाबूराव पटेल : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि द्वि-विवाह निरोध कानून के कारण, जो केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है, अधिकाधिक हिन्दू इस उद्देश्य से इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे हैं, ताकि वे बहुपत्नीक विवाह का लाभ उठा सकें, जिसकी इस्लाम अनुमति देता है ; और

(ख) यदि, हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

5178. श्री प्रकारवीर शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों का कुछ भाग स्वयं सेवी ईसाई संस्थाओं को भी दिया जाता है ;

(ख) क्या पी० एल० 480 की शर्तों में इसका कोई उपबन्ध है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ईसाई संस्थायें इन खाद्यान्नों का उपयोग धर्म परिवर्तन करने के लिए कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ।

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों में से स्वयंसेवी ईसाई संस्थाओं को कुछ भी नहीं दिया जाता । ऐसी कुछ संस्थाए अपने आहार कार्यक्रम के लिए पी० एल०. 480 के अन्तर्गत स्वयं खाद्यान्नों का आयात कर रही हैं ।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में लोक सभा में गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा 14 जून, 67 को तारांकित प्रश्न संख्या 481 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

गोदामों की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण फलों की क्षति

5179. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री काशीनाथ पान्डे :
श्री मीठा लाल : श्री राने :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण 10 लाख मीट्रिक टन फलों का नुकसान हो जाता है ; और

(ख) इस क्षति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) ऐसा अनुमान है कि देश में उत्पन्न होने वाले फलों में से लगभग 15–25% फल खराब हो जाने या अन्य कारणों से उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में यह शामिल है :–

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौराना सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में शीतागार का विकास किया जाना ।

(2) शीघ्र बिगड़ने वाले फलों और सब्जियों को आरक्षित रखने और इस प्रकार तैयार और आरक्षित रखे गये खाद्यानों के उपभोग को बढाने के उद्देश्य से फलों को आरक्षित रखने और सामुदायिक केनिंग सेन्टर की स्थापना करना ।

(3) पहले पैकिंग तथा अन्य आवश्यक चीजें करना ताकि यातायात और सामान को रखने और उठाने के दौरान खराबी की सम्भावना को कम किया जा सके।

(4) फलों पर मोम-एमूलसन का प्रयोग किया जाना ताकि उन्हें अधिक समय बिना बिगड़े रखा जा सके।

(5) निर्जलीकृत तरीके से फलों को सुरक्षित रखने को प्रोत्साहन देना।

1955 का फल उत्पाद आदेश फलों और सब्जियों के निर्जलीकरण और किस्मों पर नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया है। 1964 का शीतगार आदेश भी शीघ्र बिगड़ने वाले खाद्यान्नों की स्टोर की स्थिति में सुधार करने के लिए लागू किया गया है।

मोटल

5180. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में मोटल स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास की जो कि एक सरकारी क्षेत्र का व्यवसाय है, राष्ट्रीय मुख्य मांगों पर मोहलों के बनाने की योजनाएं हैं। पहले दिल्ली बम्बई मार्ग को लिया जायगा। व्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

चावल की अधिक उपज वाली नई किस्म

5181. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लास बोनस, फिलिपीन में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसन्धान संस्था द्वारा चावल की अधिक उपज के लिए प्रसिद्ध चावल की नयी किस्म, जिसे वैज्ञानिक रूप में आई० आर० 8-293-3 कहा जाता है, कि खोज की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या इस किस्म का भारत में उत्पादन करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) सम्भवतः आदरणीय सदस्य का अभिप्राय फिलपाइन में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसन्धान में तैयार हुई धान की आई० आर० 5288-3 किस्म से हैं। सेन्ट्रल

वैरायटी रिलीज़ कमेटी अपनी दिसम्बर 1966 की बैठक में इस किस्म को पहले ही स्वीकार कर चुकी है और इसे 'आई आर एस' नाम दिया गया है। इस किस्म को निम्न क्षेत्रों में बोने की सिफारिश की गई है :–

(अ) एक फसली क्षेत्र जहां जल संभरण की समुचित व्यवस्था है :

1–पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश

2–पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार

3–आसाम

4–पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा

5–मध्य प्रदेश

(ब) बहुगुणी सस्य क्षेत्र :

1–आन्ध्र प्रदेश के तट्टीय क्षेत्र में पहली फसल

2–मद्रास राज्य के थन्जाबर डेल्टा में दूसरी फसल

3--मैसूर तथा केरल में पहली फसल

पिछली रबी-ग्रीष्म मौसम में यह फसल देश के कुछ भागों में उगाई गई थी। वर्त्तमान खरीफ के मौसम में इस किस्म के अन्तर्गत काफी क्षेत्र आ जाने की सम्भावना है।

चीनी का निर्यात

5182. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अगाड़ी :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात के लिये विदेशों के साथ करार किये हैं; और

(ख) यदि हां; तो उनका मोटा ब्यौरा क्या है और उनसे कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) कलकत्ते की इण्डियन शूगर मिल्स ऐसोसियेशन ने केन्द्र सरकार की अनुमति से 2.18 लाख टन चीनी निर्यात करने का ठेका लिया है;

देश	मात्रा (लाख टनों में)
अमरीका	0.69
ब्रिटेन	0.78
कनाडा	0.71
कुल जोड़	2.18

(ख) निर्धारित समय में न्यूयार्क काफी और सूगर एक्सचेंज इन कार्पोरेशन द्वारा ठेका नम्बर 10 की उसी स्थान पर दी गई औसत दरों के आधार पर अमरीका को निर्यात किया जायेगा। राष्ट्रमंडल चीनी समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन को 0.25 लाख टन का निर्यात नये दर पर किया जायेगा, जो 47.50 पोण्ड प्रति बड़ा टन है। ब्रिटेन को बकाया निर्यात करने वाला माल को तोलकर लन्दन के दैनिक मूल्य पर प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। जो माल कनाडा को निर्यात होगा उसकी भी कीमत निर्धारण का कार्य लन्दन के दैनिक मूल्यों के आधार पर ही होगा। मगर विशेषकाल और प्राथमिकता के साथ उसको सम्बद्ध कर दिया जायेगा। विभिन्न समयों में जो मूल्य होंगे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भावों में चीनी बिक सकेगी उसके आधार पर ही विदेशी मुद्रा का अर्जन निर्भर करना है।

उत्तर प्रदेश में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिये केन्द्रीय सहायता

5183. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) वर्ष 1966-67 में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, नैनीताल, (उत्तर प्रदेश) को किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) क्या उस विश्वविद्यालय ने उपरोक्त अवधि में इस राशि का पूर्ण उपयोग किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 के दौरान उत्तर प्रदेश में यू० पी० कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर को 22,04,000 रुपये का नकद अनुदान दिया गया। यह राशि गर्ल्ज होस्टल, स्कैडेमिक स्टाफ के लिए स्टाफ क्वाटर्स, हैल्थ सैन्टर. उपकरण तथा पुस्तकों जैसे विकास कार्यों के लिए केन्द्र के भाग के रूप में दी गई। इस अनुदान के अतिरिक्त 9,757 रुपये की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई। यह राशि 1-1-65 से 31-3-66 तक यू० पी० कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में टीचिंग स्टाफ के लिए युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की तीसरी योजना वेतनमान को अपनाने पर जो वास्तविक अतिरिक्त खर्च हुआ उसके लिए केन्द्र द्वारा दी गई।

(ख) यू० पी० कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर से जानकारी की प्रतिरक्षा की जा रही है।

कीटनाशक औषधियां

5184. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में जोती गई कुल भूमि में से कितने प्रतिशत एकड़ भूमि पर गत वर्ष विभिन्न फसलों के सरक्षणार्थ कीटनाशक औषधियां छिड़की गई; और

(ख) उक्त अवधि में कीटनाशक औषधियों का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अनुमान है 1966-67 में 590 लाख एकड़ भूमि में पोद रक्षा संबंधी कार्य हुआ। 1966-67 के कृषिगत क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु 1964-65 में कुल मिलाकर 3900 लाख एकड़ क्षेत्र कृषिगत था।

(ख) वर्ष के दौरान में विभिन्न प्रकार के टेक्निकल ग्रेडों व रेडी ट्यूज किस्म की 4,400 मीटरी टन कीटनाशक औषधियां आयात की गई।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं

5185. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं 16 मई, 1967 को कलकत्ता में देरी से चली; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की माँगें क्या थी तथा उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्यन मंत्री (डा० कर्णसिंह): (क) और (ख) कुछ स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य इंजीनियर द्वारा कलकत्ते में 16 मई, 1967 को बुलाई गई बैठक को कुछ सदस्यों के उच्छृंखल व्यवहार के कारण स्थगित करना पड़ा। बैठक के स्थगित करने को यूनियन ने गलत समझा और उसने अपने कुछ सदस्यों को पड़ताल करने की सलाह दे दी। इससे काम बन्द होने के कारण 17 तारीख की सुबह कलकत्ते से होकर जाने वाली कुछ सेवाओं में देरी हो गई। स्थगित की गई बैठक को मुख्य इंजीनियर द्वारा 18 मई, 1967 को करने का आश्वासन दिये जाने के बाद हड़ताल 17 तारीख को समाप्त हो गयी।

सहकारी चीनी मिल बटाला

5186. श्री अनिरुधन : **श्री अब्राहम :**
श्री उमानाथ : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री एस्योस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य के सहकारी चीनी मिल, बटाला में हुए भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस मामले की जांच अधिकारियों द्वारा की गई है;

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने महा प्रबंधक (जनरल मैनेजर) के तबादले की सिफारिश की है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० के कुप्रबन्धक के बारे में तथा मिल के महा प्रबन्धक के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाए गये थे। यह शिकायत भूतपूर्व पंजाब सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए जनवरी, 1966 में भेजी गई थी।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले की जांच नहीं की है; अतः उनके द्वारा महा प्रबन्धक के स्थानान्तरण की सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तथा उर्वरकों के लिये राजसहायता

5187. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1967 को पूरा होने वाले वर्ष में प्रत्येक राज्य को उर्वरकों के लिये कितनी कितनी राज सहायता दी गई; और

(ख) क्या खाद्य तथा उर्वरक के लिये दी गई राज सहायता का खाद्यान्नों के मूल्य तथा उत्पादन पर हुए प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : रुपये के अवमूल्यन से आयातित उर्वरकों तथा उर्वरक कच्ची सामग्री की लाने ले जाने की लागत में 57.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। फिर भी पूल उर्वरकों के मूल्यों को 1966-67 में उपयुक्त राज सहायता देकर पूर्व-अवमूल्यन स्तरों पर ही रखा गया। केन्द्रीय सरकार ने राज सहायता सीधी उन देशीय निर्माताओं को दी जो देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि को सीमित करने के लिए आयातित कच्ची सामग्री को प्रयोग में लाते हैं। इन राज सहायताओं का केन्द्रीय बजट पर प्रभाव पड़ा और राज्यों को कोई अदायगी करने का प्रश्न ही नहीं हुआ।

राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित राज्य सहायता योजनाएं शुरू की गई-विचार विमर्श किया। आयोग ने अनुभव किया कि राज सहायता वापिस लेने के बाद उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि से उर्वरकों के इस्तेमाल और कृषि उत्पादन को तीव्र करने वाले कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने चाहिए। अतः आयोग राज सहायता को धीरे-धीरे वापिस लेने के हक में है।

उत्पादन की लागतों में सभी प्रकार की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए आयोग कृषि उत्पाद के मूल्यों पर सिफारिश करता है ।

सहाय्य दरों पर खाद्यान्नों को देने का अभिप्राय खाद्यान्नों के बाजार भावों को स्थिर करना और जनता की आवश्यकताओं को जुटाना हैं ।

Tourist Centres in M. P.

5188. Shri G. C. Dixit :
Shri Nitiraj Singh Choudhary :
Shri G. S. Mishra :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent by the Central and the State Governments for encouraging tourist traffic to places of tourist interest in Madhya Pradesh during the last five years ; and

(b) the steps taken to attract the tourists to places of architectural beauty and and historical record in Madhya Pradesh during the current year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation Dr. Karan Singh) : (a) The total expenditure incurred on developing tourist facilities in Madhya Pradesh in the last five years was Rs. 8,68,501 inclusive of the amount spent by the State Government.

(b) Plans are in hand for the integrated development of tourist facilities at Khajuraho, the development of Shivpuri and the development of the Kanha-Kisli-Jabalpur Complex.

Smuggling of Grams From Rajasthan

5189. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Autar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Policemen posted at the border are co-operating in the smuggling of grams in the villages of Rajsthan ;

(b) whether Government have received some complaints also in this regard ; and

(c) if so, the steps taken by Government to check smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) : (a) and (b) Complaints were received in respect of two districts.

(c) Police Officials concerned have been suspended. Strict watch is being kept by frequent raids and change of staff.

हवाई अड्डों का निर्माण

5190. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों के डिजायन तैयार करने, उन्हें बनाने तथा उनके पुर्ननवीकरण के मामले में भारत को अब भी विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये अपने वास्तविकों को प्रशिक्षित करने के सबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि हम किसी पर आश्रित नहीं है फिर भी यह सही है कि भारतीय वास्तुशिल्पियों को हवाई अड्डा टर्मीनलों के डिजाइन तैयार करने के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये कुछ वास्तु-शिल्पियों को विदेश भेजना आवश्यक है ताकि वे इस क्षेत्र में हुए नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय विकास का लाभ उठा सकें।

Grant to M. P. for Grow More Food Campaign

5191. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grant actually paid to the Madhya Pradesh State for Grow More Food Campaign during 1966-67 ; and

(b) the amount proposed to be given to this State for the said purpose during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Grant given to the State for the Grow More food Campaign is covered under the Heads of Development (i) Agricultural producation (including Land Development) and (ii) Minor Irrigation. A sum of Rs. 232.93 lakhs was sanctioned as grant to the Government of Madhya Pradesh duridg 1966-67 for the implementation of schemes under these two Heads of Development.

(b) The amount of Central financial assistance to be allocated to the State Government for individual Heads of Development during 1967-68 has not been finalised so far.

त्रिवेन्द्रम और कोलम्बो के बीच विमान सेवाएं

5192. **श्री चक्रपाणी** : **श्री नायनार** :
श्री प० गोपालन : **श्री नम्बियार** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम और कोलम्बो के बीच हवाई सेवा चालू करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डय मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। इंडियन एयर-लाइन्स की त्रिवेन्द्रम से कोलम्बो के लिए अगस्त, 1967 से सप्ताह में एक बार की विमान सेवा चलाने की योजना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम अवाई अड्डा

5193. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नम्बियार :**
श्री नायनार :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर स्थित सीमा शुल्क कार्यालय घास फूंस की एक झोंपड़ी में है; और

(ख) यदि हां, तो इस सीमा शुल्क कार्यालय के लिए एक इमारत की व्यवस्था करने संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक अस्थायी प्रबन्ध है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर स्थित इमारत में सीमा शुल्क कार्यालय के लिये स्थान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वर्धन व परिवर्तन करने का विचार है।

कोचीन हवाई अड्डा

5194, **श्री नम्बियार :** **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नायनार :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने कोचीन में एक पृथक असैनिक हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस प्रयोजन के लिए वर्ष 1966 में संबंधित अधिकारियों ने कई स्थानों का निरीक्षण किया था;

(ग) क्या कोई स्थल चुना गया है; और

(घ) क्या इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। नागर विमानन विभाग एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) इडाक्ट् दुवयाल में एक स्थान अन्तिम रूप से चुना गया है। सर्वेक्षण के व्यौरे की जांच की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

Revenue Collection by Panchayats

5195. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the States where a decisison to entrust the work of revenue Collection to the Panchayats has been taken;

(b) Whether the Central Government have issued some directive to State Governments in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The information is being Collected from the States and will be laid on the Table of the House in due Course.

(b) No, Sir.

(c) Dose not arise.

केन्द्रीय सहकारी बैंको को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण

5196. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रिजर्व बैंक केन्द्रीय सहकारी बेंकों को कुओं के खोदने तथा पम्पिंग उपकरणों के खरीदने के लिये ऋण नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) रिजर्व बैंक किन कारणों से इस बात के लिये बाध्य करता है कि मध्यम तथा अल्प कालीन ऋणों के बीच दो और एक का अनुमान होना चाहिये; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) भारत का रिजर्व बैंक सहकारी बेंकों के साधनों की अनुपूर्ति काश्तकारों को उन कृषि प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन ऋण देने के लिए करता है जो 3 से 5 वर्षों के मध्यकालीन ऋण से चलाए जा सकते हैं। भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त धन कुएं खोदने तथा पम्पिंग उपकरण खरीदने हेतु ऋण देने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि काश्तकार ऋणों को 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर लौटाने की आवश्यक क्षमता रखते हों।

(ग) इस प्रकार का कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Publications of Law Journals

5197. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Miniser of Law be pleased to State :

(a) the Languages in the Eight Schedule of the Constitution in which Law Journals are Published at present and their names and places of Publication;

(b) in case any of them is given financial assistance by the Government of India, the quantum of such assistance; and

(c) Whether similar Journals are being published of proposed to be pubiished by the Government ?

The Deputy Minister in the Minstry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The Minister of Law has no Information in the matter;

(b) Does not arise;

(c) The Government of India are considering the feasibility of publishing a Monthly Law Journal in Hindi which will contain Hindi versions of Important Judgments of the Supreme Court and the High Courts.

भारत के लिये खाद्य प्रतिष्ठान, नीदरलैण्ड (फूड फार इंडिया फाउंडेशन)

5198. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणि :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिये खाद्य प्रतिष्ठान नामक संगठन नीदरलैण्ड में स्थापित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिष्ठान कब स्थापित किया गया था और इस संगठन के प्रवर्तक कौन हैं;

(ग) क्या इस संगठन द्वारा सहायता मांगते समय की गई अपील की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 28 मार्च, 1966 को यह स्थापित किया गया था। निम्नलिखित इस संगठन के प्रवर्तक हैं :-

1. दी कैथोलिक नैशनल फाउन्डेशन फर, स्पैशल नीड्स एण्ड केयर फार रिफ्यूजीज "पीपल इन डिस्ट्रैस", नीदरलैण्ड।

2. दी नीदरलैण्ड्ज यूनीसैफ कमेटी इन हेग, नीदरलैण्ड्ज ।

3. दी नीदरलैण्ड्ज आर्गेनाइजेशन फार इंटरनैशनल एसिस्टैन्स, नौविब, हेग, नीदरलैण्ज ,

4, दी कमेटी आफ इंटरचर्च एड एण्ड सर्विस टू रिफ्यूजीज, अतरैचट, नीदरलैण्ड्स

5. यूनेस्को सैन्टर इन दी नीदरलैण्ड्स, अमसटरडम, नीदरलैण्ड ।

(ग) और (घ) सहायता सम्बन्धी अभियान का उद्घाटन करते समय नीदरलैण्ड के भूतपूर्व प्रधान–मन्त्री डा० डब्लू ड्रैस की अपील का एक अंश सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 987/67]**

संगठन तथा उसके प्रवर्तकों ने प्रेस में रेडियो तथा टेलिवीजन द्वारा रूपक जारी किए और वे लोगों के पास दान लेने के लिए भी गए ।

Airport at Sanchi

5199. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Tourim and Civil** Aviation be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the U. N. Secretary General had made a suggestion for the construction of an airport at Sanchi when he visited this place during his last visit to India; and

(b) if so, the decisiom taken by Government in the matter with details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Recentls an intimation has been received from the Government of Madhya Pradesh that the Secretary Generel of U. N. had made a suggestion for construction of an airstrip near Sanchi. The economic feasibility of an air-strip at Sanchi is being examined in the light of the fact that there is an air Port at Bhopal which is connected to Sanchi by a 44 miles long metalled road.

Reserve Bank Survey on Rural Indebtedness,

5200. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government are satisfied with the latest survey conducted by the Reserve Bank of India regarding rural indebtedness; and

(b) if so, the special aeatures thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadswamy) : (a) The latest survey conducted by the Reserve Bank of India regarding rural indebtedness is the all India Rural Debt and Investment survey, 1961--62. The processing of the material collected during the survey is still under way by the Reserve Bank of India. A full picture will be available only after data are fully processed and results published. However, on the basis of provisional findings published so far by the Reserve Bank of India the attention of the state Government of

Assam, Bihar, Rajasthan and West Bengal has been drawn to the meagre share of cooperatives in finanching the rural population in the States. Steps are being taken to augment the availability of cooperative credit for agricultural production in the country as a whole.

(b) The survey was designed to yield estimates of debt, borrowings, capital formation etc. in the rural house-hold Sector.

बाड़मेर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़क

5201. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री ओंकार सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़कों के, विशेष रूप में बाड़मेर–शिव–जैसलमेर सड़क के, निर्माण की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रगति को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रगति को ओर आगे बढ़ाने के लिये अतिरिक्त फंड प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Confirmation of Staff in Food and Agriculure Ministry.

5202. Shri Hukam Chand Kachwai : Shri S. S. Kothari ; Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to State :

(a) the number of permanent, temporary and quasipermanent employees at present in all the Departments of his Ministry after decentralization;

(b) the number of persons among the temporary employees who are at present eligible for confirmation and the number of those who have been confirmed so far; and

(c) the reasons for the delay in confirmation of these temporary employees ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (c) the information is being Collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक

5203. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि राय : श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान प्रबन्ध–निदेशक को सेवा की किन शर्तों पर नियुक्त किया गया है; और

(ख) उन्हें प्रशासन और प्रबन्ध का क्या विशेष अनुभव है; और

(ग) क्या उन्हें अब भी अपने पहले नियोजक से प्रति मास बहुत मत्ता मिल रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, जिनकी नियुक्ति 17 अक्टूबर, 66 को की गई थी के सेवा के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :–

(1) 3000–125–3500 के वेतन क्रम में 3500 रुपये मासिक वेतन ।

(2) पदाधिकारी के पद के अनुसार वेतन से 10% प्रतिशत कटौती कर सुसज्जित आवास की व्यवस्था ।

(3) दूसरे भत्ते और सुविधाएं जो निगम नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हों ।

(4) पहले पहल नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है जिसको सरकार की इच्छानुसार दो वर्ष के लिये ओर बढाया जा सकता है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति से पूर्व वे हैदराबाद स्थित मैसर्स बजीर सुल्तान टोबेक्को कं० के अध्यक्ष थे । उन्हें खरीदारी और प्रबन्ध के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हैं । वे 1964 से आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बोर्ड के सदस्य थे । वह आंध्र प्रदेश उत्पादन परिषद् के उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड के सदस्य थे । भारत बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्य करने अलावा उन्होंने ब्रिटेन में हेनले प्रशासनिक स्टाफ कालिज में भी शिक्षा प्राप्त की है वह हैदराबाद के डायरेक्टिंग स्टाफ के स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कालिज आफ इण्डिया के भी सदस्य और हैदराबाद के इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरपरायिजज के मनोनीत फैक्लटी सदस्य थे ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय

5204, श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय : श्री जे० एच० पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के लिये भवन किराये पर लेने के लिये कितना धन दिया गया है और उस भवन का वार्षिक किराया कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल ढाई लाख रुपया दो किश्तों में दिया गया था। डेढ़ लाख रुपये की पहली किश्त किराये के रूप में दी गई थी जो छः महिनों में समायोजित हो जायेगी। दूसरी एक लाख रुपये की किश्त, जिस पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लगता है, और जो तीन समान किश्तों में वापसी योग्य है, भवन में परिवर्तन और सुधार करने के लिये दी गई थी। भवन का वार्षिक किराया 5, 40, 015 रुपये है।

1967–68 में उर्वरक की आवश्यकता

5205. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि 1967–68 में विभिन्न राज्यों को अधिक पैदावार वाले अनाजों की खेती करने के लिये कुल कितने उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के पृथक–पृथक आंकड़े कितने हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यों की मांग पूरी करने के लिये व्यवस्था कर ली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 988/67]**

(ग) जी हां।

Posts Reserved for Sheduled Castes and Scheduled Tribes in F. &. A. Ministry.

5206. Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of **Food and Agricultare** be pleased to state :

(a) the number of Class I. II and III technical and non-technical posts created in his Ministry during the last five years ;

(b) the number of posts resarved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes category-wise ; and

(c) the steps being taken to fill up the reserved posts ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricuture Community Development and cooperation (Shri Annasabib Shinde) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Seizure of Rice by Delhi Police near Gurgaon

5207. **Shir K. M. Madhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the press report appearing in the English daily Statesman dated 18th June, 1967 to the effect that the Delhi Police have seized a truck containing 70 quintals of rice near Gurgaon, is correct ;

(b) whether there is some gang behind such frequent incidents or it is simply a minor incident ; and

(c) if there is some gang behind it, the reasons for Government's failure in detecting it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The information is being collected and will be pleased on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Requirement of Pumping Sets in Bihar

5208. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of pumping sets of 5 to 30 H, P. required for suitable irrigation arrangements in Bihar, for which a survey was conducted by the Central Government sometime ago ;

(b) whether the Government of Bihar have ever drawn the attention of the Central Government to the shortage of such pumping sets in Bihar ; and

(c) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Coopration (Shri Annasahib Sinde) : (a) No detailed survey has been conducted by the Central Government. However, on the basis of the visit of a Central Team to the Bihar State in October, 1966 to study the drought situation and suggest remedial measures, the targets for installation of pump.sets in the State were revised upward as under :—

	Original	**Revised**
Diesel Pump Sets by individual farmers.	1,200	6.000
Electrical pump sets by individual farmers.	6,000	14,000
River pumping stes by Government.	68	700

(b) Yes.

(c) With a view to ensuring the availability of larger number of pump sets, a meeting with indigenous manufacturers of pump sets was arranged by the Government of India. The supply position indicated was satisfactory and the manufacturers were confident to meet the entire demand of Bihar. The State Government was advised to work out its phased requirements accordingly. While the target for smaller H. P. pump sets were substantially exceeded, there has been some short fall in the supply of higher H. P. pump sets required by the State for River pumping Scheme.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिवहन ठेका

5209. श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की केरल क्षेत्रीय शाखा द्वारा परिवहन ठेके दिये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस शिकायत की जांच की है; और

(ग) जांच-निष्कर्ष क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा कालीकट में सफाई तथा कार्य को करने सम्बन्धी ठेके को न स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) पार्टी ने केरल उच्च न्यायालय में रिट पैटिशन दायर किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

देश में मुर्गीपालन केन्द्र

5210, श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने मुर्गीपालन केन्द्र हैं और उनमें प्रतिदिन कितने अंडे पैदा होते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : गैरसरकारी कुक्कुट फार्मों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1965-66 में सरकारी कुक्कुट फार्मों (विस्तार केन्द्रों सहित)की संख्या 405 थी।

प्रतिदिन कितने अण्डों का उत्पादन होता है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों के ठेके

5211. श्री क० लकप्पा :
श्री श्रीधरन :

क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को ठेके देने के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग दर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (ग) खाद्य, निगम अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य देख रेख, प्रबन्ध का कार्य और निगम का व्यापार का भार बोर्ड आफ डायरेक्टर के हाथ में होता है और केन्द्र सरकार निगम को केवल नीति के प्रश्न पर ही अनुदेश दे सकती है ।

मध्य अन्दमान द्वीपसमूह में ग्राम पंचायतों के चुनाव

5212. **श्री गणेश :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य अन्दमान द्वीप समूह में रंगत वार्ड के हाल के ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिये तमिलभाषी लगभग 100 व्यक्तियों के नाम जानबूझ कर पंजीबद्ध नहीं किये गये थे;

(ख) क्या फरवरी, 1967 के संसदीय चुनावों में इन मतदाताओं के नाम उसी बोर्ड में मतदाता सूची में दर्ज थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उपायुक्त को कोई अभ्यावेदन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सीमा सड़क संगठन

5213. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन ने टेन्डर मंगवाये बिना ही जीपें, ट्रक ट्रैक्टर तथा बुलडोजर खरीदे थे,

(ख) क्या ये गाड़ियां राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए ठेकेदारों को किराया-खरीद आधार पर दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि सड़क निर्माण कार्य पिछड़ गया है और क्या इन गाड़ियों का उपयोग ठेकेदारों द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए अन्यत्र किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की केन्द्रीय जांच विभाग को देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राजस्थान में सीमान्त सड़क संगठन ने जीपें, ट्रकें और ट्रैक्टर खरीदे थे किन्तु बुल डोजर नहीं। उसने जीपों और ट्रकों को सभरण और निपटान निदेशालय द्वारा निश्चित की गई दरों पर खरीदा था, और ट्रैक्टर उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों पर खरीदे गये थे।

(ख) राजस्थान सरकार ने ठेकेदारों को गाड़ियों की सूरत में ऋण स्वीकृत किये थे। ये उक्त सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और शर्तों के अधीन अपने स्वयं के विभागीय प्रभार में से किया गया था।

(ग) सड़कों के निर्माण की प्रगति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई अनुसूची के अनुसार हुई है और राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गाड़ियां उन्हीं कामों में इस्तेमाल की जा रही हैं जिनके लिये खरीदी गई थी।

(घ) और (ङ) चूंकि इन गाड़ियों के व्यवहार और खरीद संबंधी मामले राजस्थान की राज्य सरकार से सबंद्ध है अतः यह उसे सोचना है कि क्या किसी जांच की आवश्यकता है।

Theft From F. C. I. Godown Bhopal

5214. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a recent theft of large quantities of food grains from the big food godown of the Food Corporation of India at Chhova Road, Bhopal ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) An attempt was made to steal two full bags and two small packages in all weighing about 3 quintals of wheat but due to alertness of the staff the thieves could not carry these bags beyond a few yards where they left the bags and ran away. A report has been lodged with the police.

दिल्ली दुग्ध योजना

5215. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना बनने के समय से लेकर 31 मार्च, 1967 तक उसमें विभिन्न पदों पर कितने अधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये;

(ख) उनकी प्रतिनियुक्ति पर 31 मार्च, 1967 तक कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 30

(ख) 66,017.55 रुपये ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना नवम्बर, 1959 में स्थापित की गई थी । यह नई संस्था थी इसलिए सार्वजनिक हित में यह आवश्यक समझा गया कि शीघ्र ही कुशल तथा अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए जायें । कुछ पदों के लिए नियुक्ति नियमों को अन्तिम रूप देने के बाद इस समय ऐसे अधिकारियों की संख्या घटा कर 9 कर दी गई है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में समयोपरि भत्ता

5216. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना गत पांच वर्षों से प्रतिवर्ष समयोपरि भत्ते पर 60,000 रुपये से अधिक रुपये खर्च कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना में हो रहे इतने अधिक व्यय को कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में 12,30;576.43 रुपये दिये गये जो प्रतिवर्ष औसतन 2,46,115 रुपये प्रतिवर्ष होते हैं ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी समयोपरि भत्ते की राशि को कम रखने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । समयोपरि ड्यूटी के समय चेकिंग की जाती है । कर्मचारियों को समयोपरि ड्यूटी पर केवल उसी समय लगाया जाता है जबकि ऐसा करना अनिवार्य हो ।

Tobacco Stock in Andhra Pradesh

5217. Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large stock of tobacco has accumulated in Andhra Pradesh ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken for its disposal ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) ; (a) Yes. About 10 million kgs. of Sun-Cured (Natu) toacco have been accummulated.

(b) The stocks would be surveyed to assess the saleabale quantity and quality. Cigarette manufacturers would be persuaded to buy a portion of the saleable tobacco. Efforts will also be made to export to U. A. R., Syria and Sudan who are reported to be interested in buying Natu Tobacco. Tobacco Export Promotion Council has been asked to send samples to our Embasies in these countrias. The proposal to send a sales team to these countries is also under consideration.

Establishment of Panchayats and Zila Parishads

5218. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 494 on the 4th April, 1967 and state :

(a) the reasons for not so for establishing the Janpad Panchayats and zita parishads in Madhya Pradesh although the elections to the Gram Panchyats took place there in 1964 ; and

(b) when they are likely to be established and whether the Central Government have given any advice to the Madhya Pradesh Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricnlture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) Panchayats were reconstituted in the State in December, 1964 January, 1965. Following this the time sehedule drawn up by the State Government envesased the establishment of Janapada Panchayats and Zila Parishads over January March, 1966. The elections to local bodies in the State were, however. Postponed, consequent on the outbreak of the Indo-Pakistan conflict in August, 1965. The State Government had also, in the meanwhile. taken in hand amendment to the State legislation pertinent to the establishment of the Panchayatl Raj institutions ; they had set up a Study Group to go into the matter. As things stand, the higher tier bodies are to be constituted after the Act has been amended. The need for early establishment of these bodies in thc State has all along been urged by the Central Government.

दिल्ली में अनाज की जमाखोरी तथा तस्कर व्यापार को रोकने के लिये छापे

5219, श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों में दिल्ली में अनाज की जमाखोरी तथा तस्कर व्यापार को रोकने के लिये जमाखोरी विरोधी तथा तस्कर व्यापार विरोधी कितने छापे मारे गये;

(ख) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 114

(ख) 102

(ग) कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अनाज के जमा करने पर प्रतिबन्ध है। उत्पादकों द्वारा स्टाक की घोषणा करना अनिवार्य है और उसको नियमानुसार बेचा जा सकता है। गैर सरकारी कार्य के लिये अनाज को बिना परमिट के नहीं ले जाया जा सकता। कड़ी निगरानी के उद्देश्य से सीमा क्षेत्रों में जांच चौकियों की स्थापना की गई है। जमाखोरी और तस्कर विरोधी छापे मारने के लिये विशेष क्षेत्रों की स्थापना की गई है।

Use of Imported Jowar in Rajasthan

5220. Shri Onkar Lal Berwa : Shri N. S Sharma : Shri Beni Shanker Sharma : Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether is a fact that jowar supplied by U. S. A, for use as fodder is being consumed by people in Rajasthan ;

(b) if so, the reasons therefore ;

(c) whether any reports about deashs in Rajasthan as a result of consumption of this jowar by people have been received : and

(b) if so, the reasons for which its supply to people is not being discontinued ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise,

State Seed Farms in Rajasthan

5221. Shri Onkar Lal Berwa ; Shri N. S. Sharma : Shri Beni Shanker Sharma : Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of the State Seed Farms in Suratgarh and Jetsar in Rajasthan.

(b) the production in the said Farms during 1966-67 ; and

(c) the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Suratgarh Farm	--	30,331 acres.
Jetsar Farm	-.	21,319 acres.

(b) and (c) The information is being collected from the Farms and will be placed on the table of the Sabha as early as possible.

बहुप्रयोजनीय किसान सहकारी समिति, दिल्ली

5222. श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली किसान सहकारी बहुप्रयोजनीय सीमित की अनियमितताओं की जांच कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की जांच की जायेगी; और

(ग) यह जांच पूरी करने की कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) जांच करने का आदेश दिया गया है। ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इटली का उर्वरक देने का प्रस्ताव

5223. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इटली ने भारत को उर्वरकों का आयात करने के लिये 50 लाख डालर का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है; और

(ग) प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इडली से सप्लायर्स क्रैडिट निम्नलिखित मुख्य अदायगी की शर्तों पर उपलब्ध किया जाता है:

(क) आर्डर देते समय 5 प्रतिशत की अदायगी।

(ख) शिपमेन्ट को पूरा होने पर 5 प्रतिशत की अदायगी।

(ग) शेष 90 प्रतिशत बराबर किश्तों में, वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक।

(घ) मूल जिसमें क्रेडिट इन्शोरेन्स चार्जिज शामिल है के बकाया शेष पर सूद दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

India Cairo Air Services

5224. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Atam Das :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri J. Sundar Lal :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that direct air-service between India Cairo has been resumed ; and

(b) the estimated financial loss caused by the supension of the said air-service ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बिना जोती भूमि का सर्वेक्षण

5225. श्री मरंडी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिना जोती हुई उस भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण करने का है जिसका कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में अब तक ऐसी कितनी जमीन का खेती के लिए उपयोग किया गया है ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Anna Shaib Sindhe) : (a) Detailed surveys have already been carried out of the culturable wastelands in the country with a view to bringing them under cultivation and for the resettlement of landless agricultural workers. Originally the Government of India appointed a Wasteland Survey Committe in 1959. This Committee restricted the scope of survey to large blocks of wastelands i.e. 250 acres and above and recommended reclamation of 12.23 lakh acres in 13 States. As there were in addition considerable areas of wastelands in small scattered blocks, the Government of India further sponsored a scond survey of wastelands in blocks of less than 250 acres to supplement the work done by the Wasteland Survey Committee. This survey has been completed in 220 districts and is currently in progress in the rest of about 105 districts. Under this survey approximately 40 lakh acres of wastelands have so far been located as suitable for reclamation. The survey is likely to be completed by the end of the Fourth Five Year Plan. A provision of Rs. 62.5 lakhs has been made in the Fourth Plan for this purpose. The Central subsidy available for the scheme is up to Rs. 50,000 per district.

(b) The statistics about utilisation of such land of far, during 1967-68 are not yet available.

केरल में पर्यटक केन्द्र

5226. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल में कुट्टनाद् का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है;

(ख) क्या इसके लिए सरकार को केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार से कुट्टनाद में एक पर्यटक बंगला बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) यह स्कीम पर्यटन पर चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गयी है । इसका व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर वहन किया जायेगा ।

कृषि पुर्नवित्त निगम

5227. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि पुर्नवित्त निगम ने आन्ध्र प्रदेश कोआप्रेटिव लैंड मारगेज बैंक लिमिटेड हैदराबाद द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों में 3.15 करोड़ रुपये की राशि लगाई है;

(ख) क्या उस बैंक ने ये ऋण पत्र नागार्जुन सागर आयकट क्षेत्र में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये धन जुटाने हेतु जारी किये थे;

(ग) क्या इस बात की कोई शिकायत मिली है कि बैंक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये जुटाई गई राशि का उचित उपयोग नहीं किया है;

(घ) क्या निगम ने बैंक के कार्य-संचालन के बारे में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 989/67**]

गंगा–ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारी

5228. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारी संघ की ओर से 20 जून, 1967 को एक ज्ञापन पेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों की यूनियन की ओर से 20-6-67 को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह आग्रह किया गया था कि नदी परिवहन सेवाओं का योजनानुकूल विकास किया जाये और गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन के उन पूर्व कर्मचारियों के लिए रोजगार

की किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये जो अंतर्राज्यीय परिवहन निदेशालय तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण की 'फील्ड' संस्थाओं में विलीन किये गये हैं।

गंगा नदी में नदी सेवाओं को वाणिज्यिक आधार पर चलाने की शक्यता के प्रश्न की जांच की गयी थी और अध्ययन से मालूम हुआ कि आर्थिक आधार पर तुरंत ऐसी सेवाएं चलाने के लिए पर्याप्त यातायात उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में परिवहन के वैकल्पिक साधनों और विशेषकर सड़क और रेल, के विकास को दृष्टि में रखकर भविष्य में किसी पर्याप्त हद तक नदी मार्ग के यातायात के विकास की संभावनाओं के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होगी। फरक्का बांध के निर्माण के पूरा होने से भी इस मामले पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और यह आवश्यक है कि इस समस्या है कि इस समस्या का दीर्घ कालिक और समाकालिन आधार पर जांच किया जाय।

जिन कर्मचारियों की सेवाएं दीर्घ कालिक आधार पर आवश्यक होगी तथा जो अन्य बातों में भी उचित होने उन्हें स्थापित करने का विचारधीन हैं।

Foodgrains Productions in States

5229. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country which grow surplus foodgrains ;

(b) the population of each of theses states separately ;

(c) the annual foodgrains requirement of each of these States ; and

(d) the total quantity of foodgrains grown in each of these States during the last crop and the manner in which the surplus foodgrains was uililised ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Commuity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is difficult to say categorically which States in the country are surplus in foodgrains for all times. Whether a State in surplus or not depends upon its production and consumption requirements. The former varies from year to year and the latter depends on a number of factors including growth of population, changes in consumption patterns, levels of income, etc. However, on the basis of the pattern of Government distribution of foodgrains during the last few years, the States of Andhra Pradesh Madhya Pradesh, Orissa and Punjab can be classified as surplus States in a year of normal production.

(b) A statement giving estimated mid-year populations in 1967 of the States mentioned above is attached.

(c) There has been no scientific and comprehensive survey on the consumption of foodgrains in India so far. The requirements of foodgrains are also elastic to some extent depending on the availability of foodgrains and of other substitute, food stuffs their comparative prices, level of income, etc. It is, therefore, not possible to indicate any precise requirement of foodgrains of each State.

Final Estimates of production of foodgrains for the last year, viz 1966-67 are not yet available.

Statement

Estimated Mid-Year Population for 1967

(Figures in 000)

Andhra Pradesh	40712
Madhya Pradesh	37864
Orissa	20202
Punjab	24634

बम्बई–इंदौर–भोपाल विमान सेवा

5231. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई से इंदौर और भोपाल तक विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बम्बई और इन्दौर के बीच चल रही विद्यमान डाकोटा विमान सेवा को इस समय भोपाल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि भोपाल, दिल्ली और नागपुर से विमान सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है ।

Imported Spray Machines

5232. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Guna Nand Thakur :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints recently about the uselessness of Villier and Ellman spray machines, which are made in England ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Villiers do not manufacture spray machines. The Villiers engines now being manufactured indigenously are, however, being used by Sprayer manufactures. Some complaints about the performance of these engines have been received. The Director General, Technogical Development has been requested to enquire into the complaints as the firm is registered with him. He will naturally take appropriate action on the basis of the findings.

A few reports about minor difficulties experienced in the working of the imported Allman sprayers being used in the country were received and were attested to by the firm promptly. The machines have generally been in active use.

चांदीपुर का विकास

5233. **श्री स० कुन्डू :** **श्री बेधर बेहरा :**
श्री क० प्र० सिंहदेव : **श्री श्री निवास मिश्र :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में समुद्र के किनारे पर बसे हुए चांदीपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और पर कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण अन्दमान में भूमिहीन कृषक परिवार

5234, **श्री गणेश :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी अन्दमान द्वीप में मूल वासियों में से कितने कृषक परिवार भूमिहीन हैं ;

(ख) दक्षिण अन्दमान द्वीप के मूल वासियों के पास औसतन कितनी कृषि भूमि है;

(ग) कितने कृषक परिवारों के पास बागवानी के लिए पहाड़ी भूमि है; और

(घ) क्या भूमिहीन कृषकों को धान की खेती योग्य भूमि देने तथा अन्य लोगों को पहाड़ी भूमि देने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 'मूल वासियों' का अभिप्राय भूतभूर्व अपराधियों तथा उनकी सन्तानों से है। कोई ऐसा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि भूमि-धारी या भूमिहीन व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति मूलवासी हैं। अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि दक्षिण अन्दमान द्वीप के मूल कृषकों में से कितने परिवार भूमिधारी हैं और कितने भूमिहीन।

(ख) दक्षिण अन्दमान द्वीप में एक परिवार के पास औसतन 1.64 हैक्टेअर या 4 एकड़ भूमि है। एक परिवार की औसत भूमि का हिसाब लगाते समय कृषकों को दीर्घ अवधि के अनुदानों के रूप में मिली सरकारी बागान की भूमि शामिल नहीं की गई है।

(ग) दक्षिण अन्दमान में 1104 कृषक परिवारों के पहाड़ी भूमि है।

(घ) कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है परन्तु आशा है कि वाणिज्यिक इमारती लकड़ी के बनों की सफाई के पश्चात आस-पास के द्वीपों की सुधारी हुई भूमि कृषि प्रयोजनों के लिए प्राप्त हो सकेगी।

अन्दमान द्वीप समूह में हलचलाने वाले पशुओं से विहीन कृषक

5235. श्री गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्दमान द्वीप समूह में बहुत से कृषकों के पास हल चलाने वाले पशु नहीं हैं और इस कारण वे अपनी खेती का काम आरम्भ नहीं कर सकते;

(क) यदि हां, तो कृषि उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या उन्हें ऋण देने का सरकार का कोई विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत इस ऋण को उनकी फसलों से वसूल किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) बहुत से किसान अपनी भूमि पर हिस्से के आधार पर उप-पट्टेदारों से खेती कराते हैं। ये उप-पट्टेदार अपने हल चलाने वाले पशुओं की सहायता से या हल चलाने वाले पशुओं को उधार लेकर खेती करते हैं। ऐसी खेती प्रभावित नहीं होती।

(ग) तकावी तथा अन्य ऋण सम्बन्धी सुविधायें जरूरतमंद किसानों को दी जाती हैं ताकि हल चलाने वाले पशु खरीद सकें। इन ऋणों को देते समय किसानों की ऋण अदा करने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाता है।

(घ) सरकार कोआपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के द्वारा फसल ऋण पद्धति शुरू करना चाहती है। दी अन्डेमान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमि०, पोर्ट ब्लेयर हाल ही में स्थापित किया गया है और फसल ऋण पद्धति को इन द्वीपों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

मंगलुतान-मायाशहर सड़क

5236. श्री म० अमरसे :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान द्वीप के इमारती लकड़ी उद्योग के लट्ठों के परिवहन के लिए मंगलुतान मायाशहर सड़क के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है;

(ख) क्या जनता द्वारा इस सड़क को प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी अधिक राशि खर्च करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जंगल की पैदावार प्राप्त करने तथा इस क्षेत्र में बसे हुए लोगों की एक बड़ी संख्या के लिये संचार सुविधाओं की

व्यवस्था करने के लिए यह सड़क अगस्त 1958 में 3.36 लाख सं० की अनुमानित लागत पर मंजूर की गई थी। यह 1962 में 3.73 लाख रुपये की लागत पर तैयार हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप में पुल और पुलिया

5237. श्री म० अमरसे :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह के स्वच्छ जल के नालों पर पुल और पुलिया निर्माण करने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक सिविल इंजीनियर को अमरीका भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा नाला, नया शहर और दिगलीपुर नालों पर पुलों के निर्माण कार्य को, जो 7 वर्षों से अधिक समय से निलम्बित पड़ा है, आरम्भ करने के लिये वह कब स्वदेश लौट रहे हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप के वन विभाग में इमारती लकड़ी की कमी

5238. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० अमरसे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्दमान के वन विभाग में इमारती लकड़ी के स्टाक में हाल में बहुत कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) जांच का निष्कर्ष क्या निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्दमान वन विभाग

5239. **श्री क. प्र. सिंह देव :**
श्री म० अमरसे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान वन विभाग में लगातार बहुत घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में वास्तव में कितना घाटा हुआ था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच करने का है ताकि इस घाटे के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। 1964–65 तथा 1965–66 के लिए कमियों पर स्वामित्व की निम्नलिखित राशि मैसर्ज पी० सी० रे एण्ड कम्पनी से प्राप्त होनी है। 1966--67 के लिए वाणिज्य सम्बन्धी लेखा को अभि अन्तिम रूप नहीं दिया गया है:—

196-4-65	--	61,14,160
1965--66	–	66,93,590

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश के लिये धन का नियतन

5240. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 और 1967–68 में केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश के लिये कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) वर्ष 1966–67 में इस निधि की राशि को किन योजनाओं के लिये प्रयोग में लाया गया और 1967–68 में किन किन योजनाओं के लिये प्रयोग करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1966–67 में 76.77 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। 1967–68 के बजट में 33.00 लाख रुपये की व्यवस्था है। जैसे ही संसद द्वारा बजट पास कर दिया जायेगा यह राशि राज्य सरकारों के निपटान पर रख दी जायेगी।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल रख दी जायेगी ।

Cooperative Sugar Mills

5241. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme to set up some more cooperative sugar mills is under the consideration of Government; and

(b) if so, the number thereof and names of the States in which they would be located ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) and (b) Due to limited rupee resources for grant of long term loans, there is difficulty in the establishment of new cooperative sugar factories already licensed. Therefore, the question of granting licences for more factories has been deferred till a solution regarding finance has been found.

पब्लिकेशन डिवीजन सहकारी ऋण तथा बचत समिति

5242. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिकेशन डिवीजन सहकारी ऋण तथा बचत समिति का परिसमापन मार्च, 1966 में कर दिया गया था ;

(ख) क्या इस सोसायटी ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिये गये 1,50,000 रुपये और कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के जमा 1,00,000 रुपये देने थे ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के 1,49,138,00 रुपये और जमाकर्ताओं के 1,06,737,00 रुपये देने थे ।

(ग) जिन व्यक्तियों पर धन के गबन का आरोप है, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिये पुलिस में रिपोर्ट की गई है । यह भी विचार है कि बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1952, जो कि दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में भी लागू किया गया है, की धारा 50–ए के अन्तर्गत उनके विरुद्ध धन की वापसी हेतु सिविल दायित्व के लिए मांग की जाएगी ।

अन्य राज्यों के आवंटन के लिये पंजाब में गेहूं का समाहार

5243. श्री गु० सिं० ढिल्लों : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों के लिये आवंटित करने हेतु तथा राज्यों में गेहूं भेजने हेतु 1 अप्रैल, 1967 से लेकर आज तक पंजाब में कुल कितनी मात्रा में गेहूं का समाहार किया गया ; और

(ख) समाहार किये गये इस गेहूं में से पश्चिम बंगाल को अब तक कुल कितना गेहूं भेजा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) 1 जुलाई, 1967 तक 97,646 टन

(ख) 3 जुलाई, 1967 तक 7061 टन

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आरा मिलें

5244. श्री गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में छोटा आरा मिलों ने लट्ठों के मूल्य अधिक होने के कारण अपना काम बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या लट्ठों का मूल्य कम करने के सम्बन्ध में छोटे आटा मिल मालिकों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इनके अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गत समय में अभ्यावेदनों में की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सका।

Udaipur Aerodrome

5245. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the details of the plan prepared for the development of Udaipur aerodrome in view of the fact that Udaipur is becoming a city of international importance;

(b) whether there is any Scheme to extend night air-service to Udaipur ; and

(c) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (DR. Karan Singh) : (a) Udaipur aerodrome has already been developed for operations by F-27 type of aircraft. This meets the present requirement of Indian Airlines Corporation.

(b) and (c) : No, Sir. There is no such scheme at present under consideration,

Rise in Price of Gur

5246. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for the price of gur rising three to four times the price prevailing last year while the price of sugar has not risen to that extent ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check this rise in price of gur ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The rise in price of gur is due to fall in production of sugar and consequent increased demand for gur. The reason for the steeper rise in the price of gur compared to the price of sugar is that there is no control over price or distribution of gur while the price and distribution of sugar is controlled.

(b) Measures to maximise sugar production and to keep price of gur within the reasonable limits are under consideration of the Government in consultation with the State Governments and will be announced before the commencement of the next crushing season.

Tourism in Rajasthan

5247. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the current year, as compared to that of the last year for the development of tourism in Rajasthan ;

(b) how the said amount is proposed to be spent ; and

(c) whether any amount has been specially set apart for utilisation in Udaipur, Chittor, Jodhpur, Jaisalmer, Ramkunwar and Abu for providing hotel and travel facilities for the tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (DR. Karan Singh) : (a) A budget provission of Rs. 2.50 lakhs has been made in the Central Plan for developing tourist facilities in Rajasthan during 1967-68 as compared to Rs, 24, 986/-released as subsidy to the State Government in 1966-67.

(b) It is proposed to spend the amount of Rs. 2.50 lakhs on tourist schemes in Jaipur and Bharatpur.

(c) There are schemes for provision of tourist accommodation and/or facilities at Jaipur, Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur, Mt. Abu. Chittorgarh and Ajmer. Their finalization awaits confirmation from the State Government that they will meet 50%of the expenditure.

Allotment and Supply of Foodgrains to Maharashtra

5248. **Shri D. S. Patil** :
Shri R. D. Bhandare:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that full quantity of food-grains was not supplied by the Centre to Maharashtra State during the period January, 1967 to June, 1967 against the monthly quota allotted for them,

(b) if so, the quantity of monthly quota allotted and the quantity of supply made to them ; and

(c) the extent of cut effected and the reasons for this cut ?

The Minister of State in The Ministary of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (c) There were some short supplies in some months, while there were excess supplies in other months. The quotas of imported foodgrains (wheat and milo) allotted to Maharashtra from January to June, 1967 and the quantities actually supplied against these quotas are indicated below.

(**Figures in thousand tonnes**

	Quota allotted	Supplies
January, 67	97.7	95.2
February, 67	95.0	103.8
March, 67	90.2	90.0
April, 67	80.0	67.2
May, 67	80.0	83.9
June, 67	70.3	61.7
Total:	513.2	5 1.8

Shortfall in supplies was about 2.2% Shortfall in supplies was due to poor arrivals.

Sale of Foodgrains by Punjab and Haryana to Bihar

5249. Shri Ramavtar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whethere Government are aware of the fact that the Revenue Minister of Bihar recently visited Punjab and Haryana for negotiating purchase of wheat, barley, khuchhi and gram ;

(b) whether Governments of these two States are prepared to sell foodgrains of the Bihar Government provided they get permission for it from the Central Government and there are no other difficulties in the way ; and

(c) if not, the assistance Government propose to give to ensure that the high-yielding variety crop programme for 1967-68 becomes successful ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agricu ture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (c) : The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha,

अनाज की उपज में वृद्धि

5250. श्री मरंडी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने इस सरकारी दावे का खण्डन किया है कि अनाज के वार्षिक उत्पादन में दीर्घ-कालीन वृद्धि 2½ प्रतिशत से 3 प्रतिशत की दर पर हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके आधार क्या हैं तथा इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : कृषि मूल्य आयोग ने 1949–50 से 1964–65 तक की अवधि में अनाज के वार्षिक उत्पादन में 3.16 प्रतिशत दर पर वृद्धि के सम्बन्ध में मतभेद प्रकट नहीं किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि दर जांचने की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 से 14 वर्ष कर दी गई तो उत्पादन की दर घट जाएगी। 1965–66 तथा 1966–67 के सुखे के वर्षों में जो कम उत्पादन हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। अतः आयोग ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फसलों की प्राप्ति कुछ भी हो, राष्ट्रिय स्तर पर उत्पादन के दर के बारे में कोई दृढ़ निश्चय नहीं बताए जा सकते।

पंजाब में अधिक उपज वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम

5251. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में पंजाब में अधिक उपज वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम के लिए कितने एकड़ भूमि तथा कितनी राशि के ऋण की आवश्यकता है ;

(ख) क्या ऋण संबंधी सारी आवश्यकता को भारत का रिजर्व बैंक पूरा करेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1967–68 में अधिक उपज वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम सफल रहे, सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब में 1967–68 के खरीफ के मौसम में 2.50 लाख एकड़ तथा रबी। ग्रीष्म मौसम में 10,00 लाख एकड़ भूमि में अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती करने की योजना है। फसलवार विवरण निम्न प्रकार है:–

(क्षेत्र लाख एकड़ों में

फसल	1967 की खरीफ के लिए लक्ष्य	1967–68 की रबी। ग्रीष्म के लिए लक्ष्य
धान टी० एन०–1	0.50	–
संकर मक्का	1.00	–

संकर बाजरा	1.00	–
मैक्सिकन गेहूं	–	10.00
	2.50	10.00

उपरोक्त क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण की मांग के बारे में ठीक ठीक ज्ञानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं। रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा 1967–68 के लिए स्वीकार की जाने वाली बढ़ाई हुई ऋण राशि से केवल सहकारी समितियों के सदस्यों की ऋण विषयक मांग पूरी की जायेगी। ऐसे कृषकों की ऋण विषयक मांग, जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले तकावी ऋणों से पूरी की जायेंगी।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाले सहकारी ऋण की पूर्ति के लिए भारत सरकार राज्य सरकार के लिए उर्वरकों, बीजों, कीटनाशक औषधियों आदि के लिए 'वेज एण्ड मीन्ज' एडवांस देती है। 1967-68 में राज्यों के विभिन्न कृषि उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों के लिए 105 करोड़ रुपए का नियतन होने की सम्भावना है। इसका कुछ भाग पंजाब सरकार को उसके अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिए दिया जायेगा। अभी यह पता नहीं कि इसमें से पंजाब को कितना धन मिलेगा और उनकी विशेष मांगों के आधार पर ही उस राशि का नियतन किया जायेगा ताकि धन अभाव के कारण कार्यक्रम को हानि न पहुँचे।

चीनी के विशेष कोटे

5252. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने अमूल डेरी, अलेम्बिक तथा ऐसे ही अन्य चीनी उत्पाद निर्माताओं को, जिनके उत्पादों की खपत सारे देश में होती है, राज्यों को आवंटित चीनी के कोटों के अतिरिक्त चीनी के कोई विशेष कोटे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) कुछ बिस्कुट और मिठाई बनाने वाले यूनिटों को, जो अपने उत्पादन केवल उन्हीं राज्यों में बेचते हैं जहां वह स्थापित हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी बेचते हैं, मौसमी फलों का उपयोग करने के लिये लाइसेंस धारी फल उत्पादन वस्तुओं के निर्माताओं को आवश्यक बाल आहर तथा संघनित दुग्ध के निर्माताओं को तथा जीवन रक्षक औषधियों के कुछ निर्माताओं को विशेष कोटे दिये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का विकास

5253. श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कुछ स्थानों का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार की खजुराहो के समेकित विकास ; सांची और खजुराहो में पर्यटक बंगलों के (श्रेणी I) के कमरों के वातानुकूलन ; शिवपुरी के विकास ; और कान्हा–किसली–जबलपुर काम्प्लेक्स के विकास की योजनाएं हैं ।

भोपाल का हवाई अड्डा

5254. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भोपाल का हावाई अड्डा बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (ड० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की भोपाल के लिए विमान सेवा बन्द करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से अकाल पीड़ितों के लिये सहायता

5255. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने भारत में वर्तमान अकाल तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपत निधि द्वारा सूखा सहायता के लिये दी जाने वाली सप्लाई और उपकरणों का व्यौरा नीचे दिया गया है ।

क्रम संख्या	वस्तु	मात्रा	कीमत रुपयों में
1.	सूखा दुग्ध चूर्ण	4,402.1 टन	1,37,22,290
2.	कोर्न सेया दुग्ध	3,515.6 टन	74,71,772
3.	टीका उत्पादन के लिये कच्चा माल	—	5,16,495
4:	औषध और भेषजाय	—	25,70,250
5.	औषध और डाइट्री सपली मैन्ट सैटस	1763 सैटस	14,15,915
6.	हाथ से भरने वाली मशीने	1	4,295
7.	स्टैनलैस स्टील में जरिंग पम्प	4	2,300
8.	गाड़ियां	69	11,71,397
9.	(क) मोटर साइकिलें	430	5,93,632
	(ख) इसके लिये फलतू पुर्जे	—	8,700
	सूराख करने के उपकरण		
10.	(क) हैलको टाईगर रिगज	4	5,56,245
	(ख) हैलको टाईगर रिगज	7	
	(ग) ऊपर (क) और (ख) के लिये उपसाधन	—	4,99,785
	(घ) कलोरोनेटिंग यूनिट	10	66,000
	(ङ) जल विश्लेषण किट	20	23,624
	(च) हैण्ड पम्प	133	1,20,337
	(छ) सूराख करने वाले उपकरण के लिये फालतू पुर्जे	—	1,50,000
11	मलटि विटामिन टैबलेट, ए और डी कैपसूल,		

	बाल आहार और समस्त दुग्ध चूर्ण इत्यादि, के रूप में दान	—	58,73,528
12.	एयर कम्प्रेसर के लिये फालतू पुर्जे	—	3,000
13.	राष्ट्रीय इंजन के लिये फालतू पुर्जे		675

भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़ा

5256. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े का कितना विकास हुआ हैं ;

(ख) इन योजनाओं के आरम्भ होने से अब तक भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े ने कितने माल की ढुलाई की है; और

(ग) चौथी पंचर्षीय योजना की अवधि में इसमें क्या उन्नति की जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय जहाजों का टनभार प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में 0.37 मीलियन जी० आर० टी० था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में वह 0.48 मीलियन जी० आर० टी० था और तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंत में 1.50 मीलियन जी० आर० टी० था।

(ख) 1951 से 1965 तक भारतीय जहाजों द्वारा तटीय व्यापार में 49.84 मीलियन टन माल ले जाया गया जबकि समुद्र पार के व्यापार में उनके द्वारा दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधियों के दौरान 29.34 मीलियन टन माल ले जाया गया। प्रथम योजना काल में भारतीय जहाजों द्वारा ले जाये गये माल के आंकड़े सहज उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप में 1.70 मीलियन जी० आर० टी० के जहाजों के लेने का विचार है जिसमें 0.20 मीलियन जी० आर० टी० के वे जहाज भी शामिल हैं जो पुराने जहाजों के बदलने के लिए लिये जाएंगे। अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अंत तक 3.00 मीलियन जी० आर० टी० के जहाज चालन में रहेंगे और 0.50 मीलियन जी आरटी के जहाज निर्माणाधीन होंगे जिनके पांचवी पंच वर्षीय योजना काल के प्रारंभिक वर्षो में तैयार होने की आशा है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में नौवहन का विकास करते समय निम्नलिखित मोटे उद्देश्य ध्यान में रखे जाएंगे:—

(1) अपनी परिष्करण शालाओं में अशोधित पैट्रोलियम ले जाने के लिए पर्याप्त टैंकरो की प्राप्ति।

(2) निर्यात के लिए खनिज लौह को ले जाने के लिए आधुनिक खुले माल वाहकों की प्राप्ति ।

(3) जिन लाइनर सेवाओं में भारतीय नौवहन ने 'पूल' प्रतिशतता प्राप्त करली है या जिन में प्रतियोगिता चालन द्वारा अपने को स्थापित कर लिया है उन्हें मजबूत करना ।

(4) जिन लाइनर सेवाओं में मौजूदा जहाजी सेवाएं अपर्याप्त हैं या हमारे निर्यात वृद्धिकर उपायों के दृष्टि कोण से जिनमें सुधार हो सकता है उन नये लाइनरों में प्रवेश करना ।

Estimated Consumption of Fertilsers During Fourth Plan

5257. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the detailed estimates of the consumption during the Fourth Plan of nitrogen. phosphorus and potash as prepared by Agriculture Department ; and

(b) the quantity of fertilizers and the varieties thereof to be used separately in respect of the areas under cultivation for tea, sugarcane. potato, cotton, paddy and wheat ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The tar gets of consumption of fertlizers fixed for the Fourth Plan period aregiven below:—

(figures in Million tonnes)

Year	Nitrogenous (N)	phosphatic (P2°5)	Potassic K2°
1966-67	1.00	0.37	0.20
1967-68	1.35	0.50	0.30
1968-69	1.70	0.65	0.45
1969-70	2.00	0.80	0.55
1970-71	2.40	1.00	0.70

The above target of consumption for 1970-71 was arrived at by the Committee on Fertilisers (1965) vide para 2.24 of Report (available in Parliament Library) as indicated below:-

Million tonnes

	N	$P_2°_5$	$K_2°$
1. Base level of application at the end of the 3rd plan	0.80	0.25	0.15
2. Additional requirements of intensive programme for food-grains	1.00.	0.33	0.47

3. Additional requirements for cash crops estimated by Working Group of Manures & Fertlisers	0.36	0,23	0.06
4, Additional requirements of intensive programmes on cotton and groundnut	0.07	0-03	0.03
5. Additional requirements of intensive programmes on other crops in areas presently under irrigation	0.18	0.18	–
Total	2.41	1.02	0.71

The actual cousumption pattern for individual crops will however, differ from year to year according to the progress made in the implementation of the various programmes, the fertiliser consciousness of the farmers, the availability of supplies and irri gation facilities and such other relevant factors. The varieties of fertilisers commonly used are Ammonium Sulphate, Urea, Calcium Ammonium Nitrate, Ammonium Sulphate Nitrate, Ammonium Chloride, Ammonium Phosphate, Nitrophosphate, Diammonium Phosphate and Muriate of Potash. The quantities used of each variety will depend on availability and cost as well as on nutrient content. Subject to these factors, due consideration to the crop to be fertilised and the soil charactsistics of the area is also given in the choice of any particular variety of fertiliser.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CLLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों की वापसी

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी (मंदसौर): श्रीमान मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रजनों की वापसी"

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : सितम्बर 1965 में भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ जाने पर पाकिस्तान में रहने वाले कुल मिलाकर 3886 भारतीय राष्ट्रकों को पाकिस्तान सरकार ने विभिन्न आरोप लगा कर बन्दी बना लिया था। ये लोग पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान दोनों में, बहुत से शिविरों में रोक रखे गए थे। लड़ाई बन्द होने पर, इन भारतीय राष्ट्रिकों को हवाई जहाज, पानी के जहाज और जमीन के रास्ते से देश वापस ले जाने का प्रबन्ध किया गया और 16-2-66 तक उनमें से अधिकाँश लोगों का पुनः देशावर्तन कर दिया गया।

जो भारतीय लोग पाकिस्तानी जेलों में अभी बचे हैं, उनके बारे में हमने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था कि वे हमें उनका ब्यौरा दें, जैसे उनके खिलाफ क्या आरोप

लगाए गए हैं, उन्हें कितनी सजा दी गई है, उन्हें यहां बन्दी बना कर रखा गया है आदि, ताकि हम उन्हें भारत वापस ला सकें। उन्होंने हमें यह सूचना नहीं दी है। लेकिन बाद में, उन्होंने कई अवसरों पर हमें ऐसे लोगों की सूचियां भेजी जिन्होंने अपनी सजा भुगत ली थी और जिन्हें भारत पुनर्देशावर्तित किया जा सकता था। इस तरह के लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता का पता लगा लेने के बाद हमने पाकिस्तान–स्थित अपने हाई कमीशन से इन्हें देश वापस भेजने का प्रबन्ध करने को कहा। इस तरह के सभी मामलों में हमारे हाई कमीशन के अधिकारी उन लोगों के साथ सीमा तक आए और संम्बद्ध राज्य सरकारों ने उनके सीमा पार कर लेने पर भारत में उनके नगरों तक पहुंचाने का आवश्यक प्रबन्ध कर दिया।

अब तक कुल मिलाकर 228 व्यक्ति पाकिस्तानी बन्दी शिविरों से छूट कर पांच अलग-अलग दलों में भारत पहुँचे हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत सरकार को दी गई सूचना के अनुसार, अभी 77 व्यक्ति ऐसे हैं जो बन्दी हैं।

भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को इस बात के लिए राजी करने की निरन्तर कोशिश करती रही है कि वह बंदी लोगों को रिहा कर दे। कहा जाता है कि इन बंदी शिविरों में रहने की दशा बहुत खराब है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी बंदियों से बातचीत करने के लिए उन बन्दी शिविरों में जाते हैं और भारत में उनके रिश्तेदारों को उनकी हालत के बारे में सूचना देते रहते हैं। हम कुछ निर्दोष लोगों को रिहा कराने का विशेष प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो नाबालिग हैं जो असावधानी में पाकिस्तान चले गए थे। दुर्भाग्य से हम अपनी कोशिशों में अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : बर्बरता में पाकिस्तान चीन का अनुसरण करता प्रतीत होता है और बौद्ध नजरबन्दियों और जेलों में निर्दोष व्यक्तियों जिनमें नाबालिग भी शामिल है, पर हाल के बर्बरता पूर्ण हमले से तथा इस बात से कि वहां पर दो वर्ष से अधिक समय से जेलों में रहने की दशा खराब है यह स्पष्ट हो जाता है। पूर्वी क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर कुछ व्यक्तियों के अपहरण के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है और सरकार उन्हें छुड़वाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : नई दिल्ली का एक 16 वर्षीय छात्र अभी तक लापता है और सरकार ने उसकी रिहाई के लिये कुछ भी नहीं किया है।

श्री मु० क० चागला : यह बात नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है। हम बराबर पाकिस्तान से पूछताछ करते रहे हैं। जैसा मैंने कहा कुछ नाबालिग भी हैं और हमने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। ये नाबालिग हैं: एक लड़का गलती से उनकी सीमा में चला गया था क्योंकि उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता था। हमने पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसका दो-तीन वर्ष पहले अपहरण किया गया था (अन्तर्बाधा)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए :-

श्री मु० क० चागला : यह इससे उत्पन्न नहीं होता । अपहरण के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । प्रश्न यह था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ जाने पर कितने व्यक्ति बन्दी बनाए गये और कितने रिहा किये गये तथा कितने अभी तक रिहा नहीं किये गये हैं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : जिनका अपहरण किया गया है यह स्पष्ट है कि वे अभी भी जेल में है ।

श्री मु० क० चागला : मैं कोशिश करूंगा और अपने माननीय मित्र को यह जानकारी दूंगा । वे मुझे लिख सकते हैं और मैं अवश्य ही उन्हें जानकारी दूंगा । परन्तु यह इससे उत्पन्न नहीं होता और मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) चौथा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 29 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 989 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी० एस० आर० 1031 को दिनांक 3 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या** एल० टी० 975/67]

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 10 जुलाई 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत हैं ।"

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : मेरा निवेदन है कि दो शनिवारों को बैठने के अतिरिक्त हम मध्यान्ह भोजन अवकाश को भी समाप्त कर दें या एक घन्टा देर तक अर्थात 7 बजे तक बैठें जिससे ज्यादा से ज्यादा मांगों पर चर्चा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम । प्रस्ताव हमारे सामने है । इस समिति ने इन सब पर विचार किया है । परन्तु जब 5 बजे ही गणपूर्ति नहीं होती है तो 6 बजे गणपूर्ति कैसे हो सकती है । मैं देखता हूं कि कभी कभी बोलने वालों को छोड़ कर शेष सदस्य उठ कर चले जाते हैं । यदि गणपूर्ति रहती है तो 7 बजे तक बैठने में किसी को आपत्ति नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I want to know from the hon. Minister when Dr. Lohiya's motion re : ceiling on expenditure will be taken up this week or next week.

अध्यक्ष महोदय : उसका इस प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह एक पृथक मद है । अगले सप्ताह का कार्य अगले सप्ताह निर्धारित किया जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो 10 जुलाई, 1967 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें जारी

DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

संचार विभाग-जारी

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : This Department is not serving the people efficiently a lot of difficultirs are experienced by the pepole due to the shortcomings in the working of this Department. The attitude of the employees should be changed and they should adopt an attitude of serving the people and not to harass them.

Frequent complaints are made about inordinate delays in the delivory of money orders and latters, For examples a money order which was sent from Asansol Post office in 1965 has not been delivered so far. Such thingh should be put an end to immediately.

The demands put forward by the National Federation of P. and T. Employees should be gone into and steps should be taken to implement them. Hon. Minister has said that he will appoint a tribunal for arbitration. But uptil now nothing has been done.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Government should pay more attention to imporve the working conditions of low-paid employees. They should be paid better salaries housing facilities should also be provided to them. This would instill in them the felling of working honestly and efficiently.

Salaries of high officials should be reduced. The saving resulting from this step can be utilised for paying better salaries to the low-paid staff.

The R. M. S employees of Kanpur are experiencing certain difficulties. Government should improve their conditions of service.

There are no adequate postal and telephone facilities in Eastern Uttar Pradesh. Eastern Uttar Pradesh is a backward area. More postal and telephone facilities should be provided there.

दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। हमारा देश बहुत लम्बा चौड़ा है और जहां तक डाक तथा अन्य सेवाओं का सम्बन्ध है। हमारे देश वासियों के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है। इस विभाग की बजट राशि को दुगुना कर देना चाहिये ताकि यह प्रत्येक गांव में एक डाकघर तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

पिछड़े क्षेत्रों में उतनी डाक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जितनी उपलब्ध होनी चाहिये। इस देश के पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये उपाय किये जाने चाहिये।

विभागातिरिक्त डाकघरों की आजकल कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो अंग्रेजी शासन की यादगार हैं। इन्हें अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

डाक तथा तार विभाग का रेलवे बोर्ड के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिये। इसे संचार मन्त्रालय का एक वास्तविक कार्य पालक अंग बना दिया जाना चाहिये। इस समय इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह तो केवल सलाह देने का ही काम करता है।

रेल डाक सेवा कर्मचारियों की दशा में सुधार किया जाना चाहिये। उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्हें अधिक वेतन अधिक सुविधाएं तथा अधिक संरक्षण दिया जाना चाहिये।

इस विभाग ने चुनावों के दौरान बहुत ही सराहनीय ढंग से काम किया है। उस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी।

टेलीफ़ोन सेवा में सुधार किया जाना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक नगर में जिसकी जनसंख्या 10,000 है, टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था हो। दिल्ली के टेलीफोन केन्द्रों को यन्त्रों तथा टेलीफोन आपरेटरों के मामले में सुदृढ़ किया जाना चाहिये। महिलाओं को रात्रि ड्यूटी पर नहीं रखा जाना चाहिये। डाक कर्मचारियों को मकान उपलब्ध किये जाने चाहिये और इसके लिये ऐक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

Shri Ram Charan (Khurja) : Government has provided all facilities to high officials while the low-paid empolyees like postmen are being neglected. Their lot is miserable, Steps should be taken to improve their lot. Although postmen have been classified as Class III employees but they get pay of Class IV employees. Their pay scale should be the same as that of Class III employees.

The persons working in the extra-departmental post offices get a meagre pay of Rs. 30 This is very inadequate keeping in view the increased cost of living. It should be increased to Rs. 6).

'Malis' in the P. & T. Department are not given uniform. This matter should be looked into. Watchmen experience great difficulty in getting leave. Some additional staff should be provided to relive the watchmen desirous of proceeding on leave.

The uniform of a postman is not of good quality cloth. Better uniforms should be provided to the postman working in the P. & T. Department,

The low-paid employees find it difficult to make both ends meet. More D. A. should be paid to them.

The increased rates of trunk calls cause great hardship to the people. Charges for trunk calls for a distance less than 50 miles should be between one and tow rupees. It would enable more people to avail of the trunk call facilities and add to the revenue of the Govt.

A departmental examination used to be held for giving promotion to Class IV employees wherein reservation for scheduled caste employees was also fixed. But this reservation has been abolished now to reduce their percentage in the services, The reservation of Scheduled Caste employees should be restored in order to give them encouragement.

Separate P. & T. circles should be provided for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh,

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) ; A new practice in respect of trunk call bills has been started. The name of the city and date of the call is not mentioned .in the bill now. This causes a lot of inconvenience to the people. It is reallygratifing that the hon. Minister has now agreed to discontinue this practice.

If there is some error in a trunk call bill the matter is to be taken up with the headquarters. If somehow or other some delay occurs in doing so, the telephone is disconnected. It causes great inconvenience. Although the Minister has now agreed to remedy the situation the concerned staff should also be instructed in this respect.

The people in the rural areas require more post and telegraph offices and telephone facilities. Large amount is not required for providing a post office in a village. It is not advisable for the Government not to open post offices on this pretext that there is emergency in the country at present. An all-out effort should be made to provide more postal facilities in the rural areas.

More powers should be given to Divisional and zonal advisory commitees. At present they have no powers and are therefore of no use.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) ; The Department of Communications discharged its duty veryably during the last elections. The staff worked ceaselessly in those days,

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.04 बजे म० प० पुनः समवेत हुई :

The lok Sabha reassembled after lunch at four Minutes past fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अनुदानों की मांगे–जारी

DEMANDS FOR GRANTS–Contd.

संचार विभाग-जारी

Shri Yamuna Prasad Mandal : More facilities should be provided to Class IV employees. School should be opened for the education of the children of the employees by this Department as is being done by the Railways.

No doubt, this Department did a commedable job during the last election, it has to go along way yet. More communication facilities should be Provided in the rural areas. At present influential persons in villages are inchrge of extra departmental post offices, this old system should be changed. Suitable persons with new out look should be made in charge of these post offices. It is of paramount importance to provide adequate postal and other communication facilities in the backward and border areas of our country.

Air Mail Servise should be expanded. So far as Air Mail service is concerned, State capitals should be linked with one another.

As at present, the P. and T. Board does not enjoy enough powers. Enough powers should be vested in it. It should be made an autonomous body.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : There are 5 lakh villages in our country and the hon. Minister can not deny this fact that about three-fourths of villages of our country do not have any postal facilities. Goveanment have failed to provide necessary postal facilities even after 20 years of independence. A programme should be drawn up to provide post offices in all the villages within two or three years.

The position in regard to telephone facilities is no better. There are long waiting lists of people who have applied for telephone connections, This is perhaps because of corruption. It plays its role there from the beginning to the end-i. e, from the sanctioning of the telephone to its installation and people in the cities can get telephone connections by giving them money. It is not understood that why the Government has not taken any concrete steps to enhance the production in the Indian Telephone Industries, Bangalore. At present there is, perhaps, an investment of Rs. 5 crores. It could have been increased to Rs. 10 crores so that internal requirements could be met and more foreign exchange could also be earned. The hon'ble Minister should consider this matter seriously.

The employees of the Telephone Department in Bombay have been insisting on the construction of a building in which all the telephones offices in Bombay could be accommodated. At persent these offices are located in different private buildings for which

probably heavy rents are being paid. It is understood that Government has purchased land for the building but the building has not yet been constructed. The Government should consider the demand of the employees and take a decision in the matter.

The telephone facilities as provided in the cities should also be extended to villages.

The factory of Indian Teleprinters is working for the last seven years. It is not understood that why Hindi Teleprinters of better quality could not be manufactured especially when Government has already decide l to switch over to Hindi ? Due to lack of Hindi Teleprinters there is shortage of Hindi News papers. At present they have to get the news translated and then get them printed in the Newspapers which takes time. The Communication Minister should him self feel the responsbility and take necessary steps to solve this problem.

The postmen of Posts and Telegraphs Department stopped their work at the commencement of rains because of nonavailability of umbrellas. They have also not been provided with unifroms, I would therefore ask the Government to provide more facilities to these employees. Their conditions of service should be improved.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हमारे देश में डाक सेवाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है जिसका मुकाबला आधुनिक युग के किसी भी देश से किया जा सकता है । पत्रों और तारों द्वारा अच्छे और बुरे समाचार भेजे जाते हैं, यह देश की बहुत महत्वपूर्ण सेवा है ।

चुनावों के दौरान इस मंत्रालय ने परिणामों की सूचना देने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की थी, उस पर संसार में कोई भी उन्नत देश गर्व कर सकता है । टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना कई स्थानों पर की गई है । मेरे जन्म स्थान चण्डोक में बहुत ही कम समय में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है । टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं और देश की जनता ने इस बात की बहुत सराहना की है । अन्तर्देशीय पत्रों की कमी है इसलिये मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने पीड़ित हरिजनों की जब सेवा की थी जब महात्मा गांधी का ध्यान इस समस्या की ओर गया भी न था । स्वर्गीय महाराजा राष्ट्रवादी एवं देश सुधारक थे । उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए । सरदार पटेल की स्मृति में डाक टिकट जारी कराने के लिए भी मुझे काफी कोशिश करनी पड़ी थी ।

पत्रों के वितरण में बहुत देर हो जाती है । इस प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । कई बार पत्र गलत स्थानों को भेज दिये जाते हैं और इसी कारण पत्र देर से पहुंचते हैं । गुजरात सर्किल में एक भवन 800 रुपये महीने के किराये पर लिया गया जब कि इस भवन का किराया 25 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होना चाहिए । मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस विभाग के कर्मचारी की, जो हिमाचल प्रदेश में कासा स्टेशन पर बीमार हो गया था, जान बचाई है । इस कर्मचारी को हवाई जहाज द्वारा चन्डीगढ़ लाया गया । यद्यपि इस कार्य में 10 हजार रूपये खर्च हो गये परन्तु इस प्रकार एक व्यक्ति की जान बच गई ।

श्री अब्राहम (कोट्टायम) : डाक-तार विभाग अपनी अकार्यकुशलता के लिये बदनाम है। इसकी स्थिति हाल ही में और बिगड़ गई है।

कार्यकुशलता के लिए प्रयाप्त संख्या में संतुष्ट कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सेवा की शर्तें भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे काम के लिए समय पर औजार उपलब्ध होने चाहियें। आज इन वस्तुओं में से वहां एक भी नहीं है। इस स्थिति के लिए बहुत ही खर्चीला नौकरशाही ढांचा उत्तरदायी है। केरल में तथा देश के अन्य भागों में कर्मचारियों की भारी कमी है। प्लेट फार्मों पर डाक-घर बनाने के लिए इमारतें देने के लिये तथा रेल गाड़ियों में डाक के डिब्बों की व्यवस्था करने के लिये उन्हें रेलवे पर निर्भर करना पड़ता है। परन्तु वर्षों गुजर जाते है, रेलवे विभाग रेल के डिब्बों की व्यवस्था नहीं करता।

डाक और तार बिभाग ने प्रशासन में परिवर्तन लाने के लिये जितने प्रयोग किये हैं, वे सेवामें सुधार लाने में असफल रहे हैं। रेलवे डाक सेवा में डाक और तार बोर्ड ने प्रादेशिक योजना आरम्भ की थी और तीन क्षेत्र बनाये थे। इसमें कई प्रकार की बाधायें पड़ी हैं और डाक प्रबन्ध बिलकुल अस्तव्यस्त हो गया है। कर्मचारी वर्ग इस योजना को समाप्त करने के लिए कह रहा है परन्तु अधिकारी वर्ग उसी के साथ चिपटा हुआ है। इसी प्रकार टेलीफोन विभाग में आर. डी. टी. योजना बहुत खर्चीली योजना है। डाक और तार विभाग के कार्यालयों के पुनर्गठन के कारण इस विभाग के कर्मचारियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इतना खर्च करने के बावजूद जनता की आशायें पूरी नहीं हो सकी। बार बार अभ्यावेदन भेजने के बावजूद एरणाकुलम और कोचीन के लोगों को स्वचालित टेलीफोन प्रणाली के टेलीफोन नहीं दिये। कोट्टायम के देहाती उप नगरों के लोगों को कोट्टायम में अपने मित्रों के साथ बात चीत के लिए ट्रंक काल बुक करना पड़ता है। कोट्टायम जिले के पूरे अडुम्बुचोला ताल्लुके में न तो कोई टेलीफोन का कार्यालय है न टेलीफोन है।

डाक और तार विभाग लेखन सामग्री प्रपत्र मोहरे, फर्नीचर, छंटाई की पेटियां, मोटर गाड़ियां, दूसुनी के थैले आदि वस्तुएं उपलब्ध नहीं कर सका। यह आश्चर्य की बात है कि केरल में रेलवे डाक सेवा के पास 29 दस्ती ट्रंकों की कमी है। जब तक ये ट्रंक उपलब्ध नहीं होते तब तक स्पष्ट ही कर्मचारी लोग काम नहीं कर सकते।

कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में रेलवे डाक सेवा के विश्राम घर के पास पर्याप्त आवास नहीं है। अमृतसर के विश्राम घर में भी आवास की कमी है। वहां बड़ी गन्दगी है। वहां पंखों का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये शोरानूर और इरोड में कोई विश्राम घर नहीं है। जिन डाक तार कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है। उन्हें विशेष प्रतिकर भत्ता प्रदान करने की मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। इसी कारण कर्मचारी लोग बहुत असन्तुष्ट है।

यद्यपि डाक और तार विभागों ने विभागीय औषधालय खोले हैं परन्तु उनका प्रबन्ध ठीक नहीं है। इस विभाग ने अपने भवन बनाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे निहित स्वार्थ वाले लोग खूब धन कमा रहे हैं। किराये पर भवन लेने के कारण हजारों रुपये किराये के रूप में खर्च किये जाते हैं। आवास की कमी के कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस विभाग ने अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये। मैंने त्रिचूर में देखा कि वहां के डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिए गये।

इसलिये डाक और तार विभाग में अकुशलता होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस समस्त विभाग में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। श्री नम्बियार और श्री नी० श्रीकान्तन नायर के कटौती प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इनमें निहित मांगों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : इस मंत्रालय के पास पांच विषय है, इनमें से डाक और तार विभाग के साथ जन साधारण का सम्बन्ध है। हमारे देश के दूरस्थ स्थानों पर भी डाक और तार की सुविधाएं पहुंचाई गई है। किसी भी देहात में चले जाये वहां एक प्राथमिक विद्यालय और एक लाल रंग का टीन का बक्स तो मिल ही जायेगा। यह लोकतन्त्र की सफलता है। संचार विभाग सार्वजनिक उपयोगिता का विभाग है। परन्तु इस विभाग में वाणिज्य का एक तत्व है। इस तत्व को पूरी स्वतन्त्रता तथा प्रभावशाली ढंग से काम करने देना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है कि टेलीफोन के बिल वर्षों तक इकट्ठे होते रहते हैं और यह बहुत बड़ी धन-राशि है। बकाया रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये नहीं तो यह विभाग प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकेगा।

संचार व्यवस्था के साथ-साथ यह विभाग अन्य रूपों में भी राष्ट्र की सहायता करता है। सामान्य बचत बैंक खाता के अतिरिक्त डाकघर विभिन्न बचत प्रमाण पत्रों को बेचते हैं और वित्तिय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये राष्ट्र की सहायता करते हैं। विभाग के लिये यह प्रशंसा की बात है कि जनता ने इस पर जितना विश्वास व्यक्त किया था उस पर वह खरा उतरा है। देश में इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी इतना ईमानदारी से काम करना कोई सरल बात नहीं है।

आधुनिक संसार में किसी देश का मूल्यांकन डाक-तार की व्यवस्था से लगाया जाता है। भारत को अपनी डाक की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना चाहिए, नहीं तो भारत के अन्य देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। प्रत्येक वर्ष डाक और तार की दरों में भी वृद्धि होनी चाहिये।

कई दृष्टियों से असम पिछड़ा हुआ और उपेक्षित क्षेत्र है। वहां की जनता की इच्छा के विरूद्ध पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय शिलाग में है जबकि राज्य का केन्द्रीय स्थान गौहाटी है और वहां नेफा, नागालैंड और मनिपुर से पहुंचना सरल है। परन्तु ऊंचे अधिकारियों के लाभ और आराम के लिये यह कार्यालय शिलाग में ही चल रहा है।

डाक विभाग में महान व्यक्तियों की स्मृतियों में डाक टिकटें जारी की जाती है परन्तु असम के किसी व्यक्ति की स्मृति में एक भी ऐसी टिकट जारी नहीं की गई है। इस प्रकार असम की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। असम के महान सपूत स्व० लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ की जन्म शताब्दी 1968 में मनायी जायेगी मैं आशा करता हूं कि यह विभाग इस अवसर पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेगा।

इस विभाग में पांच लाख के लगभग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं परन्तु असम की जनता को सेवा के बहुत कम अवसर दिये जाते हैं। इस कारण असम के युवकों में बड़ी निराशा है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Our Government have t me and again announced that progressive use of Hindi would be made in its departments. The Home Ministry have also announced that Union Public Service Commission will conduct its examination through regional languages. But it is only Posts and Telegraphs Department wherein Hindi is not being used at all. If no change can be made in the working of this Department even after the 20 years of achievement of independence and if this Department still wants to maintain **status quo**, the people will agitate against this. Wherever Hindi has not been used, Ministry of Communications is on the top. The annual report on the manufacture of teleprinters shows that 2700 teleprinters have been manufactured against the target of 2200 teleprinters, Will the hon'ble Minister let us know as to how many Hindi teleprinters are in demand and what was the production. These teleprinters will not only help the Hindi newspapers but they will also help Marathi and Gujrati newspapers. It has been agreed to by the Chief Ministers of all the States that Devanagari script should be used as alternative script. But if Hindi teleprinters are not made available then how Devanagari script will be used as common script. I want to know whether the Minister of Communications still feels the essentiality of Manufacturing English teleprinters and their is no need of Tetepr inters for our national languages ? As English is going to be replaced by Hindi and other Indian languages, the production of teleprinters should increase.

I congratulate the hon'ble Minister for introducing 'Namaskar' in place of 'good morning or good evening' on the telephones. But I may suggest that 'Namaskar' should **be substituated by** 'Namaste' which is grammatically more correct.

So far the telephones are concerned I would like to draw the attention of the hon'ble Minister that complaints are not properly looked into. Arrangements should be made to see that the telephones, which went out of order, were repaired quickly.

The Public Accounts Committee has asked the Ministry of Communications to make arrangements to recover the outstanding amounts of telephone bills which run into crores.

There should be more offices of Posts and Telegraphs in the villages. Their aim should be service of the nation and they should not be established simply by keeping in view the economic gains. There is deterioration in the telegraph service. Most of the telegrams are sent by post. To day people are more inclined to send their letters by Express Delivery instead of sending telegrams. I would, therefore, request that steps should be taken to improve the telegraph service.

It is good that Posts and Telegraphs Department has been issu ng commemorative stamps in the memory of Shivaji and Rana Pratap, the national heroes. They have issued many such stamps. Amar Shaheed Swami Shradhanand had also faced the bayonets of British soldiers and sacrilficed his life at Chandni Chowk, near Ghanta Ghar. I therefore, request that a commemorative stamp in the name of Swami Shradha Nand should be issued.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I support the demands of Posts and Telegraphs Department. I fully realise the difficulties experienced by the staff of this Department.

The employees of the Department of Posts and Telegraphs do not get proper facilities. They have to attend to what they call 'split duty'. They come to their jobs early in the morning and then reach their houses late in the evening. They are not provided with housing accommodation. This problem is more serious in big cities. Because of non-availability of Governmet accommodation, the employees live at distant places which is very inconvenient especially when they have to attend to their duties in the early hours.

It has been noticed that at several places the post offices are located in rental buildings and the staff has to work while standing because of shortage of acc mmodation. This seems to be unnecessary expenditure I would therefore suggest that the Department should construct their own building wherever necessary. The quarters for its employees should also be constructed at the head offices.

Our country and especially Madhya Pradesh is backward as we have introduced the facilities of posts and telegraphs very late. The postal facilities do not exist in the big Adivasi area. The Police Stations situated in the areas where Dacoits are active do not have telephone connections and telegraph facilities. The news of dacoities cannot reach the headquarters for days together. I therefore request that these areas should be provided with telephone connections and telegraph facilities. Arrangements should also be made to connect directly Beena with Tikamgarh which would establish direct contact with Bhopal. Similarly there should be telephone connections between other important Governmentd agencies.

श्री के० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : कल्याणकारी राज्य में कुछ ऐसे संगठन, उद्योग तथा ऐसी मूलभूत सेवायें होती हैं जिनकी व्यवस्था तथा जिनका नियन्त्रण राज्य करता है, ताकि जनता को उनसे अधिकतम लाभ पहुंच सके। डाक और तार विभाग निःसंदेह उन्हीं में से एक है। परन्तु यह विभाग जनता की सेवा के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं में डाक टिकट में वृद्धि करता जा रहा है। टिकटों के दर बढ़ाये जा रहे हैं, एक पैसे का पोस्ट कार्ड छ पैसे का कर दिया गया है। फिर भी वर्तमान बजट में यह कहा गया है कि यह विभाग घाटे पर जा रहा है। यदि बजट की निर्धारित राशि को देखा जाये तो पता चलता है कि इस विभाग को कोई घाटा नहीं, घाटा केवल इस लिये हुआ है कि पर्याप्त धन-राशि लाभांश तथा अन्य कार्यों में लगाई जाती है। इसके बावजूद भी इस विभाग को इस वर्ष 3 करोड़ रुपये का लाभ ही होगा। यदि हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो दरों की प्रस्तावित वृद्धि उचित नहीं है। लोगों पर इतने अधिक कर लगाये जाते हैं और फिर उस पर डाक की दरों में भी वृद्धि की जा रही है। बजट को संतुलित रखने में यह पूंजीवादी दृष्टिकोण है। कुछ भी हो यह समाजवादी दृष्टिकोण कदापि नहीं है।

डाक और तार विभाग अपनी कार्यकुशलता पर उचित ध्यान नहीं दे रहा। यह बात वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से बिल्कुल स्पष्ट है। टेलीफोन बिल की धन राशि वसूल नहीं की जाती। टेलीफोन विस्तार योजनाओं के पूरा करने में पर्यवेक्षण की भी कमी है। इसलिये जितनी आय होनी चाहिये, नहीं होती। सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध करनी चाहिये। जिस खर्च को केवल लाखों पर किये बिना काम चल सकता है, उस खर्च को भी किया गया है, उसकी बचत नहीं की गई। इस मामले की भी जांच की जानी चाहिये।

इस विभाग के बहुत से अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं जिनके वेतन और भत्ते बहुत कम हैं। इसके साथ साथ उन्हें अधिकारियों की दया पर रहना पड़ता है। यह गरीब लोगों का शोषण है। अधिकारी लोग इन अभागे कर्मचारियों को तंग करके मौज उड़ाते हैं। सरकार को उनके मामलों पर सहानुभूति पूर्ण तरीके से विचार करना चाहिये और उनकी सेवाओं को नियमित कर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन कर्मचारियों को अधिकारी वर्ग नौकरी से निकाल देने की धमकी देता रहेगा और उनका शोषण होता रहेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सारे मामले की जांच करें।

जिस प्रकार की सुविधायें अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलती है, वे सभी इस विभाग के कर्मचारियों को भी उपलब्ध की जानी चाहिये। इन्हें चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिये भी काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मंत्री महोदय को उन्हें महंगाई भत्ता देने पर भी विचार करना चाहिये क्योंकि वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि देहातों में डाक और तार में संचार की सबसे प्राचीन वाहक प्रणाली है। रेलवे स्टेशन से देहात तक पहुँचने के लिये साइकिल तक नहीं दिया जाता। आज भी बहुत से गांव हैं जहां केवल अतिरिक्त विभागीय डाक-घर हैं और यही आस पास के देहातों का काम चलाते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि ये डाक-घर समाप्त करके उनके स्थान पर उप-कार्यालय स्थापित किये जायें, जिससे टेलीफोन, तार, बचत बैंक जैसी अन्य सुविधायें उपलब्ध हो सके। इन देहातों में यदि कोई आपात कालीन स्थिति पैदा हो जाये तो समय पर पुलिस तक को नहीं बुलाया जा सकता। नगरों में इतनी अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु देहातों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैंने इतने पत्र लिखे हैं फिर भी हमारे गांव में एक उप-डाक कार्यालय नहीं खोला गया। इन कठिनाइयों के कारण देहाती क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : जहां कहीं भी डाक और तार विभाग अनिवार्य सेवा के काम को पूरा नहीं कर सकता वहां इस विभाग को सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये खर्च को लौटा देना चाहिये। उन्नत देशों में भी यही तरीका है। कोई भी व्यक्ति एक या दो रुपये के लिये विभाग के साथ पत्र-व्यवहार में समझ कर ही करना चाहिये। अतः विभाग को स्वयं यह काम करना चाहिये। मंत्री महोदय को स्वयं इस दिशा में कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

डाक तथा तार विभाग एक सार्वजनिक उपयोगिता विभाग है। अतः इसे लाभ अर्जित करने के आधार पर नहीं चलाया जाना चाहिए। हानि को पूरा करने के लिए तार व टेलीफोन की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। परन्तु इतनी अधिक दर देने के पश्चात भी उतनी अच्छी सेवा प्राप्त नहीं होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए तार तथा टेलीफोन सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

डाक तथा तार विभाग में खादी के प्रयोग को समाप्त कर हथकरघा अथवा अन्य प्रकार के मिल के सस्ते कपड़े का प्रयोग किया जाना चाहिए। खादी का प्रयोग शायद खादी आयोग को प्रोत्साहन देने के लिये किया जा रहा है। परन्तु ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं बंगलौर टेलीफोन उद्योग तथा टेलीप्रिन्टर उद्योग की सराहना करता हूँ। ये उद्योग दक्षता से कार्य कर रहे हैं तथा अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसलिए इन उद्योगों में अधिक धन लगाकर इनको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ये न केवल विदेशी मुद्रा ही अर्जित करें बल्कि अपने देश की मांगों को भी पूरा कर सकें।

हमने इस आशा में कि निकट भविष्य में एक स्वयचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जायेगा निजामाबाद में स्थान प्राप्त करने में डाक तथा तार विभाग की सहायता की थी। परन्तु इसके लिए अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। निजामाबाद से लगभग 16 मील दूर दो टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो प्रायः खराब रहते हैं।

निजामाबाद के निकट किशन नगर में 1966 में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु इस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि तांबे की तार उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन सभी बातों की ओर ध्यान दें।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) कटौती प्रस्ताव संख्या 74 तार विभाग के यातायात सम्बन्धी कर्मचारियों की बीमारी की छुट्टी को छूट-दिवस समझने के बारे में है। जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो माननीय मन्त्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि ऐसा नहीं किया जायेगा। परन्तु ऐसा किया जा रहा है चाहे बीमारी की छुट्टी के समर्थन में डाक्टर का प्रमाणपत्र ही क्यों न दिया गया हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसी छुट्टी मंजूर की जानी चाहिए।

कटौती प्रस्ताव संख्या 75 तार बाबुओं के वेतनमान के पुनरीक्षण के प्रश्न को मध्यस्थ को सौंपने के बारे में है। माननीय मन्त्री इस बात के लिए सहमत हो गये थे अतः इस मामले को एक सदस्यीय न्यायाधिकरण को सौंपकर माननीय मन्त्री को अपना वचन निभाना चाहिए।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव अखिल भारतीय तार और टेलीफोन कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी) के संघ की मान्यता को समाप्त करने सम्बन्धी 'कारण बताओ नोटिस' को वापिस लेने के बारे में हैं। मेरा निवेदन है कि इस कारण बताओ नोटिस को वापिस ले लिया जाये।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों के समान ही समझा जाये ।

{श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए}
{Shri C. K. Bhattacharya *in the Chair*}

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : There were only 72 Hindi teleprinters out of the total of 5314 teleprinters which were available upto 31st December, 1966. I would request the hon. Minister to make available more Hindi Teleprinters as Hindi is a national language.

It is difficult to post examination papers to other places from Pandria and Lokhi as proper post offices facilities are not available there. Baloda post office should be converted into sub-post office. Telegram and telephone facilities should also be provided in that post office.

I would also request the hon. Minister to incerease the rate of interest under the postal insurance from 3.5 percent to 4.1 percent. This will attract more persons towards this scheme.

More powers should be given to the Departmental Committees so that they could meet the needs of the employees. I would also say that only those persons should be appointed to these Committees who have the knowledge of the working of the department with this words I conclude.

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : भारत जैसे विकास कर रहे देश के लिए संचार बहुत ही आवश्यक है । परन्तु यह खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात भी हमारी संचार व्यवस्था पिछड़ी हुई है । यदि देश की समृद्धता के साथ-साथ संचार व्यवस्था का विकास नहीं किया जाता तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता ।

भारत जैसे देश को जिसको पाकिस्तान तथा चीन से खतरा है अपनी संचार व्यवस्था का तेजी से विकास करना चाहिए । सैनिक दृष्टि से भी ऐसा किया जाना आवश्यक है । देश की ट्रंक काल सेवायें बहुत खराब है । बीकानेर, जोधपुर अथवा जैसलमेर में ट्रंक काल करने के लिये दो अथवा तीन दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस कठिनाई के बारे में मन्त्री महोदय को बताया गया था । हमें यह बताया गया है कि तारों की चोरी के कारण ऐसा हु ा है । परन्तु सचाई यह है कि ट्रंक सेवाओं में कुछ मूलभूत त्रुटि है । मेरे विचार में इस मामले को आश्वासनों सम्बन्धी समिति को सौंप दिया जाना चाहिए । यदि दिल्ली से बम्बई ट्रंक काल करनी हो तो गरीब व्यक्ति को अपना आधा वेतन देना पड़ता है । परन्तु यदि साधारण काल बुक कराई जाये तो वह काल ही नहीं मिलती । आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान देंगे तथा साधारण कालों को भी किसी प्रकार की प्राथमिकता दी जायेगी ।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि बहुत सी तारों को डाक द्वारा भेजा जाता है । आमतौर पर तारों से पत्र जल्दी मिल जाते हैं । यदि तारों को डाक द्वारा भेजा जाये तो तार की राशि को वापिस कर दिया जाना चाहिए ।

डाक विभाग के बारे में मेरा अनुभव है कि लगभग दस प्रतिशत डाक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचती। आमतौर पर हमें पत्र की दो प्रतियां भेजनी पड़ती है जिससे एक तो पहुंच जाये। डाक तार तथा टेलीफोन सेवाओं में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय बतायें कि वह किस प्रकार आवश्यक परिवर्तन करेंगे जिससे भारत प्रगति कर सके।

Shrimati Laxmi Bai (Medak): Telephone facilities are not available in the Narainkhed and Ramayanpat Talukas in my constituency. Although the poles were erected at the time of the general elections yet not even a single telephone has been installed there so far. These areas have also not been connected with the railways. I would request the hon. Minister to pay attention and provide necessary facilities to these backward areas.

The Post and Telegraph department is not working efficiently at all. I have to ring 20 to 25 times to get a connection for trunk call The employees do not care for M. Ps. like me. Generally the operators connect the wrong numbers which causes great inconvenience. Necessary steps should be taken to bring improvement in department.

The operators also do not behave properly with the ladies and sometimes they even disturb in the middle of night. I have recived many complaints in this matter and have been asked to raise the matter in Parliament.

There is also a practice to ask for a 'Baksheesh' on various festivals by the postmen. This wrong practice should be stopped.

श्री धीरेन्द्रनाथ देव (अंगुल) : 5 जुलाई 1967 के अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता में डाक विभाग में एक कांड का पता लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि डाक तथा तार विभाग में सब ठीक नहीं है।

पिछले बीस वर्ष से हम देख रहे हैं कि डाक तथा तार विभाग की कार्यकुशलता में कमी आ रही है। डाक की वस्तुओं के वितरण के कार्य के महत्व को समझा नहीं जाता है। बुक-पोस्ट द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुयें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पत्र-पत्रिकाएं तथा कलैण्डर मार्ग में ही गुम हो जाते हैं।

ऐसा बताया जाता है कि जनसंख्या तथा पढ़ाई-लिखाई में वृद्धि के कारण डाक विभाग के कार्य में भी असाधारण वृद्धि हो गई है परन्तु कार्य में वृद्धि के अनुसार कर्मचारी वर्ग में वृद्धि नहीं की गई है।

घाटे को पूरा करने के लिए दरों में वृद्धि की जा रही है यद्यपि इस विभाग की कार्य-कुशलता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस आयव्ययक में भी डाक की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि टेलीफोन उद्योग को 74.33 लाख रुपये का लाभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि यदि इस उद्योग को अधिक कार्यकुशलता से चलाया जाता तो हम अधिक मुनाफा अर्जित करने के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते थे। निर्यात की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि कुछ

विदेशी सहयोगियों के साथ हिन्दी टेलीप्रिन्टर बनाने के लिए करार किया जा रहा है। इस कार्य को तेजी से किया जाना चाहिये। हिन्दी टेलीप्रिन्टरों की अनुपस्थिति में समाचार भारती को समाचार भेजने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

माननीय सदस्य श्री सरजू पाण्डेय ने डाक तथा तार बोर्ड के सदस्यों की आलोचना की है परन्तु उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसकी जांच की जा सके। उन्होंने आसनसोल से 1959 में भेजे गये एक मनीआर्डर की बात कही है परन्तु उन्होंने सम्बन्धित कागज अभी तक मुझे नहीं दिये हैं।

डाक तथा तार विभाग देश के प्रत्येक भाग की सेवा करता है। इसी प्रकार हमारा समुद्र-पार विभाग भी विश्व के प्रत्येक भाग में पत्र पहुँचाता है।

आयव्ययक प्राक्कलनों में वर्ष 1967–68 के लिये राजस्व प्राप्ति का अनुमान 182·62 करोड़ रुपये लगाया गया है। परन्तु गत वर्ष के अन्तिम महीनों में राजस्व की प्राप्ति आशानुसार नहीं हुई। यदि यह प्रवृति चालू रही तो चालू वर्ष में राजस्व की प्राप्ति लगभग 177 करोड़ रुपये ही होगी। इस प्रकार हमें पुनर्नवन आरक्षण निधि में बकाया अंशदान का 3 करोड़ रुपया तथा बकाया लाभांश का 1·62 करोड़ रुपया देने में कठिनाई होगी क्योंकि 1966-67 के पुनरीक्षित अनुमान में डाक तथा तार शाखाओं के कार्य-संचालन के बारे में क्रमशः 8·5 करोड़ तथा 5·9 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। गजेन्द्रगड घर आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से भी चार करोड़ रुपया का खर्च बढ़ जाने का अनुमान है।

कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषकर श्री शशिरंजन ने छोटे समाचार पत्रों को कुछ रियायत देने की मांग की है। सरकार इसके महत्व को समझती है तथा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

टेलीफोन की बकाया राशि वसूल करने के बारे में विभाग को अनुदेश दिये गये हैं कि उन लोगों को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाये जिनसे 1 जनवरी, 1965 से पूर्व की बकाया राशि अभी वसूल करनी है। यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि यह कार्य 20 अगस्त तक समाप्त हो जाना चाहिये। मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि बकाया राशि में निरन्तर कमी हो रही है। इस वर्ष के अन्त तक या तो सभी बकाया राशि वसूल कर ली जायेगी अन्यथा जिन्होंने राशि जमा नहीं कराई उनके कन्कशन काट दिये जायेंगे चाहे वे टेलीफोन सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी, दिल्ली में इस समय लगभग 63,000 टेलीफोन हैं जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत की और राशि बकाया है।

स्वतन्त्रता से पूर्व केवल 22,116 डाकघर थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 93,000 हो गई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। यह इस प्रकार है

कि 9500 डाकघर देहातों में तथा 2500 डाकघर नगरीय क्षेत्रों में खोले जायेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहाड़ी, जंगली तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाक की सेवाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।

दूर-संचार सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से हम उपग्रह संचार सेवा भी आरम्भ करना चाहते हैं। भारत में ग्राउण्ड स्टेशन स्थापित करने के कार्यवाही की जा रही है ताकि विश्वजननीय उपग्रह संचार व्यवस्था में भाग लिया जा सके। इस उद्देश्य हेतु पूना के निकट अरबी में भूमि अर्जित कर ली गई है। आशा है कि 1968 के उत्तरार्द्ध में यह स्टेशन स्थापित हो जायेगा। उसी समय हिन्द महासागर में उपग्रह छोड़ने का भी प्रस्ताव है।

डाक, तार तथा टेलीफोन की दरों को तदर्थ आधारों पर निर्धारित किया गया हैं। मैं नहीं चाहता कि उनको आगे भी इसी प्रकार रखा जाये, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाये जो टरिफ ढांचे की जांच करे। यह समिति समय-समय पर टैरिफ नियत करने के सिद्धान्तों की जांच करे तथा विभिन्न सेवाओं की आर्थिक स्थिति की विवेचना भी करे। यह समिति व्यापार तथा उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा डाक-तार विभाग के वाणिज्यिक ढांचे को देखते हुए टैरिफ लगाने के सिद्धान्त बनायेगी। नये क्षेत्रों में डाक तार सेवाओं को बढ़ाने के उपाय भी इस समिति द्वारा सुझाये जायेंगे। सेवाओं को प्रभावशाली बनाने तथा विभाग की वित्तीय स्थिति को सुधारने के बारे में भी उपाय बताये जा सकते हैं।

बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में पहले ही कुछ कार्यवाही की जा चुकी है। सदस्य (वित्त) तथा इसकी तुलना में डाक-तार बोर्ड की स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया है। रेलवे बोर्ड के आधार पर वित्तीय कार्य को बोर्ड के साथ मिलाने का निश्चय किया जा चुका है। इस निर्णय को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा। मामलों को तुरन्त निपटाने के लिये डाक-तार बोर्ड तथा पोस्ट-मास्टर जनरलों को वित्तीय अधिकार देने का भी विचार है। इन सभी बातों के अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को देखते हुए बोर्ड के ढांचे की ओर अधिक जांच की जायेगी।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमिटेड में हिन्दी के टेलीप्रिन्टरों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जायेगा।

ढेकांनाल तथा कटक आदि में डाक भेजने के लिए राज्य परिवहन की बसों का प्रयोग किया जा रहा है।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

ढेंकानाल और अठमाल्लिक डाक-घर भूतपूर्व रियासत के भवनों में स्थित हैं। हमारा विभाग उड़ीसा की राज्य सरकार से इन भवनों को खरीदने के बारे में बातचीत कर रहा है।

डुलउर का मुख्य डाक-घर इस समय किराये के दो भवनों में अपना कार्य कर रहा है। विभागीय इमारत के निर्माण का कार्य गुजरात राज्य के लोक कर्म विभाग को सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। और हम राज्य सरकार पर इसी वर्ष भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये दबाव डाल रहे हैं।

जहां तक लिफाफों और अन्तर्देशीय पत्रों की कमी का सम्बन्ध है मैं इसका पता लगाऊंगा और मैं इनकी कमी दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं इनके रंगों को भी बदलने का प्रयत्न करूंगा। जैसाकि श्री सोगवने ने कहा है कुछ गांवों के डाक-घरों का स्तर बढ़ा दिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कठिनाइयों का हवाला दिया था। उन्हें दिन में पांच घंटे से अधिक काम नहीं करना पड़ता। उन्हें विभागीय राजन समिति की सिफारिशों के अनुसार परिश्रमिक मिलता है। हम उनकी कठिनाइयों को यथा सम्भव दूर करेंगे। 31.3.66 को अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 1,74,000 थी।

श्री के० एम० अब्राहम ने एरणाकुलम और कोचीन में स्वचालित टेलीफोन लगाने के लिये कहा है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि कोचीन में पहले ही 2,400 लाइनों की क्षमता वाला स्वचालित एक्सचेंज है और एरणाकुलम में भी शीघ्र ही इसे स्थापित किया जा रहा है। वहां पर एक नये भवन का निर्माण हो गया है और उपकरणों की स्थापना की जा रही हैं। वर्ष 1968 के दौरान 3,000 लाइनें चालू की जाने की सम्भावना है। इसकी क्षमता और बढ़ाने के लिये 5,000 लाइनों के लिये उपकरण मंगवाये जा रहे हैं यह काम वर्ष 1969 में पूरा हो जायेगा।

आसाम और उसके आसपास के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक और तार की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक स्मृति टिकट जारी करने का सम्बन्ध है, मैं इस पर विचार करूंगा। जहां तक हैदराबाद और दिल्ली के बीच ट्रंक-काल की शिकायतों का सम्बन्ध है, मैं प्रयत्न करूंगा कि वे दूर की जा सकें। मैं यह भी महसूस करता हूं कि निरीक्षण संस्था को उचित ढंग से सुदृढ़ किया जाना चाहिये जिससे वास्तविक और कुशल कार्यसंचालन सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय सेवा में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त हम इस विभाग में एक कुशलता ब्यूरो की स्थापना करने जा रहे हैं। मैंने विभाग को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कहा है और वे इस पर अमल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस विभाग तथा इसके कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का उचित विश्लेषण किया जाये और उन्हें और अधिक कार्य करने की प्रेरणा दी जाये।

प्रशुल्क समिति इस बात का समय निश्चित करेगी कि तार या मनीआर्डर कितनी देर में सम्बन्धित व्यक्ति को मिल जाना चाहिये। हम इस बात को सुनिश्चित बताना चाहते हैं कि भारत के किसी भी कोने में एक सप्ताह के अंदर मनीआर्डर सम्बन्धित व्यक्ति को मिल जाये। इसी प्रकार तार 12 घण्टे के अन्दर अन्दर मिल जानी चाहिये।

जहां तक मकान और दूसरी सुविधाओं का सम्बन्ध है यह ठीक है कि इस समय मकान सम्बन्धी सुविधायें केवल 4.2 प्रतिशत कर्मचारियों को ही प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में हमने चालू योजना में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर हम इस सम्बन्ध में और धन की व्यवस्था करेंगे।

कल्याण कार्यों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समय लगभग 9 औषधालयों की व्यवस्था है और हम इन सुविधाओं में आगे सुधार करते रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे की तरह डाक और तार विभाग ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां पहले ही चालू कर दी हैं। इन छात्र-वृत्तियों की धन-राशि पृथक पृथक निर्धारित की गई है। बाद में इस धनराशि में वृद्धि भी की जायेगी।

पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष के दौरान तथा आम चुनावों के दौरान डाक और तार विभाग ने प्रशंसनीय ढंग से काम किया है। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखूंगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संचार विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following demands in respect of Department of Communications were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
93	संचार विभाग	8,34,000
94	समुद्रपारीय संचार सेवा . . .	1,55,68,000
95	डाक और तार विभाग (कार्य चालान व्यय) .	1,17,09,67,000
96	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग .	13,61,86,000
97	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	21,60,000
142	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	38,42,00,000
143	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय .	1,15,57,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की मांग संख्या 32 से 37, 121 और 122 पर चर्चा तथा मतदान होगा। जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं वे कटौती प्रस्ताव की संख्या बताते हुए 15 मिनट के अन्दर पर्चियां भेज सकते हैं।

वर्ष 1967-68 के लिये खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
32	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	99,29,000
33	कृषि	6,17,89,000
34	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां . .	11,00,39,000
35	सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	7,60,000
36	वन	1,07,63,000
37	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	25,60,04,000
121	अन्न तथा उर्वरक की खरीद . . .	4,76,61,76,000
122	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	21,10,59,000

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : खाद्य के मामले पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्य समस्या परमात्मा की नहीं मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण में छपे आंकड़ों से पता चलता है कि इस सरकार ने जो कुछ किया है उसका परिणाम उलटा ही निकला है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार का यह दावा बिल्कुल निराधार है कि खाद्य समस्या के लिये देश की जनसंख्या, सूखा और खाद्य-बीज आदि की कमी उत्तरदायी है।

इस समय प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि 14.2 औंस है और खाद्यान्न का वर्तमान मूल्य सूचक अंक 215 है तथा अन्य खाद्य पदार्थों का मूल्य सूचक अंक 252 है। जब वर्ष 1952 में केवल 13.9 औंस की उपलब्धि थी, मूल्य सूचक अंक केवल 100 था। इसलिये उपलब्धि और मूल्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरा प्रश्न जन-संख्या का है। यदि राशन की औसत लगाई जाये तो वह 18 औंस बैठता है क्योंकि बच्चे और बूढ़े जिनकी संख्या कुल जनसंख्या की एक तिहाई है बयस्कों से आधा अन्न खाते हैं। परन्तु इसके बावजूद हमारे यहां भुखमरी की स्थिति है इससे यह सिद्ध हो जाता है कि खाद्य समस्या सरकार की नीतियों का परिणाम है।

हमारी सरकार खाद्य की समस्या के लिये वर्षा को उत्तरदायी मानती है। इस देश में कहीं न कहीं सूखे की स्थिति बनी रहती है। कई बार पहले वर्षा अच्छी होती है परन्तु बाद

में इतनी अधिक होती है कि सारी फसल नष्ट हो जाती है। मैं यह मानता हूँ कि बिहार में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर अनाज की कमी है। परन्तु इस कमी के लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है। वास्तव में इसके लिये अनाज के लाने ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध भी उत्तरतायी हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की क्रय-शक्ति नहीं है और क्रय-शक्ति का अभाव मूल्यों में वृद्धि के हो समान है।

तीसरा प्रश्न खाद-बीज आदि की कमी का है। सरकार इस सम्बन्ध में सदा दावा करती रही है कि वह भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु खाद-बीज आदि की इस व्यवस्था के बावजूद गत 10 वर्षों में उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है? उत्पादन की स्थिति तो पहले जैसी ही है। सिंचाई की सुविधाएं जुटाने के बावजूद और अधिक पानी की व्यवस्था होते हुए भी उत्पादन में वृद्धि क्यों नही हो सकी। फिर सामुदायिक परियोजनाओं पर खर्च 90 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गया है। फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। इस स्थिति को एक और तरीके से भी स्पष्ट किया जा सकता है। वर्ष 1952-53 में जब सरकार ने नियंत्रण हटाये गये तब वर्ष 1956 तक उत्पादन के सूचक अंक में 20 की वृद्धि हो गई थी और मूल्यों के सूचक अंक में 6 की कमी हो गई थी। परन्तु वर्ष 1956 में जब सरकार ने पुनः नियंत्रण लागू कर दिये तब उत्पादन के सूचक अंक में 10 की वृद्धि हुई। परन्तु मूल्यों में 16 अंकों की वृद्धि हुई। वर्ष 1963 से अब तक हमारे उत्पादन में 10 अंकों की गिरावट आ गई है और मूल्यों के सूचक अंक में 115 अंकों की वृद्धि हुई है। हमारे देश के इतिहास में चार वर्षों के अन्दर मूल्यों में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि वर्ष 1963 में सरकार ने अपनी खाद्य नीति में कुछ परिवर्तन किये थे। पहला परिवर्तन वसूली के बारे में था। वसूली के कार्यक्रम में चावल के साथ साथ गेहूँ तथा अन्य मोटे अनाजों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस बात को महसूस नहीं किया गया कि इन अनाजों पर नियन्त्रण न होने से ये चावल की कमी को दूर करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि कमी वाले राज्यों में भी वसूली का कार्यक्रम लागू किया गया। यह कठोर ही नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण बात भी है।

राशन प्रणाली चालू करने से काफी अनाज बेकार चला जाता है। हाल ही में केवल दिल्ली में 500,000 जाली कार्ड पकड़े गये हैं। ऐसे लोगों ने भी अपना राशन लिया जो होटल में खाना खाते हैं। इसलिये राशन व्यवस्था एक धोखा है। जिन व्यक्तियों को वास्तव में अनाज की आवश्यकता है उन्हें खाने को नहीं मिलता। मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस काम में सरकार भी पीछे नहीं रही है क्योंकि उन्होंने अपनी वसूली के मूल्य बढ़ा दिये हैं। यह स्वाभाविक ही है कि जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो लोग अपना अनाज नहीं बेचते। जिसका परिणाम यह होता है कि अनाज की जमाखोरी होने लगती है।

जो कुछ वर्ष 1963 में हुआ है उसे अब समाप्त किया जा सकता है। सरकार आगामी तीन महीनों में वसूली और प्रतिबन्धों को स्थगित कर सकती है क्योंकि इन महीनों में वर्षा होगी और बाजार में अनाज नहीं आयेगा। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि तीन महीनों में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो सरकार पुनः नियन्त्रण लागू कर सकती है।

सरकार का यह विचार है कि वह उत्पादन के जोरदार कार्यक्रम, अच्छे बीज तथा अधिक उर्वरकों आदि की सहायता से कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति लाने में सफल हो जायेगी। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं इतना बता देना चाहता हूं कि योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है और केन्द्रीय सरकार राज्यों को इतनी सहायता नहीं देती। खाद्य मंत्री को चाहिये कि वह राज्यों को अधिक सहायता देने के लिये वित्त मंत्री पर दबाव डाले और उनसे कहे कि सिंचाई के लिये जितने धन की आवश्यकता हो, वे दे। आपने कुछ दिन पूर्व कहा था कि बोकारो योजना पर जो 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला है, वह न किया जाये तो सिंचाई की सभी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। खाद्य मंत्री वित्त मंत्री से अधिक सहायता के लिये कह सकते हैं।

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी भूमि का 1/7 भाग खेती योग्य परती भूमि है। ऐसी भूमि उन व्यक्तियों को दे देनी चाहिये जो इस पर खेती करना चाहते हों जिससे उसमें कुछ उत्पादन हो सके। यदि लोग खेती करें तो वे उस पर मजदूर लगायेंगे और अन्न उत्पन्न करेंगे।

मैं एक और बात यह कहना चाहता हूँ कि मद्य निषेध को समाप्त कर देना चाहिये। क्योंकि यह नीति अब एकदम पुरानी पड़ गई है।

अब मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि मितव्ययता कैसे की जा सकती है। वित्त मंत्री ने करों में वृद्धि करके एक प्रकार से मुद्रा-स्फीति का कार्य आरम्भ किया है क्योंकि करों में वृद्धि से खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 232 बिन्दुओं से 253 बिन्दुओं तक वृद्धि हो गई है। 115 करोड़ रुपये के करों के कारण पिछले 6 सप्ताहों में, मूल्यों में 21 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अभूतपूर्व है। यह स्थिति तब है जब कर अभी वास्तव में लगे नहीं है। 115 करोड़ का खर्च तो सरकार के कुल खर्च का दो प्रतिशत है जो विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययता से पूरा किया जा सकता है। क्या यह कोई कठिन कार्य है? खाद्य मंत्रालय में अधिकारियों की संख्या गत वर्ष 247 थी जो अब बढ़ा कर 360 कर दी गई है। हम मितव्ययता की बात सोच रहे हैं और उधर मंत्रालय के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुदान 7.6 करोड़ से बढ़ा कर 12.8 करोड़ रुपये कर दिया है। फिर 24 करोड़ रुपये का उपबन्ध अनाज के व्यापार में हानि के लिये किया गया है। कृषि की नई योजनाओं के लिये अनुदान एक करोड़ से तीन करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च के लिये अनुदान 2.6 करोड़ से बढ़ा कर 6.3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस करोड़ों रुपये के खर्च के बिना भी काम चल सकता है।

मेरा यह अनुरोध है कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं, उन पर विचार किया जाये। यदि उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाये।

Shri T. Ram (Araria) : Our agricultural policy has proved unsuccessful during the last twenty years, The condition of the agricultural labour remained pitiable as it was wheh we achieved our independence. He is still poor, burdened with loans and was victimised and exploited. Unless his condition is improved, no measure could bring about any remarkable increase in the production of foodgrains. The purpose of land holdings has not been served. The main reason is that we, the representatives of the people do not realise the difficulties of cultivators. and the labourers, We get the votes of depressed class but do not pay attention to their plight. So long agricultural landless

labourers are not provided with land, till then land holdings cannot be proved effective. In case we cannot encourage the labourers, how can we expect that they will bring any increase in production. I would appeal to the hon'ble Food Minister to take effective steps for land holdings and besides consolidation of holdings should also take place.

The question of food problem should not be considered at State level. There must be a national policy of agriculture which should apply to the whole country. I cannot understand this zonal system and restrictions on the movement of foodgrains. When people of Bihar are starving why the foodgrains of Punjab cannot be sent there ? They also belong to the same country, I therefore want to say that this zonal system should go.

I would ask the Government not to depend on the businessmen in the matter of food. Government should play active roll in this respect. This Government claims to be in favour of socialistic pattern of society. In order to stop malpractices of traders and exploitation of the cultivators, the Government should take over trade in foodgrains. There is food crisis in the country not because there was shortage of food but because of ineffective control and ineffective control and inefficient distribution machinery. Any quantity of foodgrains is available in the black market. If foodgrains are not available then from where these stocks are coming in. The Government should fix a ceiling price and take stern measures against those who indulge in profiteering. Irrigation is most important for agriculture. Irrigation facilities should be stepped up even if we have to give up certain other projects. We should give up our policy of indecision and take effective steps in the matter. I would suggest that there should be a ceiling of 15 acres of irrigated area of land for a family. The labourers working on the land should get atleast two acres of land. They should also be provided with plough, bullocks, inputs etc. by the Government. Government should also provide food for four months or till the next harvest. Such revolutionary steps could only solve this problem.

In the programme of community development demonstration farms were supposed to set an example for the farmers. But with all the improved methods used therein, the farms have failed to show results which could encourage the farmers to adopt these means. The farmers then followed the old methods and its yield was much more.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : The intensity of famine in Bihar is so ghastly that it has turned that State into a cremation ground. It is very unfortunate that even after twenty years of our independence, we have been able to achieve a mere twenty percent increase in food production. To-day we have to import 2½ times more foodgrains than we used to import twenty years before. Inspite of the huge amount being spent on the imports under P. L. 480. There had been no substantial increase in the food production. The reason is not far to seek. Wrong policies of the Government have come up as a wall between the land and the cultivator. The Government should have paid more attention to the needs of the land and they should have tried to know the needs of the farmers. Instead of meeting them by way of more water, improved seeds and techniques, the Government have done more paper and desk work. If the money spent on the imports of foodgrains had been spent on increasing agricultural facilities, we would have been able to solve the food problem.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Dy. Speaker *in the Chair*}

We should consider the question of providing bullocks to the farmers since have not yet been able to switch over to mechanised farming. At present 25,000 tractors are

being used in Punjab, but there is not a single tractor factory in that State. There are no proper facilities for the repairs of these tractors.

It is unfortunate that the percentage of agricultural production from unirrigated land is the same as from irrigated land. The Government should have been able to get more production from irrigated lands by way of double crops etc.

While creating more capital by way of tractors, we must make the best use of existing capital, namely the bullocks. Thousands of tractors are not being used due to shortage of spare parts while the quality of bullocks has deteriorated due to wrong policies of the Government,

The old plan of seed farms has failed because politics was involved in such farms. It is now proposed to set up bigger seed farms. The experiment of Suratgarh farm in Rajasthan has shown that these are bound to fail. It will be better for the Government to give up such schemes.

Hybrid seeds require double the resources in the form of water and fertilizers than the conventional variety of seeds. If we have not been able to provide those resources in sufficient quantity even for the old variety of seeds, how will be able to meet the requirements of those inputs for the new hybrid varieties.

All these difficulties arise because the Plans are not made with the interests of villages in view. Punjab is suffering from the problem of water-logging and floods have become a permanent feature. The Government should do something to resolve this crisis.

It is unfortunate that in our country tillers of the soil are not the owners of the soil. The tiller should have the ownership of the land, if we want him to produce more. The farmer must be paid a remunerative price for his produce. The land reforms have not benefitted the farmer in any way. He is not the owner of the land, the farmer is not compensated for his labours and he does not get a good price for his produce. The crisis in the production of sagar is a result of injustice to the farmer.

There should be a uniform agricultural policy for the whole of the country. The zonal system must be scrapped because it results in wasteful expenditure and smuggling and has done a great harm to the country. A meeting of the representatives of all the parties should be convened in order to evolve a national agricultural policy.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषक देश का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि की उपज में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि कृषकों की दशा में सुधार हो। कृषकों का वर्षों से शोषण किये जाने के कारण वे असन्तुष्ट हैं, नक्सालबाड़ी इसका एक उदाहरण है, कृषकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये। यदि कृषकों का शोषण बन्द नहीं होगा, तो हमें एक और क्रान्ति का सामान करना होगा।

फसल पैदा करने के लिये कृषकों को लगभग 45 रुपये प्रति बीघा व्यय करने पड़ते हैं परन्तु उन्हें केवल 30 से 35 रुपये प्रति बीघा की ही आय होती है। कृषकों की वित्त सम्बन्धी

आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी समितियां भी असफल रही हैं। उन्हें लम्बी अवधि के लिये कम ब्याज पर अधिक ऋण मिलने चाहिये, कृषि वित्त निगम स्थापित करने से उनकी आवश्यकता पूरी होगी। फसल का बीमा यथासम्भव शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये। बाढ़ों को रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। वर्षा ऋतु आरम्भ हो गई है और लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि बाढ़ों से फसल को अग्रंतर हानि न होने पाये।

कीटाणुओं तथा पौधों के रोगों के कारण हमारी 20 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। इसें रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये। हमारी 20 करोड़ एकड़ भूमि अर्थात् देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 25 प्रतिशत भूमि के कटाव से प्रभावित है। हमें इस सम्बन्ध में भी ऐसे उपाय करने चाहिये जो प्रभावी हों, खेद की बात है कि सिंचाई की योजनाओं पर इतना अधिक धन व्यय किये जाने के बाद भी हमारी केवल 20 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। सिंचाई के विकास के लिये ग्रामों को अधिक बिजली दी जानी चाहिये। सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक उपज करने वाले बीजों की व्यवस्था करने से उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी।

हमारे कृषक विश्व में सबसे अधिक परिश्रम करने वाले, बुद्धिमान तथा देश-भक्त हैं। हमारे लिये शर्म की बात है कि इसके बावजूद हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। हमारे कृषि उपकरण अभी तक वैसे ही हैं जैसे शताब्दियों से प्रयोग किये जा रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ट्रैक्टरों के निर्माण की व्यवस्था की जावे। बैलों की तुलना में ट्रैक्टरों से कृषि करना सस्ता रहता है। हमें यथासम्भव अधिक ट्रैक्टरों का निर्माण करके उन्हें कृषकों को बेचना चाहिये अथवा उन्हें किराये पर देना चाहिये। जिन लोगों के पास थोड़ी भूमि है, वे अन्य कृषकों की भूमि में ट्रैक्टरों द्वारा काम करके धन कमा रहे हैं।

नलकूपों की खुदाई के लिये कृषकों को ऋण देने की बजाये सरकार को स्वयं प्रत्येक ग्राम में एक-एक नलकूप खुदवाने की व्यवस्था करनी चाहिये। जिन क्षेत्रों में नहरें नहीं हैं, उनमें नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इंगलैंड में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाता है और प्रति एकड़ 15 से 20 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। भारत में भी ऐसा किया जाना चाहिये। तब कृषक अपना महत्व अनुभव करेगा।

हरियाणा की भूमि बहुत उर्वर है और यदि हरियाणा की ओर ध्यान दिया जाये तो वह भारत का अन्न का भण्डार बन सकता है। यदि आप हरियाणा के लिये सिंचाई की व्यवस्था करें तथा पशुपालन को प्रोत्साहन दें तो यह देश के बहुत ही हित में होगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
32	1	श्री नायनार	भूमि सुधार नीति की असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
32	7	श्री यशपाल सिंह	गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	,,
32	8	,,	रासायनिक खाद और अच्छी किस्म के बीजों के वितरण सम्बन्धी नीति ।	,,
32	9	,,	राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों को अनाज देना ।	,,
32	10	,,	गन्ने के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति ।	,,
32	11	,,	चीनी और चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण ।	,,

32	12	,,	खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगे क्षेत्रिय प्रतिबन्ध को हटाने में असफलता ।	,,
32	13	,,	फसल बीमा लागू करने में असफलता ।	,,
32	16	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों पर हो रहे भारी खर्च को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
32	17	श्री भोला नाथ	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प कालीन तथा मध्यम-कालीन ऋणों की राशियां किसानों को ठीक प्रकार न दिया जाना ।	,,
32	23	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि शिक्षा की धीमी प्रगति ।	,,
32	24	,,	कृषि कालेजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
32	25	श्री यशपाल सिंह	भारतीय खाद्य निगम के कार्य संचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
32	26	,,	सघन कृषि जिला कार्यक्रम की वांछनीयता ।	,,

32	27	श्री यशपाल सिंह	लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देने की वांछनीयता ।	100 रुपया
32	28	,,	गन्ना उत्पादकों तथा चीनी मिलों में को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
32	29	,,	केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्य संचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
32	30	,,	यंत्रीकृत फार्मों के कार्य-संचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	
32	22	श्री गार्डि लिंगन गौड	पंचायत समितियों और तालुक समितियों की असफलता जो सामुदायिक विकास योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है ।	,,
32	33	,,	सहकारिता विभाग को खाद्य उत्पादन बढ़ाने की योजनायें प्रभावी तौर से लागू करने में असफलता ।	
33	34	श्री रामावतार शास्त्री	भूमि को उपजाऊ बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
33	35	,,	देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने में असफलता ।	,,

33	36	,,	खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	,,
33	37	,,	रोगों से मुक्त कृषि सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
33	38	श्री क. मि. मधुकर	प्रत्येक गांव में पौधों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
33	39	,,	अलग अलग मौसमों में उपयुक्त फसल उगाने के लिए ग्राम स्तर पर शिक्षा देने की आवश्यकता ।	,,
33	40	,,	अकाल पीड़ित क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता ।	,,
33	41	,,	छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक सरकारी योजना की आवश्यकता ।	,,
33	42	,,	ट्रैक्टर-चालकों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,

33	43	श्री क. मि. मधुकर	ग्राम स्तर पर भूमि की जांच करने तथा किसानों को सलाह देने की आवश्यकता ।	100 रुपया
33	44	श्री नायनार	भारत में कृषि उत्पादन में असफलता ।	,,
33	46	श्री रामावतार शास्त्री	पौधों के परिरक्षण की आवश्यकता ।	,,
33	47	,,	मीम-क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता ।	,,
33	48	,,	जिला स्तर पर गहन खेती की योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
33	49	,,	पौधों को टिड्डियों एवं अन्य किटाणुओं से बचाने की आवश्यकता ।	,,
33	50	,,	भूमि को उपजाऊ बनाने की आवश्यकता ।	,,
33	51	,,	कृषि फार्मों की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
33	52	,,	फलों और फल-उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
33	53	,,	गन्ने की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	,,

33	54	,,	किसानों के लिये लघु सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
33	55	श्री भोला नाथ	राजस्थान में कृषि-उत्पादन की बिक्री के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता ।	,,
33	56	,,	राजस्थान में कुएं खोदने संबंधी कार्य का अपर्याप्त प्रबन्ध ।	,,
33	57	,,	राजस्थान में भूमिगत पानी का पता लगाने के लिये परियोजना ।	,,
33	58	,,	राजस्थान में ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना की आवश्यकता ।	,,
33	73	श्री गाडि लिंगन गौड	खाद्य तथा कृषि संगठन तथा अन्य बैठकों और सम्मेलनों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में वास्तविक किसानों और कृषि विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	,,
33	74	,,	गांवों में युवक-कार्यों की योजना की असफलता ।	,,

33	75	श्री गार्डि लिंगन गौड	देश में सबसे अधिक चावल के उत्पादकों को पुरस्कार देने के प्रस्तावों संबंधी राज्य सरकारों की रिपोर्टों का उचित मूल्यांकन करने में असफलता ।	100 रुपया
34	80	श्री रामावतार शास्त्री	देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
34	85	श्री गार्डि लिंगन गौड	मशीनी फार्मों के लिये धान के पौधे बोने वाले यंत्र की खोज करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
35	90	श्री रामावतार शास्त्री	विकास खण्डों की अनुपयोगिता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
35	91	श्री नायनार	केरल में पंचायती राज का असफल होना ।	100 रुपया
35	93	श्री भोला नाथ	राजस्थान में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्यों को ठीक से नहीं चलाया जाना ।	,,
36	95	श्री रामावतार शास्त्री	देश में वनों का परिरक्षण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये,

36	96	,,	वनों का परिरक्षण करने की आवश्यकता।	100 रुपया
37	99	,,	निर्धन जनता को लाभ पहुंचाने में सहकारी समितियों की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
37	101	श्री नायनार	केरल के लोगों को कम खाद्यान्न दिया जाना।	100 रुपया
37	102	श्री रामावतार शास्त्री	खांडसारी उद्योग के विकास की आवश्यकता।	,,
37	103	,,	भारत में घोड़ों की नस्ल सुधारने की आवश्यकता।	,,
121	115	श्री रमानी	गरीब तथा मध्यम वर्ग के किसानों को नियंत्रित मूल्यों पर उर्वरक देने में असफलता।	राशि घटा कर 100 रुपया की जाये।
122	116	श्री नायनार	केरल में मछली उद्योग की सहायता करने की आवश्यकता।	100 रुपया
32	133	श्री ह० प० चटर्जी	सभी राज्यों में खाद्यान्न का समान वितरण सुनिश्चित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
32	134	,,	खाद्य उत्पादन युद्ध-स्तर पर करने के लिये सभी उपायों की खोज करने में असफलता।	,,

32	138	श्री हृ० प० चटर्जी	कार्बनिक खाद प्रयोग किये जाने तथा उर्वरकों का सोच समझ कर प्रयोग करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
32	139	,,	विदेशों से खाद्यान्न का आयात कम करने की आवश्यकता ।	,,
32	140	,,	पशुपालन तथा मुर्गीपालन में सुधार सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता ।	,,
32	141	,,	नदी घाटी परियोजनाओं के ऊंचे स्तर तथा न्यूनतम स्तर के जलाशयों में रेत न जमे यह सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय करने की आवश्यकता ताकि सिंचाई की क्षमता बनी रहे ।	,,
32	142	,,	भूमि सम्बन्धी नियमों को नवीनतम रूप देने की आवश्यकता ।	,,
33	143	,,	एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न लाने ले जाने पर से रोक हटाने की आवश्यकता ।	,,
33	144	,,	ऐसा प्रशासन समाप्त करने जिसमें अधिकारी अधिक हों ।	,,
33	145	,,	सघन खेती करने की आवश्यकता ।	,,

33	146	,,	भूमि संरक्षण के लिये उचित उपाय करने की आवश्यकता।	,,
32	151	श्री रामावतार शास्त्री	उर्वरकों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
32	152	,,	उर्वरकों में मुनाफाखोरी तथा चोर-बाजारी को प्रोत्साहित करना।	,,
32	153	,,	स्वदेशी खाद, जैसे कि गोबर की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।	,,
32	154	श्री गणेश घोष	खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता।	,,
32	155	,,	उन क्षेत्रों में जहां कानूनी रूप से राशन व्यवस्था लागू की गई है वहां राजसहा-यता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न की सप्लाई करने में हुई हानि को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान देने में असफलता ।	,,
32	156	,,	गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों को विशेषकर पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न देने में भेदभाव।	,,

32	157	श्री गणेश घोष	पश्चिम बंगाल में गैर-कांग्रेसी सरकार बन जाने के बाद पश्चिम बंगाल को उतनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई न किया जाना जितना कि आश्वासन दिया गया था।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये। ,,
32	159	श्री ह० प० चटर्जी	लघु सिचाई योजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपया
32	161	श्री रामावतार शास्त्री	उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता, जिसके कारण अधिक उत्पादन करने में कठिनाई हो रही है।	,,
32	162	,,	चोरबाजारी, खाद्यान्न की चोरी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी रोकने की आवश्यकता।	,,
32	163	श्री रा. की. अमीन	गुजरात राज्य में प्रत्येक जिले में केन्द्रीय कृषि पालिटेक्निक स्थापित किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपया
32	164	,,	देश के अनुसंधान फार्मों और किसानों के बीच समन्वय का अभाव।	,,
32	165	,,	पूरे देश में भूमि का परीक्षण और सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	,,
32	166	,,	गुजरात राज्य के भाल और नलकण्ठा क्षेत्रों में नल-कूपों का विकास करके पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

32	167	,,	सामुदायिक विकास कार्य बन्द करके सुधरे बीजों, कीटनाशी दवाइयों और उर्वरकों के लिये पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
32	168	,,	देश में कृषि शिक्षा का ढांचा बदलने की आवश्यकता ।	,,
32	169	,,	देश के प्रत्येक तालुके और खण्ड में ग्राम संस्थायें और औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
32	170	,,	उत्तर गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
32	171	,,	देश में भाण्डागारों और अन्य बैंकों का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
35	172	,,	गुजरात राज्य में मीनक्षेत्रों के विकास के लिये प्रर्याप्त धन जुटाने की आवश्यकता ।	,,
32	173	,,	गुजरात राज्य में पंचमहल और भाल नलकण्ठा में ग्रामीण-कार्य की समुचित योजनाओं का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
32	174	,,	फसल के बीमें के लिये प्रबन्ध करने में असफलता ।	,,

32	175	श्री रा. की. अमीन	देश में रुई के पर्याप्त उत्पादन के लिये प्रबन्ध न करना में असफलता।	100 रुपया
32	176	,,	सहकारी खेतों को प्रोत्साहन देने के लिये सहायता बन्द करने की आवश्यकता।	,,
32	177	,,	गुजरात-भर में ठीक प्रकार से फैली प्रशीतागार सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता।	,,
32	178	,,	कृषि उत्पादन के लिये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
32	179	,,	सिंचाई के जल का अधिकतम मात्रा में प्रयोग करने हेतु योजनायें बनाने के लिये उत्पादकों, इंजीनियरों और स्वतंत्र सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की एक सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता।	,,
32	180	,,	गुजरात राज्य को आयातित खाद्यानों का उचित भाग देने में असफलता।	,,
32	181	,,	नमक मिलें उर्वरकों की सप्लाई के बारे में बेपरवाही।	,,
33	191	श्री गणेश घोष	घी तथा खाद्य तेलों विशेषकर सरसों के तेल का अपमिश्रण के सम्बन्ध में निवारक उपाय करने के असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।

33	192	,,	राज्य में मछलीपालन उद्योग का विकास करने के लिये पश्चिम बंगाल को सहायता देने में असफलता ।	,,
37	196	,,	विदेशों को निर्यात की गयी चीनी के मूल्यों की तुलना में देश के बाजारों में भी चीनी के मूल्य निर्धारित करने सम्बंधी नीति ।	,,
37	197	,,	देश में उपभोग की जाने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि ।	,,
32	200	श्री किरूतिनन	अनाज और चीनी में आत्मनिर्भर बनने में असफलता ।	100 रुपया
32	201	,,	किसानों को पानी, उर्वरक और सस्ता ऋण देने में असफलता ।	,,
32	202	,,	मद्रास राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये अधिक धन देने में असफलता ।	,,
32	203	,,	उर्वरक के मूल्य कम करने और उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
32	204	,,	मद्रास सरकार को, वहां एक रुपया प्रति माप (मेजर) चावल देने की योजना लागू करने में हुई हानि की पूर्ति के लिये राज सहायता देने में असफलता ।	,,

32	205	श्री किरुतिनन	अधिक अन्न उगाने की नीति को प्रोत्साहन देने हेतु उर्वरकों को कम मूल्य बनाये रखने की आवश्यकता।	100 रुपया
32	206	"	फसल बीमा योजना लागू करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता।	"
32	207	"	मद्रास राज्य में बड़े बड़े तालाबों में से मिट्टी निकालने, उन्हें गहरा करने और उनकी मरम्मत करने के लिये अधिक धन देने की आवश्यकता।	"
32	208	"	मद्रास राज्य के रामानाथपुरम जिले के लिये विशेष सिंचाई योजनायें बनाने की आवश्यकता।	"
32	209	"	सामुदायिक विकास खण्डों का कार्यचालन सुधारने की आवश्यकता।	"
32	210	"	मद्रास राज्य को पर्याप्त मात्रा में चीनी न दिया जाना।	"
32	211	"	मद्रास राज्य में मतस्य-पालन उद्योग के लिये अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता।	"

32	212	,,	मद्रास राज्य के रामनाथपुरम जिले में 'लिफ्ट सिंचाई समिति' योजना लागू करने की आवश्यकता ।	,,
32	213	,,	सहकारी समितियों का कार्यचालन सुधारने की आवश्यकता ।	
32	214	श्री श्रीकान्तन नायर	भूमि–सुधार कानून लागू किये जाने की आवश्यकता ।	,,
32	215	,,	खाद्यान्न तथा चीनी में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता ।	,,
32	216	,,	एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने में असफलता ।	,,
32	217	,,	केरल को नियमित तथा सुस्थिर रूप में चावल की सप्लाई बनाये रखने की आवश्यकता ।	,,
32	218	,,	छोटी सिंचाई के सम्बन्ध में समन्वित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता ।	,,
32	219	,,	उर्वरकों के लिये पुनः राजसहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
32	220	,,	केरल में जर्सी नसल के पशुओं के लिये केन्द्रीय प्रजनन फार्म स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,

32	221	श्री श्रीकान्तन नायर	रूसी सहायता से स्थापित किये जाने वाले बड़े पैमाने के पांच फार्मों में से एक फार्म केरल में स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
32	223	श्री रा० की० अमीन	कोटा क्षेत्र में भू–सुधार के लिये उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता।	,,
32	224	श्री श्रीकान्तन नायर	खाद्य तथा कृषि संगठन/विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत केरल में एक कागज और लुग्दी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
33	259	श्री रमानी	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित तम्बाकू की खेती का लक्ष्य पूरा करने में असफलता।	,,
33	260	,,	रूई की खेती करने वालों को सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त कीट-नाशक औषधियां देने में असफलता।	,,
33	261	,,	वर्ष 1966 में चीनी–उत्पादन में कमी को रोकने में असफलता।	,,
34	262	,,	तम्बाकू की काश्त बढ़ाने के लिये तम्बाकू की काश्त करने वालों को उत्साहित करने तथा सहायता देने में असफलता।	,,

36	263	,,	कृषि श्रमिकों को अनाज की खेती के लिये सरकारी परति तथा वन भूमि देने में असफलता ।	,,
37	264	,,	न्यूनतम आवश्यक चीनी उत्पादन तथा उपभोक्ताओं को उसका वितरण बनाये रखने में असफलता ।	,,
37	265	,,	गन्ने के छोटे काश्तकारों के लिये बढ़े हुए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने में असफलता ।	,,
121	266	,,	अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं में सुधार करने हेतु राज्यों को पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	,,
121	267	,,	उन सभी क्षेत्रों में कानूनी अनौपचारिक तथा संशोधित रूप में राशन व्यवस्था लागू है तथा उचित मूल्य की दूकानों में कम मूल्य पर अच्छी किस्म का चावल सप्लाई करने में असफलता ।	,,
121	268	,,	कृषि प्रयोजन के लिये कृषकों को पर्याप्त ऋण सुविधायें देने में असफलता ।	,,
121	269	,,	सस्ते उर्वरकों का वितरण करने तथा कृषकों को उर्वरकों की सप्लाई में चोर-बाजारी रोकने में असफलता ।	,,

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री रामभद्र नायडू (तिंडिवनम) : उपाध्यक्ष महोदय इस समय हम देश के करोड़ों भूखे लोगों की समस्या पर विचार कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों से हम देश के विभिन्न भागों से भुखमरी के समाचार सुनते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें मौज नहीं उड़ानी चाहिये। हमें इस उपेक्षा के कारणों पर विचार करना चाहिये। और उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार सब से बड़ी दोषी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में देश की स्थिति को बिल्कुल खराब कर दिया है। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्तमान स्थिति के लिये सूखा ही जिम्मेदार नहीं बल्कि जल एकत्र करने की क्षमता न होना भी जिम्मेदार है। सरकार को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही सिंचाई के समुचित प्रबन्ध करने चाहिये थे। सरकार ने पहले तो इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। अब जबकि मुश्किल में हैं तो ध्यान आया है कि सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये। भारत जैसे देश में सिंचाई पर जो व्यय किया गया है वह बहुत कम है।

उर्वरक के बारे में भी सरकार ने उपेक्षा की नीति अपनायी है। भारत का प्रति एकड़ उत्पादन विश्व में लगभग सभी देशों के प्रति एकड़ उत्पादन से कम है। इसका कारण हमारे देश में खाद की कमी है। यदि हम खाद का उत्पादन बढ़ा सकें और किसानों की मांगे पूरी कर दें तो हमारे अनाज के उत्पादन में दुगनी वृद्धि हो सकती हैं। सरकार के सिंचाई तथा उर्वरक मंत्रालयों में प्राथमिकता दिये जाने पर मतभेद है। मेरे विचार में सरकार को विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिये।

मुझे खेद है कि मेरे राज्य की मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। उर्वरक की वहां बहुत आवश्यकता है। किसानों को ऊंचे दामों पर खाद लेनी पड़ती है। इससे किमतें नीचे लाने में कठिनाई होती है। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में उदारता का रवैया अपनाना चाहिये और राज्यों की अधिकाधिक सहायता करनी चाहिये। निवेली लिगनाइट निगम से वितरण का काम लेकर राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को डी० एम० के० सरकार की सही तरीके से सहायता करनी चाहिये और आश्वासन देना चाहिये कि पहले की स्थिति अब नहीं रहेगी। छोटी सिचाई योजनाओं के लिये और धन उपलब्ध किया जाना चाहिये। मद्रास सरकार ने राज्य के जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया है और अब इन से लाभ उठाने के लिये धन जुटाने में प्रयत्नशील है। वहां पर चरणवार कार्यक्रम बनाया गया है और उसके लिये 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इसमें पर्याप्त योगदान देगी। किसानों की सहायता के लिये सरकार को उसकी आवश्यकता की वस्तुओं अर्थात् बिजली, उर्वरक आदि के मूल्य नियन्त्रण में रखने चाहिये। खेतीहर मजदूरों की कमी होने के कारण भी खाद्य उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त किसानों की औजारों सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिये। किसानों की ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकें। मद्रास की राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह हानि उठाकर लोगों को

सस्ते दर पर चावल दे रही है । और केन्द्रीय सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य की किसी प्रकार भी सहायता नहीं कर सकेगी । परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि जब गेहूं के मामले में केन्द्रीय सरकार राज सहायता दे रही है तो मद्रास सरकार से इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ।

इसके पश्चात लोक सभा बुद्धवार 12 जुलाई, 1967/21 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, July 12, 1967/ Asadha 21, 1889 (Saka).